

Kumar Edutainment Presents

Current Affairs Magazine

SEP 2025

महत्वपूर्ण घटनाक्रम

- प्रधानमंत्री ने खाद्य और शाति के लिए वैश्विक एम. एस. स्वामीनाथन पुरस्कार का शुभारंभ किया
- क्या रोहिंग्या 'शरणार्थी' हैं? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सामने अहम सवाल
- प्रख्यात राजनेता शिवू सोरेन, सत्य पाल मलिक और ला गणेशन का निधन
- सोनाली मिश्रा 143 वर्षों में आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनीं
- क्या धराली में बादल फटा या हिमनद झील का फटना हुआ? अंतर जानें
- मोल्डोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का 107वाँ सदस्य बना
- संसद के मानसून सत्र में स्वीकृत प्रमुख विधेयकों पर एक नज़र
- मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता
- विकसित भारत 2047 के लिए प्रमुख घोषणाएँ एवं दृष्टिकोण
- मित्रता से मतभेद तक: बदलते भारत-अमेरिका संबंध



मनिका
विश्वकर्मा

विशेषता:

- लघु लेख
- प्रश्न बैंक
- क्विक बाइट्स
- इन्फोग्राफिक्स



मुकेश कुमार



8882388888



Kumar Edutainment



your_kumar_sir



kumarsias.com

कुमार एडुटिमेंट
सभी कॉपीराइट सुरक्षित
पता: 7 जवाहर नगर, खंडारी, आगरा, उत्तर प्रदेश
दूरभाष: 8882388888
मेल: Kumariasacademy@gmail.com
वेब: <https://kumarsias.com/index-2.html>



अखोकरण

यह पुस्तक शैक्षिक और सीखने के उद्देश्यों के लिए है। पुस्तक के लेखक (ओं) ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित देखभाल की है कि पुस्तक की सामग्री किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के किसी भी मौजूदा कॉपीराइट या अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है। घटना में लेखक किसी भी स्रोत को ट्रैक करने में असमर्थ है / और यदि कोई कॉपीराइट अनजाने में उल्लंघन किया गया है, तो कृपया प्रकाशक को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए लिखित रूप में सूचित करें।

इस प्रकाशन में त्रुटियों या चूक से बचने का हर संभव प्रयास किया गया है। इसके बावजूद, त्रुटियों में कमी हो सकती है। विष्यात किसी भी गलती, त्रुटि या विसंगति को हमारे ध्यान में लाया जा सकता है जिसे अगले संस्करण में ध्यान रखा जाएगा। यह अधिसूचित किया गया है कि प्रकाशक या लेखक या विक्रेता किसी भी प्रकार के, किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार की किसी भी क्षति या कार्रवाई के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। यह सुझाव दिया जाता है कि किसी भी सदेह से बचने के लिए पाठक को मूल प्रकाशन या सूचनाओं के साथ प्रकाशन के सभी तथ्यों, कानून और सामग्री को पार करना चाहिए।

बाइंडिंग मिस्टेक, मिस्प्रिंट्स या गुम पृष्ठों आदि के लिए, प्रकाशक की देनदारी समान संस्करण द्वारा खरीद के सात दिनों के भीतर बदलने तक सीमित है। इस संबंध में सभी खर्च क्रेता द्वारा वहन किए जाने हैं।

सभी कॉपीराइट सुरक्षित

इस पुस्तक का कोई भी भाग किसी भी रूप में या किसी भी तरह से (ग्राफिक, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग, टेपिंग, या सूचना पुनर्पाप्ति प्रणाली सहित) या किसी डिस्क, टेप, छिद्रित मीडिया या अन्य सूचना भंडारण पर पुनः प्रस्तुत या कॉपी आदि, प्रकाशकों की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। इस शर्त का उल्लंघन कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है।

लेखक प्रतिनिधित्व करता है और वारंट करता है कि लेखक ही संपूर्ण रूप से सभी अधिकारों का एकमात्र मालिक है, कि कॉपीराइट के कार्यों के ऐसे अंशों को छोड़कर कार्य मूल है क्योंकि कॉपीराइट स्वामी की अनुमति के साथ शामिल किया जा सकता है, जिससे कार्य किसी भी व्यक्ति के निजता के अधिकार का हनन या उल्लंघन नहीं करता है और साथ ही यह किसी भी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट या दूसरों के किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।



8882388888



Kumar Edutainment



your_kumar_sir



kumarsias.com



Kumar Edutainment Presents

CURRENT AFFAIRS MAGAZINE

प्रिय अभ्यर्थी,

मैं पूरे संस्थान की ओर से आपका स्वागत करता हूं और हम में आपकी रुचि दिखाने के लिए धन्यवाद।

वर्षों से हम युवा छात्र एवं छात्राओं को शिक्षित कर रहे हैं जिन्होंने हमारे साथ जुड़ कर एक जिम्मेदार नागरिकों और कॉरपोरेट्स प्रमुख में अपना परिवर्तन अनुभव किया। हमारे साथ जुड़कर, आप एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कर रहे हैं जो परिवर्तनकारी है - अकादमिक, सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से। "उत्कृष्टता और मूल्य" हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो संस्थान की प्रत्येक गतिविधि में परिलक्षित होते हैं।



हमारी हैंडबुक कई प्रतियोगी और सरकारी परीक्षाओं में बड़ी भूमिका निभाती है। यह आपकी सफलता के अवसर को बनाने या तोड़ने की शक्ति रखता है। इसलिए, उम्मीदवारों को करेंट अफेयर्स को अच्छी तरह और स्मार्ट तरीके से कवर करना चाहिए। विभिन्न परीक्षाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमारी हैंडबुक को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। दिए गए करेंट अफेयर्स की प्रस्तुति की योजना सावधानीपूर्वक बनाई गई है। इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि यह पाठकों के जेहन में लंबे समय तक बना रहे।

हमारा मिशन एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है जिसमें प्रत्येक छात्र हमेशा बदलते, वैश्विक समुदाय के कुशल, उत्पादक सदस्य बनने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त करेगा। हमारे संकाय व्यक्तियों का एक बहुत ही समर्पित समूह है जो हमारे छात्रों के लिए सर्वोत्तम संभव निर्देश प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखता है।

एक बार फिर, साझा सिद्धांतों एवं मूल्यों के हमारे समुदाय में आपका स्वागत है। आने वाले वर्षों में आपके सुखद, स्वस्थ और फलदायी होने की कामना करते हैं।

संस्थान में आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।

मुकेश कुमार



8882388888



Kumar Edutainment



your_kumar_sir



kumarsias.com



समाचार श्रेयः
बीबीसी/
रॉयटर्स/
अलजजीरा/
पीआईबी/
पीटीआई/
बिजनेस स्टैंडर्ड/
द हिंदू/
इंडियन एक्सप्रेस/
टाइम्स ऑफ इंडिया/
इकोनॉमिक टाइम्स/
बिजनेस लाइन/
इंडिया टुडे/
मनीकंट्रोल एवं अन्य
सभी प्रमुख समाचार
पत्र



Kumar Edutainment Presents
**CURRENT AFFAIRS
MAGAZINE**

इस संस्करण में शामिल हैं

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	नियुक्तियाँ	1
2	राजतन्त्र एवं शासन	14
3	अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं घटनाएँ	20
4	अर्थव्यवस्था एवं व्यापार	32
5	रक्षा एवं सुरक्षा	37
6	सामाजिक मुद्दे एवं योजनाएँ	41
7	पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	45
8	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	49
9	संस्कृति एवं इतिहास	53
10	खेल-कूद	57
11	निधन	61
12	परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण दिन	66
13	पुस्तकें एवं लेखक	67
14	अभ्यास हेतु प्रश्न बैंक	68
15	किविक बाइट्स	94
16	इन्फोग्राफिक्स	97

हमारे बारे में:

संस्करण: सितम्बर 2025

संपादक का नाम: कुमार एडुटिमेंट

सलाहकार का नाम: मुकेश कुमार

पता: 7 जवाहर नगर, खंडारी, आगरा, उत्तर प्रदेश

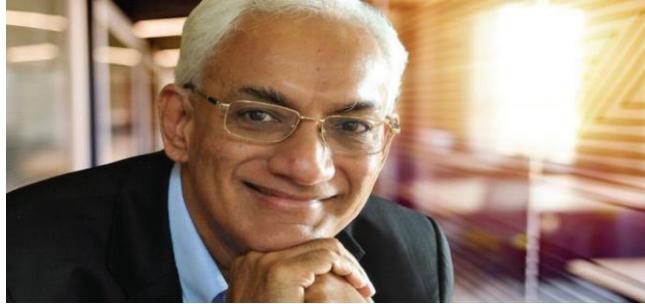
दूरभाष: 8882388888

मेल: Kumariasacademy@gmail.com

वेब: <https://kumarsias.com/index-2.html>

नियुक्तियाँ

श्रीनिवासन के. स्वामी AAAI के अध्यक्ष निर्वाचित (2025-26)



भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ (AAAI) के 2025-26 के पदाधिकारियों के चुनाव में, आर. के. स्वामी लिमिटेड के कार्यकारी समूह अध्यक्ष, श्रीनिवासन के. स्वामी को अध्यक्ष चुना गया है। यह इस पद पर उनका चौथा कार्यकाल है, इससे पहले वे 2004 से 2007 तक AAAI के अध्यक्ष रह चुके हैं।

उपाध्यक्ष: जयदीप गांधी।

अन्य बोर्ड सदस्य: अनुप्रिया आचार्य, सैम बलसारा, मोहित जोशी, अनुषा शेट्टी, शशि सिन्हा, विक्रम सखुजा, परितोष श्रीवास्तव।

निर्वाचित अध्यक्ष: प्रशांत कुमार।

AAAI

- पूर्ण रूप: भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ।
- स्थापना: 1945।
- स्वरूप: भारत में विज्ञापन एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था।
- भूमिका: उद्योग मानकों को बढ़ावा देना, सहयोग को बढ़ावा देना और विज्ञापन एजेंसियों के हितों की रक्षा करना।
- सदस्यता: भारत भर की अग्रणी राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय विज्ञापन एजेंसियाँ।

श्वेता मेनन AMMA की पहली महिला अध्यक्ष बनीं



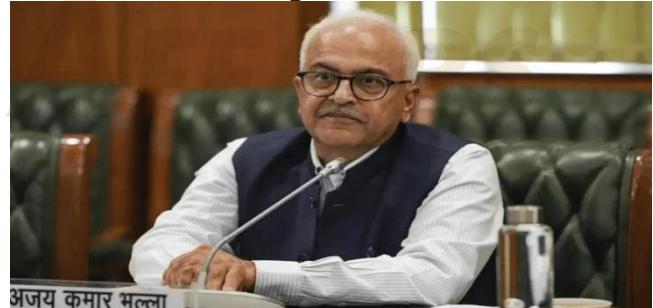
अभिनेत्री श्वेता मेनन को मलयालम फिल्म कलाकार संघ (AMMA) की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। उनकी नियुक्ति अभिनेता मोहनलाल द्वारा अगस्त 2024 में AMMA अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद हुई है। न्यायमूर्ति के. हेमा समिति की रिपोर्ट में मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न के आरोपों का उल्लेख किया गया था। 235 पृष्ठों की रिपोर्ट (संपादित संस्करण

जारी) ने मॉलीवुड में महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण का पर्दाफाश किया है, जिसमें कहा गया है कि इस उद्योग को 10-15 पुरुष निर्माताओं, निर्देशकों और अभिनेताओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मोहनलाल के इस्तीफे के बाद, 17 सदस्यीय कार्यकारी समिति ने भी इस्तीफा दे दिया। केरल सरकार ने महिला अभिनेताओं के सामने आने वाली समस्याओं की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल (SIT) का गठन किया था। इससे पहले जनवरी 2025 में, अभिनेता उन्नी मुकुंदन ने मानसिक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए AMMA कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। श्वेता मेनन की नियुक्ति के साथ, एएमएमए में महिलाओं की सुरक्षा और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों पर केंद्रित सुधारों की उम्मीद है।

मलयालम मूर्वी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (एएमएमए)

- स्थापना: 1994
- मुख्यालय: कोच्चि, केरल
- मलयालम फिल्म उद्योग (मॉलीवुड) के अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है।
- मॉलीवुड - केरल स्थित मलयालम फिल्म उद्योग।
- वृमेन इन सिनेमा कलेक्टिव (डब्ल्यूसीसी) - मलयालम सिनेमा में लैंगिक न्याय के लिए लड़ने हेतु 2017 में गठित एक मंच।

राष्ट्रपति ने मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया



राष्ट्रपति द्वारा प्रदीपदी मुर्म ने मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त, नागालैंड के राज्यपाल के कार्यों का भी निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है। यह नियुक्ति नागालैंड के राज्यपाल ला. गणेशन के निधन के बाद हुई है।

- भारत की राष्ट्रपति: द्वारा प्रदीपदी मुर्म (15वीं राष्ट्रपति, 25 जुलाई 2022 को पदभार ग्रहण किया)।
- राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद: अनुच्छेद 155 - किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद: अनुच्छेद 156 - राष्ट्रपति के प्रसादपर्यात, सामान्यतः 5 वर्षों के लिए, पद धारण करता है।

- नागलैंड की राजधानी: कोहिमा।
- मणिपुर की राजधानी: इंफाल।
- महत्वपूर्ण सूचना: नागलैंड को 1 दिसंबर 1963 को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ (भारत का 16वाँ राज्य)।

रवि नारायणन एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट के सीईओ नियुक्त



एक प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट (एसएमआईसीसी) ने रवि नारायणन को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, जो 28 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट ₹60,000 करोड़ से अधिक की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों (एयूएम) का प्रबंधन करता है और पूरे भारत में 30 लाख से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है।

पेशेवर पृष्ठभूमि

रवि नारायणन को खुदरा और शाखा वितरण क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है, उन्होंने एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक में वरिष्ठ नेतृत्वकारी पदों पर कार्य किया है। उन्होंने एक्सिस सिक्योरिटीज और एक्सिस म्यूचुअल फंड के बोर्ड में भी कार्य किया है।

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड:

- प्रकार: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)
- स्वामित्व: सुमित्रोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप (एसएमएफजी), जापान की सहायक कंपनी
- पूर्व नाम: फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (2021 में एसएमएफजी अधिग्रहण के बाद पुनः ब्रांडेड)
- स्थापना: 2007
- मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
- उत्पाद और सेवाएँ: व्यक्तिगत ऋण, व्यावसायिक ऋण, दोपहिया वाहन ऋण, संपत्ति पर ऋण, एसएमई ऋण, ग्रामीण वित्तपोषण और डिजिटल ऋण समाधान
- अध्यक्ष: राजीव कन्नन

संदीप आर्य भूटान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त

1994 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी, संदीप आर्य को भूटान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। यह घोषणा विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा की गई। वह वर्तमान में वियतनाम में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं और जल्द ही अपना नया पदभार ग्रहण करने की उम्मीद है।



पूर्व राजनयिक कार्यभार

अक्टूबर 2022 में वियतनाम में राजदूत नियुक्त।

पदों पर कार्य किया:

- अतिरिक्त सचिव (निरस्तीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले), विदेश मंत्रालय (2019-2022)।
- संयुक्त सचिव (यूरोप पश्चिम/AD), विदेश मंत्रालय (2019-2022)।
- तंजानिया में उच्चायुक्त और पूर्वी अफ्रीकी समुदाय के प्रतिनिधि (2015-2019)।

भारतीय दूतावासों में सेवा की:

- नीदरलैंड
- रूस
- यूक्रेन
- 1994 से 2015 के बीच नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय मुख्यालय में विभिन्न पदों पर भी रहे।

भारत-वियतनाम संबंध

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान 2016 में भारत-वियतनाम संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में उत्तर किया गया। शुरुआत में, भारत के उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम दोनों के साथ वाणिज्य दूतावास स्तर के संबंध थे, जिसके बाद 7 जनवरी 1972 को पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए। वर्तमान में, यह संबंध प्रधानमंत्री मोदी और वियतनाम के पूर्व प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक के बीच सहमत "शांति, समृद्धि और लोगों के लिए संयुक्त दृष्टिकोण" द्वारा निर्देशित है।

भूटान

- राजधानी: थिम्पू
- मुद्राएँ: भूटानी नुलट्रम, भारतीय रुपया
- आधिकारिक भाषा: जोंगखा
- प्रधानमंत्री: शेरिंग तोबगे
- राजा: जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक

पीबी बालाजी जगुआर लैंड रोवर के पहले भारतीय सीईओ बने

पीबी बालाजी को जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है - इस प्रतिष्ठित ब्रिटिश ऑटोमोबाइल ब्रांड का नेतृत्व करने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं।

- प्रभावी तिथि: वे नवंबर 2025 में पदभार ग्रहण करेंगे।

- पूर्ववर्ती: एडियन मार्डल, जो जेएलआर में 35 वर्षों के कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसमें 3 वर्ष सीईओ के रूप में भी शामिल हैं।
- जेएलआर की मूल कंपनी टाटा मोटर्स द्वारा 4 अगस्त, 2025 को हुई बोर्ड बैठक के बाद एक नियामक फाइलिंग में इसकी घोषणा की गई।



पीबी बालाजी का परिचय:

वर्तमान में टाटा मोटर्स समूह के ग्रुप सीएफओ के रूप में कार्यरत (नवंबर 2017 से)

जगुआर लैंड रोवर लिमिटेड (जेएलआर):

- मुख्यालय: व्हिटली, कोवेंट्री, इंग्लैंड
- स्थापना: 2008 में एक संयुक्त इकाई के रूप में (हालाँकि जगुआर और लैंड रोवर का इतिहास पुराना है)
- मूल कंपनी: टाटा मोटर्स लिमिटेड (टाटा समूह, भारत का एक हिस्सा)
- टाटा मोटर्स ने 2008 में फोर्ड से जेएलआर का अधिग्रहण किया था

राजीव आनंद इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त



एक्सिस बैंक के पूर्व उप-प्रबंध निदेशक, राजीव आनंद को इंडसइंड बैंक का नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और निदेशक मंडल ने 4 अगस्त, 2025 को मंजूरी दी थी। कार्यकाल: उनका कार्यकाल तीन वर्षों का होगा, 25 अगस्त, 2025 से 24 अगस्त, 2028 तक।

नई नियुक्ति का कारण

यह नई नियुक्ति इंडसइंड बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ सुमंत कठपालिया के इस्तीफे के बाद हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ₹1,960 करोड़ की लेखा चूक के बाद कठपालिया ने पद छोड़ दिया। आरबीआई ने पहले कार्यकारी समिति का कार्यकाल

नए सीईओ की मंजूरी मिलने तक 28 जुलाई, 2025 तक बढ़ा दिया था।

इंडसइंड बैंक:

- स्थापना: अप्रैल 1994
- मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
- प्रवर्तक: हिंदुजा समूह
- प्रकार: निजी क्षेत्र का बैंक

उपलब्धियाँ

- ईएसजी के लिए पीएमआई इंडिया पुरस्कार और एशियामनी पुरस्कार जीते
- 2019 में भारत फाइनैशियल इक्लूजन लिमिटेड का अधिग्रहण किया
- आरबीआई के साथ किसानों के लिए सीबीडीसी पायलट लॉन्च किया

प्रत्यय अमृत बिहार के नए मुख्य सचिव नियुक्त



बिहार सरकार ने वरिष्ठ आईएस अधिकारी प्रत्यय अमृत को 1 सितंबर 2025 से बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वह अमृत लाल मीणा का स्थान लेंगे, जो 31 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव बी राजिंदर द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई।

समय से पूर्व नियुक्ति का कारण

इस वर्ष के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए, नियुक्ति की अधिसूचना एक महीने पहले ही जारी कर दी गई थी।

राष्ट्रीय सम्मान

2021 में, वे उस वर्ष लोक प्रशासन में उल्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार (व्यक्तिगत श्रेणी) से सम्मानित होने वाले एकमात्र आईएस अधिकारी बने।

बिहार:

- राजधानी: पटना
- मुख्यमंत्री: नीतीश कुमार
- राज्यपाल: आरिफ मोहम्मद खान

खालिद जमील भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच नियुक्त



अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने खालिद जमील को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त करने की घोषणा की है। वह स्पेनिश कोच मनोलो मार्केज़ की जगह ले गए, जिन्होंने लगातार निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पद छोड़ दिया था। जमील एक दशक से भी ज़्यादा समय में सीनियर राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले सावियो मेडेइरा 2011 से 2012 तक भारतीय मुख्य कोच रहे थे।

खालिद जमील का करियर और उपलब्धियाँ

भारत के लिए 40 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पूर्व मिडफील्डर जमील ने 2009 में मुंबई एफसी के साथ अपने कोचिंग करियर की शुरुआत की। उन्हें 2020-21 में नॉर्थईस्ट यूनाइटेड को इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के प्ले-ऑफ में पहुँचाने के लिए पहचान मिली, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र भारतीय कोच बन गए। 2024-25 के आईएसएल सीज़न में, उन्होंने जमशेदपुर एफसी के मुख्य कोच के रूप में कार्य किया और पाँचवें स्थान पर रहे। उन्होंने ईस्ट बंगाल और मोहन बागान जैसे प्रतिष्ठित भारतीय क्लबों का भी प्रबंधन किया है।

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ):

- स्थापना: 23 जून 1937
- मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत
- फीफा से संबद्ध: 1948 से
- एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एफसी) से संबद्ध: 1954 से
- भारत में फुटबॉल की शासी निकाय
- वर्तमान अध्यक्ष: कल्याण चौबे
- वर्तमान महासचिव: शाजी प्रभाकरन

शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव नियुक्त



1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, आईएस अधिकारी शशि प्रकाश गोयल ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। राज्य सरकार द्वारा उनकी

नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा की गई और गोयल ने मनोज कुमार सिंह का स्थान लिया, जो 31 जुलाई, 2025 को सेवानिवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश:

- राजधानी: लखनऊ
- राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल
- मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ
- गठन: 24 जनवरी, 1950 (संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश में परिवर्तित)
- सीमाएँ: उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड
- अंतर्राष्ट्रीय सीमा: नेपाल

सोनाली मिश्रा 143 वर्षों में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनीं



मध्य प्रदेश के डर की 1983 बैच की आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) का महानिदेशक (डीजी) नियुक्त किया गया है। इस प्रकार, वह बल के 143 वर्षों के इतिहास में इस बल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं। उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है और वह 31 अक्टूबर 2026 को अपनी सेवानिवृत्ति तक इस पद पर कार्यरत रहेंगी। उनके पास विभिन्न कानून प्रवर्तन भूमिकाओं में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है, उन्होंने निम्नलिखित पदों पर कार्य किया है:

- सीबीआई, बीएसएफ
- कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन
- पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में एडीजी और मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी, भोपाल में निदेशक के रूप में।

उन्हें इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है:

- विशेष सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक
- उत्कृष्ट सेवा के लिए पुर्विस पदक

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) - मुख्य तथ्य

- स्थापना: 1957 (आरपीएफ अधिनियम, 1957 द्वारा); 1985 में वैधानिक बल बना
- शासी मंत्रालय: रेल मंत्रालय, भारत सरकार
- बल की प्रकृति: रेल मंत्रालय के अधीन संघ का सशस्त्र बल
- प्राथमिक उद्देश्य: रेलवे संपत्ति की सुरक्षा, यात्री सुरक्षा और अपराध रोकथाम
- मुख्यालय: रेल भवन, नई दिल्ली

JioStar की डिजिटल CEO किरण मणि, IAMAI की डिजिटल मनोरंजन समिति की अध्यक्ष होंगी



इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) ने JioStar की CEO (डिजिटल) किरण मणि को डिजिटल मनोरंजन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है।

सह-अध्यक्ष: दीपित पुरकायथ, सह-संस्थापक और CEO, Inshorts

किरण मणि के बारे में:

वर्तमान में भारत के सबसे बड़े डिजिटल मनोरंजन प्लेटफॉर्म में से एक, JioHotstar की प्रमुख हैं। IAMAI की गवर्निंग काउंसिल की सदस्य हैं। IAMAI की डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर (D2C) समिति की पूर्व सह-अध्यक्ष हैं। प्रौद्योगिकी, सामग्री और उपभोक्ता व्यवहार के क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव रखती हैं।

IAMAI डिजिटल मनोरंजन समिति के बारे में:

एक प्रमुख उद्योग निकाय जो बढ़ावा दे रहा है:

- नीतिगत संवाद
- उद्योग सहयोग

नियुक्ति की वकालत:

- OTT प्लेटफॉर्म
- सामग्री निर्माता
- डिजिटल-प्रथम मीडिया कंपनियाँ

सहकारी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी इफको ने केजे पटेल को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया, अवस्थी की जगह ली।



सहकारी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी इफको ने पूर्व प्रमुख यू एस अवस्थी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद के जे पटेल को अपना नया प्रबंध निदेशक (एमडी) नियुक्त किया है।

के जे पटेल के बारे में:

उर्वरक और सहकारी क्षेत्रों में व्यापक अनुभव रखते हैं। इनसे इफको के नवाचार, किसान सशक्तिकरण और वैश्विक उल्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है।

डॉ. उदय शंकर अवस्थी की विरासत:

- 1993 से (32 वर्षों से अधिक) इफको के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत
- इफको को दुनिया की अग्रणी उर्वरक सहकारी कंपनी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नियुक्ति की विवरण:

- अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यमों की स्थापना
- नैनो उर्वरकों का शुभारंभ
- इफको को एक वैश्विक सहकारी केंद्र में बदलना

लेफिनेंट जनरल पुष्टेंद्र सिंह अगले उप-सेना प्रमुख बने



भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट के अधिकारी, लेफिनेंट जनरल पुष्टेंद्र सिंह को उप-सेना प्रमुख (VCOAS) नियुक्त किया गया है।

- नियुक्ति प्रभावी तिथि: 1 अगस्त, 2025
- पूर्ववर्ती: लेफिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि (1 जुलाई, 2024 को पदभार ग्रहण)

लेफिनेंट जनरल पुष्टेंद्र सिंह के करियर की मुख्य उपलब्धियाँ:

- सेवा अवधि: 35 वर्षों से अधिक समर्पित सेवा
- कमीशन प्राप्त: 1987 में 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस

प्रमुख अभियानों में भाग लिया:

- ऑपरेशन पवन
- ऑपरेशन मेघदूत
- ऑपरेशन रक्षक
- ऑपरेशन ऑर्किड

अंतर्राष्ट्रीय अनुभव:

- लेबनान और श्रीलंका में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन

पुरस्कार और सम्मान:

- अति विशेष सेवा पदक (AVSM)
- सेना पदक (SM) - दो बार प्रदान किया गया

भारतीय मूल के तकनीकी विशेषज्ञ निखिल रविशंकर एयर न्यूज़ीलैंड के नए सीईओ बनेंगे।

एयर न्यूज़ीलैंड ने भारतीय मूल के निखिल रविशंकर को अपना अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है।

नियुक्ति विवरणः

- प्रभावी तिथि: 20 अक्टूबर, 2025 को कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- पूर्ववर्ती: ग्रेग फ़ोरेन, जिन्होंने मार्च 2025 में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी।

**पेशेवर पृष्ठभूमि:**

वर्तमान भूमिका: एयर न्यूजीलैंड के मुख्य डिजिटल अधिकारी।
एयर न्यूजीलैंड में कार्यकाल: लगभग 5 वर्ष।

प्रमुख योगदानः

- डिजिटल बुनियादी ढाँचे में प्रमुख प्रगति का नेतृत्व किया।
- ग्राहक अनुभव और लॉयल्टी सिस्टम को बेहतर बनाया।

अनंत अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के कार्यकारी निदेशक नियुक्त

मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों ने कंपनी के कार्यकारी निदेशक के रूप में अनंत अंबानी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

- बोर्ड का निर्णय: आरआईएल के निदेशक मंडल ने शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन, नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
- पूर्व भूमिका: वह इससे पहले आरआईएल में गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे।
- शैक्षिक पृष्ठभूमि: अनंत अंबानी ब्राउन यूनिवर्सिटी, अमेरिका से स्नातक है।

बोर्ड के अन्य पदः

- जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड - मई 2022 से बोर्ड सदस्य
- रिलायंस फाउंडेशन - सितंबर 2022 से बोर्ड सदस्य
- रिलायंस न्यू एनर्जी और रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी - जून 2021 से बोर्ड सदस्य

एसीसी ने आईपीएस संजय सिंघल को सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में मंजूरी दी



केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल के विशेष महानिदेशक संजय सिंघल को सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का नया प्रमुख नियुक्त किया है।

- नियुक्ति: संजय सिंघल, उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी।
- वर्तमान पद: सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के विशेष महानिदेशक (एसडीजी) के रूप में कार्यरत।
- प्रभावी तिथि: 1 सितंबर, 2025 को कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- कार्यकाल: 31 दिसंबर, 2028 को सेवानिवृत्ति तक या अगले आदेशों तक - जो भी पहले हो, सेवारत रहेंगे।
- पूर्ववर्ती: अमृत मोहन प्रसाद का स्थान लेंगे, जो 31 अगस्त, 2025 को सेवानिवृत्त होंगे।
- नियुक्ति प्राधिकारी: कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा नियुक्ति को मंजूरी दी गई।
- अनुशंसा करने वाला मंत्रालय: यह प्रस्ताव गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
- एसएसबी की भूमिका: गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जो नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार है।

प्रॉफेटर एंड गैंबल ने भारतीय मूल के शैलेश जेजुरिकर को सीईओ नियुक्त किया



प्रॉफेटर एंड गैंबल कंपनी ने अपने लंबे समय से कार्यरत कार्यकारी शैलेश जेजुरिकर को कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है।

नियुक्ति विवरणः

- पद: पी एंड जी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)
- प्रभावी तिथि: 1 जनवरी, 2026
- पूर्ववर्ती: जॉन मोलर

- वर्तमान भूमिका: मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ)
- संदर्भ और महत्व:**
- अमेरिकी बाजार में व्यापार युद्ध और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच कार्यभार संभाला
- पी एंड जी ने हाल ही में टैरिफ और मांग में उत्तर-चढ़ाव के कारण बिक्री और लाभ के दृष्टिकोण में कटौती की।
- प्रमुख अमेरिकी कंपनियों का नेतृत्व करने वाले भारतीय मूल के सीईओ की बढ़ती सूची का हिस्सा कंपनियाँ, जिनमें शामिल हैं:
- सुंदर पिचाई (गूगल)
- सत्य नडेला (माइक्रोसॉफ्ट)
- शांतनु नारायण (एडोब)
- अरविंद कृष्णा (आईबीएम)
- नील मोहन (यूट्यूब)
- लीना नायर (यूनिलिवर)

प्रोफेसर उमा कांजीलाल इश्गू की पहली महिला कुलपति नियुक्त

उमा कांजीलाल को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इश्गू) की स्थापना के चार दशक बाद, विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है।

ओडीएल में अनुभव:

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) प्रणाली में 36+ वर्षों का अनुभव।



इश्गू में पूर्व भूमिकाएँ:

- इश्गू के कार्यवाहक कुलपति (जुलाई 2024 तक)
- प्रति कुलपति (मार्च 2021 - जुलाई 2024)

डिजिटल शिक्षा में राष्ट्रीय भूमिका:

- राष्ट्रीय समन्वयक:
- स्वर्य (ऑनलाइन शिक्षा मंच)
- स्वर्य प्रभा (शैक्षिक टीवी चैनल)



"मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है !
लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता !!

YORKSHIRE DAY



1 August

Importance
To mark the anniversary of the Battle of Minden and the emancipation of slaves.

Motto
To promote the historic English county of Yorkshire.

Founded By
Yorkshire Ridings Society.

History Behind
This Day is to remember and celebrate the largest county in the UK, Yorkshire.
Originating as a military holiday, it includes the emancipation of slaves in 1834, and some protests about losing Yorkshire's cultural identity.

Inception: 1975

HIROSHIMA DAY



6 August

Importance
To mark the anniversary of the atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki by the United States in 1945.

History Behind
During World War II on 6 August, 1945, US dropped an atomic bomb on the city of Hiroshima in Japan by an American B-29 bomber.
The 9000-pound Uranium-235 bomb was loaded on B-29 bomber named as "Enola Gay".
This nuclear bomb was named as "Little Boy".
The explosion wiped out around 90% of the city and around 80,000 people were killed and more than 35,000 people were injured.

Note
This day serves as a day of remembrance and as a focus for anti-war and anti-nuclear discussions and demonstrations.

Edition: 80th

राजतन्त्र एवं शासन

खान एवं खनिज (संशोधन) विधेयक, 2025 संसद द्वारा पारित

संसद ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 पारित कर दिया है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन को बढ़ावा देना, सतत खनन को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है।

मुख्य प्रावधान

यह विधेयक सरकार को एक्सचेंजों के माध्यम से खनिज व्यापार को सुगम बनाने, पर्यावरणीय खतरों को कम करने के लिए खनिज भंडारों की बिक्री की अनुमति देने और गहरे खनिजों के निष्कर्षण को बढ़ावा देने का अधिकार देता है। यह राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET) का विस्तार राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट (NMEDT) में भी करता है और रॉयलटी अंशदान को 2% से बढ़ाकर 3% करता है। मौजूदा पट्टों में नए खनिजों को शामिल करने और रणनीतिक खनिजों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के प्रावधान भी किए गए हैं।

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM)

NCMM के तहत, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, एलईडी, एयरोस्पेस और मशीनों जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण 24 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है। उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, भारत तटीय और अपतटीय दोनों तरह के अन्वेषण को बढ़ावा दे रहा है। अंडमान सागर में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल सहित अपतटीय खनिज ब्लॉकों की पहली नीलामी नवंबर 2024 में आयोजित की गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

भारत अर्जेंटीना, जाम्बिया, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, ज़िम्बाब्वे, मोज़ाम्बिक, मलावी और कोट डी आइवर जैसे देशों के साथ समझौतों के माध्यम से विदेशों में भी महत्वपूर्ण खनिजों की खोज कर रहा है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियों के बीच स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जैसे संगठनों के साथ भी साझेदारी की गई है।

महत्व

केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि 2014 से पहले, महत्वपूर्ण खनिजों की बड़े पैमाने पर उपेक्षा की जाती थी, जिससे भारत आयात पर निर्भर रहता था। उन्होंने कहा कि तब से हुए सुधारों ने कोयले के आयात को कम किया है और खनन क्षेत्र में पारदर्शिता में सुधार किया है। इस विधेयक के पारित होने से महत्वपूर्ण खनिजों में भारत की आत्मनिर्भरता मजबूत होने, संसाधन सुरक्षा सुनिश्चित करने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार खनन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

सरकार ई-स्पोर्ट्स को विनियमित करेगी और ऑनलाइन मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाएगी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य भारत के तेज़ी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करना और पैसे पर आधारित ऑनलाइन गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

असली पैसे वाले खेलों पर प्रतिबंध (कौशल या अवसर की परवाह किए बिना)। ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के लिए विज्ञापनों पर प्रतिबंध। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को संबंधित लेनदेन करने से रोका गया।

- दंड: उल्लंघन करने वालों के लिए 3 साल तक की कैद और जुर्माना।
- फ्री-टू-प्ले और सब्सक्रिप्शन-आधारित गेम्स की अनुमति है, लेकिन पैसे पर दांव लगाने की अनुमति नहीं है।

उद्योग पर प्रभाव

- ड्रीम11, गेम्स24x7, विंजो, गेम्सक्राप्ट, 99गेम्स, खेलोफैटेसी, माई11सर्कल जैसे प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म अस्तित्व के संकट का सामना कर रहे हैं।
- भारत का ऑनलाइन गेमिंग बाज़ार, जो वर्तमान में 3.7 अरब डॉलर का है, 2029 तक बढ़कर 9.1 अरब डॉलर होने का अनुमान है, लेकिन इसका 86% राजस्व रियल-मनी फ़ॉर्मेट से आता है।
- यह क्षेत्र सालाना ₹25,000 करोड़ से ज्यादा कर उत्पन्न करता है और 1 लाख से ज्यादा रोज़गार पैदा करता है।

विपक्ष और चिंताएँ

ऑल इंडिया गेमिंग फ़ेडरेशन (AIGF) ने चेतावनी दी है कि पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से:

करोड़ों गेमर्स अवैध विदेशी ऑपरेटरों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। कर राजस्व का नुकसान हो सकता है (अनुमानित 4 अरब डॉलर GST सालाना)। अनुच्छेद 14 और 19 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। उद्योग के जानकारों को नौकरियों के नुकसान, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (2021-22 में 2 अरब डॉलर से ज्यादा) में गिरावट और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के कमज़ोर होने का डर है।

संदर्भ और पृष्ठभूमि

सरकार ने पहले 28% GST (2023) और जीत पर 30% कर (वित्त वर्ष 2024-25) लगाया था। भारतीय न्याय संहिता (2023) ने अनधिकृत सट्टेबाजी को अपराध घोषित करते हुए 7 साल तक की जेल की सज़ा का प्रावधान किया है। 2022 से अब तक 1,400 से ज्यादा अवैध जुआ साइटों को ब्लॉक किया जा चुका है। यह कदम कर-और-विनियमन से हटकर निषेध-और-प्रवर्तन के दृष्टिकोण की ओर ले जाता है।

निष्कर्ष

यह विधेयक धन-आधारित गेमिंग पर अंकुश लगाने का प्रयास करता है, लेकिन उद्योग जगत का तर्क है कि प्रगतिशील विनियमन (कौशल बनाम संयोग में अंतर करना, उपयोगकर्ता सुरक्षा



सुनिश्चित करना और राजस्व की सुरक्षा) पूर्ण प्रतिबंध से बेहतर विकल्प है।

जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2025 लोकसभा में पेश

छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करके जीवन और व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 लोकसभा में पेश किया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह विधेयक पेश किया और इसे एक प्रवर समिति को भेज दिया, जो संसद के अगले सत्र में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

पृष्ठभूमि

इससे पहले, जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 ने 19 मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त कर दिया था। 2025 का विधेयक इन सुधारों को 10 मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत 16 केंद्रीय अधिनियमों तक विस्तारित करता है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

अपराधमुक्ति के उपाय:

10 अधिनियमों के अंतर्गत 76 अपराधों के लिए परामर्श/वेतावनी। मामूली/तकनीकी चूक के लिए कारावास के स्थान पर आर्थिक दंड या चेतावनी। बार-बार अपराध करने पर जुमनि में वृद्धि के साथ आनुपातिक दंड। प्रशासनिक अधिकारियों को दंड लगाने का अधिकार, न्यायिक बोझ कम करना।

➤ हर तीन साल में दंड में स्वतः: 10% की वृद्धि।

शामिल अधिनियम (और अधिक गैर-अपराधीकरण प्रस्तावित):

- चाय अधिनियम, 1953
- विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009
- मोटर वाहन अधिनियम, 1988
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940

विशिष्ट प्रावधानों में संशोधन:

- 3 प्रावधान - कारावास/जुर्माना हटाया गया
- 33 प्रावधान - जुर्माना हटाया गया
- 14 प्रावधान - कारावास हटाया गया, जुर्माना बरकरार रखा गया
- 4 प्रावधान - कारावास हटाया गया, जुर्माना बढ़ाया गया
- 2 नियम - कारावास कम किया गया, जुर्माना बढ़ाया गया

एनडीएमसी अधिनियम, 1994 में संशोधन

67 संशोधन प्रस्तावित।

- संपत्ति कर प्रणाली: कर योग्य मूल्य पद्धति से इकाई क्षेत्र पद्धति में परिवर्तन, कर को संपत्ति के आकार, उपयोग और स्थान से जोड़ना।
- मूल्यांकन को सरल बनाने, विवेकाधिकार को कम करने और अनुपालन को बढ़ाने की उम्मीद है।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन

अनुपालन में छूट:

- क्षेत्राधिकार-विशिष्ट के बजाय राज्यव्यापी वाहन पंजीकरण।

➤ ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, नवीनीकरण की तिथि से, समाप्ति के बाद भी मान्य।

➤ लाइसेंस की समाप्ति के बाद 30 दिनों की छूट अवधि। दावा न्यायाधिकरणों को दावा दाखिल करने में 12 महीने तक की देरी को माफ करने का अधिकार।

संसद ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया

संसद ने दो प्रमुख विधेयक पारित किए हैं - राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 - जिनका उद्देश्य भारत के खेल प्रशासन में आमूल-चूल परिवर्तन लाना और 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत करना है। ये विधेयक केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा प्रस्तुत किए गए और दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिए गए।

राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025

उद्देश्य: ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर के अनुरूप खेल प्रशासन के लिए एक एकीकृत कानूनी ढाँचा स्थापित करना।

मुख्य प्रावधान:

- संघों को विनियमित और मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन।
- चुनाव में अनियमितताओं, पारदर्शिता की कमी, या लेखापरीक्षित खातों को प्रकाशित न करने पर संघों की मान्यता रद्द करने का अधिकार।
- खिलाड़ियों के चयन, प्रशासन और चुनावों से संबंधित विवादों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के एक वर्तमान/सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण।
- न्यायाधिकरण के निर्णयों की अँपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।
- खेल महासंघों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का अधिदेश।

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025

उद्देश्य: भारत के डोपिंग रोधी ढाँचे को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) के मानकों के अनुरूप बनाना।

प्रावधान:

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) की परिचालन स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड से निगरानी शक्तियाँ हटाता है। जाँच, प्रवर्तन और न्यायनिर्णय में नाडा के अधिकार को बढ़ाता है। 2036 ओलंपिक की बोली जीतने की भारत की संभावनाओं को मजबूत करता है।

महत्व

नैतिक शासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत जवाबदेही को बढ़ावा देता है। विवाद समाधान को सुव्यवस्थित करता है और खेल प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाता है। 2036 ओलंपिक की बोली जीतने की भारत की संभावनाओं को मजबूत करता है।

लोकसभा ने आयकर (संखा 2) विधेयक, 2025 पारित किया

- 1961 के अधिनियम का स्थान लेने वाला 'सरल' कानून



लोकसभा ने आयकर (संखा 2) विधेयक, 2025 पारित कर दिया है, जो आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेता है। अब यह विधेयक राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाएगा।

उद्देश्य: भारत के प्रत्यक्ष कर ढाँचे को सरल, सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना।

मुख्य सिद्धांत - "सरल"

S - सुव्यवस्थित संरचना और भाषा

I - एकीकृत और संक्षिप्त अधिनियम

M - न्यूनतम मुकदमेबाजी

P - व्यावहारिक और पारदर्शी

L - वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना और अपनाना

E - कुशल कर सुधार

प्रमुख विशेषताएँ

- कर कानूनों का सरल और समझने में आसान प्रारूपण।
- प्रावधानों का एक सुव्यवस्थित अधिनियम में समेकन।
- अस्पष्टता में कमी, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और विवादों से बचने के लिए मार्गदर्शन।
- अनावश्यक खंडों को हटाना और प्रति-संदर्भों का सरलीकरण।
- वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाते हुए स्थापित कर नीतियों को बरकरार रखा गया है।

1961 अधिनियम के प्रावधानों को बरकरार रखा गया है। यदि आयकर रिटर्न नियत तिथि तक दाखिल नहीं किया गया है, तो भी टीडीएस वापसी का दावा स्वीकार किया जा सकता है। धार्मिक-सह-धर्मार्थ ट्रस्टों को गुमनाम दान के लिए छूट। गैर-लाभकारी संगठनों (एनपीओ) पर आय पर कर लगाया जाता है (सकल प्राप्तियों पर नहीं)। गुमनाम दान छूट को मिश्रित-उद्देश्य वाले एनपीओ (धार्मिक + धर्मार्थ) तक बढ़ाया गया है।

नए/संशोधित प्रावधान

धारा 187 में "पेशा" शामिल किया गया है - ₹50 करोड़ से अधिक की प्राप्तियों वाले पेशेवर निधारित ई-भुगतान विधियों का उपयोग कर सकेंगे। घाटे को आगे ले जाने और समायोजित करने के स्पष्ट नियम। टीडीएस सुधार विवरण की समय सीमा 6 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दी गई है। एकीकृत पेशन योजना (यूपीएस) छूट जोड़ी गई है। खोज मामलों में ब्लॉक मूल्यांकन प्रावधानों को अद्यतन किया गया है। सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोषों को प्रत्यक्ष कर लाभ प्रदान किए गए हैं।

फ़रवरी 2025 के मसौदे से हटाए गए प्रस्ताव

- मिश्रित-उद्देश्य ट्रस्टों के लिए गुमनाम दान छूट को हटाना (अब बहाल)।
- टीडीएस वापसी दावों के लिए समय पर आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य (हटाया गया)।
- एनपीओ पर "आय" के बजाय "प्राप्तियों" के आधार पर कर लगाना (वापस)।

संसद ने नौवहन कानूनों के आधुनिकीकरण हेतु दो प्रमुख समुद्री विधेयक पारित किए

संसद ने भारत के नौवहन कानूनों को अद्यतन करने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने हेतु दो महत्वपूर्ण समुद्री विधेयक पारित किए। इनमें शामिल हैं:

- व्यापारी नौवहन विधेयक, 2024 - लोकसभा में पारित
- समुद्री माल परिवहन विधेयक, 2025 - राज्यसभा में पारित
- व्यापारी नौवहन विधेयक, 2024
- प्रतिस्थापित: व्यापारी नौवहन अधिनियम, 1958
- उद्देश्य: भारत के समुद्री ढाँचे को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलनों के अनुरूप बनाना।

मुख्य विशेषताएँ:

इसमें 16 भाग और 325 खंड हैं (पुराने अधिनियम में 561 से घटाकर)। समुद्र में सुरक्षा, आपातकालीन प्रतिक्रिया और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाता है। भारतीय टन भार और नाविक कल्याण को बढ़ावा देता है।

शिपिंग कंपनियों के लिए अनुपालन बोझ को कम करता है।

भारत के नौवहन क्षेत्र में विकास, निवेश और नवाचार को बढ़ावा देता है।

समुद्री माल परिवहन विधेयक, 2025

- प्रतिस्थापित: भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम, 1925
- उद्देश्य: समुद्री मार्ग से माल परिवहन से संबंधित कानून को सरल और आधुनिक बनाना।

मुख्य विशेषताएँ:

हेग-विस्बी नियम (माल परिवहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक) को अपनाना है। पारदर्शिता में सुधार, मुकदमेबाजी में कमी और व्यापार सुगमता को बढ़ाता है। भारतीय समुद्री कानून को सीईटीए जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के साथ संरेखित करता है।

लघु लेख

क्या रोहिंग्या 'शरणार्थी' हैं? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास अहम सवाल

1. कानूनी शून्यता: भारतीय कानून में शरणार्थी की कोई परिभाषा नहीं

भारत में शरणार्थियों को परिभाषित या संरक्षित करने वाला कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है। नागरिकता अधिनियम (1955) में केवल "अवैध अप्रवासियों" की परिभाषा है, जबकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन (1951) या उसके 1967 के प्रोटोकॉल पर न तो हस्ताक्षर किए हैं और न ही उसकी पुष्टि की है। परिणामस्वरूप, सर्वोच्च न्यायालय को यह तय करना होगा कि भारत में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी का दर्जा पाने के हकदार हैं या वे केवल अवैध रूप से प्रवेश कर रहे हैं।

2. सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रमुख प्रश्न

तीन न्यायाधीशों की पीठ से यह निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है:

क्या रोहिंग्या शरणार्थी किसी कानूनी मानक के अधीन हैं? यदि हाँ, तो उन्हें कौन से अधिकार और सुरक्षा मिलनी चाहिए? यदि नहीं, तो क्या भारत उन्हें कानूनी रूप से निर्वासित कर सकता है?

क्या अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखा जा सकता है, या क्या उनके पास ज़मानत के अधिकार हैं?

क्या शिविरों में गैर-हिरासत में रखे गए रोहिंग्याओं को स्वच्छ पानी, स्वच्छता या स्कूली शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएँ मिलती हैं?

3. भारत की वास्तविक नीति

रोहिंग्याओं की एक बड़ी आबादी होने के बावजूद—अनुमानतः लगभग 40,000, जिनमें 22,500 से ज़्यादा UNHCR-पंजीकृत व्यक्ति शामिल हैं—भारत उन्हें “अवैध अप्रवासी” मानता है। विदेशी अधिनियम (1946) उन्हें रोकने और निर्वासित करने का अधिकार देता है, और नागरिकता साबित करने का दायित्व व्यक्ति पर ही होता है।

4. सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले

8 मई, 2025 को, न्यायालय ने घोषणा की कि केवल भारतीय नागरिकों को ही भारत में निवास करने का संवैधानिक अधिकार है। परिणामस्वरूप, विदेशी माने जाने वाले रोहिंग्या व्यक्तियों को घरेलू कानून के तहत निर्वासन से कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है। निर्वासन रोकने की मांग वाली याचिकाओं के जवाब में—जिनमें म्यांमार के पास समुद्र में 40 रोहिंग्याओं को छोड़े जाने के परेशान करने वाले आरोप भी शामिल हैं—न्यायालय ने अंतरिम राहत को अस्वीकार कर दिया और याचिकाओं की आलोचना करते हुए कहा कि वे “खूबसूरती से तैयार की गई” हैं, लेकिन उनमें विश्वसनीय सबूतों का अभाव है।

5. अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाम भारत का रुख

गैर-प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, जो व्यक्तियों को उन देशों में वापस भेजने पर रोक लगाता है जहाँ उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत कानून में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। फिर भी, चूँकि भारत ने 1951 के शरणार्थी सम्मेलन की पुष्टि नहीं की है, इसलिए न्यायालय ने माना कि गैर-प्रत्यावर्तन भारत को कानूनी रूप से बाध्य नहीं करता है—हालाँकि याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि संवैधानिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 21 और 51(सी)) को इसे बरकरार रखना चाहिए।

6. जमीनी हक्कीकत

दिल्ली में रोहिंग्या बस्तियाँ—खासकर कालिंदी कुंज और श्रम विहार—बेहद भयावह हालात पेश करती हैं। परिवारों ने अचानक नज़रबंदी, आपात स्थिति में निर्वासन, बच्चों के स्कूल जाने के

कार्यक्रम में बाधा, और व्यापक भय की बात कही है क्योंकि आश्रय स्थल भी खतरे में हैं।

लंबे समय से यहाँ रहने वाले निवासियों—कुछ तो 2012 या उससे पहले से मौजूद हैं—में गहरा तनाव और अनिश्चितता साफ़ दिखाई देती है।

7. अधिकार बनाम राज्य की संप्रभुता

हालाँकि कई देश म्यांमार में हिंसा से भाग रहे रोहिंग्याओं को शरण देते हैं, भारत में शरणार्थी कानून का अभाव अधिकारियों को उन्हें सुरक्षा जोखिम के रूप में देखने पर मजबूर करता है। एक समान कानूनी ढाँचे के अभाव का मतलब है कि उनके साथ व्यवहार अस्थायी और असंगत है, जो सिद्धांत से ज़्यादा सुविधा पर आधारित है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (2019) इस परिवृश्य को और जटिल बना देता है। कुछ पड़ोसी देशों के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को त्वरित नागरिकता प्रदान करके, यह कानून रोहिंग्या जैसे मुस्लिम शरणार्थियों को इससे बाहर कर देता है—यह पूर्वग्रिहों को मज़बूत करता है और गैर-भेदभाव के मानदंडों को कमज़ोर करता है।

8. संवैधानिक तनाव

आलोचकों का कहना है कि अनुच्छेद 14 (समानता) और 21 (जीवन और स्वतंत्रता) के तहत मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं, चाहे उनकी नागरिकता कुछ भी हो। अनुच्छेद 51(c) भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने के लिए बाध्य करता है। संवैधानिक अधिकारों की व्याख्या में गैर-वापसी जैसी मानवीय सुरक्षा को शामिल करना भारत के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों के अनुरूप माना जाता है।

9. राजनीतिक और मानवीय प्रतिक्रिया

मानवाधिकार समूहों ने कथित जबरन निर्वासन की निंदा की है। एक व्यापक रूप से उद्धृत घटना में दावा किया गया है कि 40 रोहिंग्याओं—जिनमें बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे—को भारतीय अधिकारियों ने एक नौसैनिक पोत में डालकर म्यांमार के पास समुद्र में फेंक दिया था। हालाँकि सरकार किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार करती है, संयुक्त राष्ट्र ने इस कृत्य को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है।

10. आगे की राह और व्यापक निहितार्थ

सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करेगा:

- अगर रोहिंग्या को कानूनी सुरक्षा के हकदार शरणार्थी के रूप में मान्यता दी जाती है, तो भारत को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप मानवीय व्यवहार के लिए ढाँचे को लागू करने की आवश्यकता हो सकती है।
- अगर उन्हें अवैध अप्रवासी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो निष्कासन और संधि-स्वतंत्र हिरासत जारी रह सकती है।



- अदालत यह भी तय कर सकती है कि क्या अनिश्चितकालीन हिरासत को समाप्त करना या ज़मानत और बुनियादी सुविधाएँ सुनिश्चित करना संवैधानिक रूप से आवश्यक है।

अंततः, यह मामला भारत के कानूनी मानदंडों और उसकी मानवीय विरासत के बीच सामंजस्य को चुनौती देता है। एक निर्णयिक फैसला भविष्य की नीति-निर्माण को प्रभावित कर सकता है—शायद राष्ट्रीय शरणार्थी कानूनों को लागू करने के लिए प्रेरित कर सकता है, या अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता पर वैधानिक हठधर्मिता की पुष्टि कर सकता है।

सारांश तालिका

मुख्य मुद्दा	स्थिति / निहितार्थ
शरणार्थी मान्यता:	भारतीय कानून के तहत कोई परिभाषा नहीं
सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश:	निवास का अधिकार नागरिकों तक सीमित
संवैधानिक अधिकार:	अनुच्छेद 14 और 21 नागरिकों से आगे तक विस्तारित; गैर-वापसी का समर्थन कर सकते हैं
गैर-वापसी	भारत में कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी इसका संवैधानिक आधार होने का तर्क दिया जाता है
जमीनी स्थिति	शरणार्थी बस्तियों को भय, निर्वासन और सुविधाओं से वंचित होने का सामना करना पड़ रहा है
राजनीतिक माहौल:	सीएए मुस्लिम शरणार्थियों को बाहर करता है; मानवाधिकारों की चिंताएँ बढ़ती हैं
रणनीतिक अनिवार्यता	परिणाम भविष्य की शरणार्थी नीति रूपरेखा को प्रभावित कर सकते हैं

भारत में कानून, राज्य और आवारा कुर्तों की दुविधा

भारत में आवारा कुर्तों का संकट लंबे समय से जन स्वास्थ्य, कानूनी सिद्धांतों और मानवीय मूल्यों के चौराहे पर खड़ा है। यह मुद्दा दो बुनियादी विचारों को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा करता है: नागरिकों की सुरक्षा का संवैधानिक अधिकार और जानवरों के साथ दयालुता से पेश आने का नैतिक और कानूनी दायित्व। हाल के न्यायिक हस्तक्षेपों - विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के अगस्त 2025 के निर्देश और उसके बाद के संशोधन - ने इस गंभीर चुनौती से निपटने के तरीके पर एक राष्ट्रीय बहस को फिर से छेड़ दिया है।

1. कानूनी ढाँचा: वध की बजाय मानवीय व्यवहार

आवारा पशुओं के प्रति भारत का दृष्टिकोण पशु कूरता निवारण (पीसीए) अधिनियम, 1960 पर आधारित है, जो पशुओं को अनावश्यक पीड़ा से बचाने का आदेश देता है। इसी आधार पर, पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2001 के तहत नगरपालिका अधिकारियों को आवारा कुर्तों को उनके मूल स्थानों पर वापस छोड़ने से पहले उनकी नसबंदी और टीकाकरण करना अनिवार्य था। इस कानून में पागल, घातक रूप से घायल या गंभीर रूप से बीमार कुर्तों को छोड़कर, वध पर रोक लगा दी गई थी।

2023 के एबीसी नियमों ने इस मानवीय दर्शन को और पुष्ट किया। बिलियों तक कवरेज का विस्तार करते हुए और आवारा कुर्तों को औपचारिक रूप से "सामुदायिक पशु" के रूप में वर्गीकृत करते हुए, अद्यतन नियमों ने एक ऐसे ढाँचे को संस्थागत रूप दिया जो सह-अस्तित्व पर ज़ोर देता था।

न्यायालयों ने भी इन सिद्धांतों को लगातार बरकरार रखा। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम आवारा समस्याओं के उन्मूलन के लिए काम करने वाले लोग (2009) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा कुर्तों की अंधाधुंध हत्या पर रोक लगा दी। बाद के फैसलों, जिनमें के.के. वर्मा मामला (दिल्ली उच्च न्यायालय, 2015) और पेटा बनाम भारत संघ (2016) शामिल हैं, ने नसबंदी और टीकाकरण को पसंदीदा समाधान के रूप में फिर से पुष्ट की। हाल ही में 2022 में, सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा कुर्तों के भोजन के अधिकार पर ज़ोर दिया और अधिकारियों को एबीसी ढाँचे का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

2. अगस्त 2025 का निर्णयिक मोड़: मानव सुरक्षा सर्वोपरि

अगस्त 2025 में, सर्वोच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने इस दृष्टिकोण को बदल दिया। दिल्ली-एनसीआर में कुर्तों के काटने की घटनाओं और रेबीज से होने वाली मौतों में वृद्धि को देखते हुए, पीठ ने आदेश दिया कि सभी आवारा कुर्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी की जाए, उनका टीकाकरण किया जाए और उन्हें स्थायी रूप से आश्रय दिया जाए - उन्हें सड़कों पर वापस छोड़े बिना।

यह निर्देश एमिक्रस क्यूरी की एक रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधारित था, जिसमें तर्क दिया गया था कि कुर्तों के हमलों के डर के बिना नागरिकों का स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, आवारा कुर्तों के सार्वजनिक क्षेत्रों में घूमने के अधिकार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जब तक कुत्ते लगातार सार्वजनिक खतरा पैदा करते रहेंगे, तब तक मानवीय सह-अस्तित्व अस्थिर है।

अदालत ने नगर निगम अधिकारियों को आदेश का पालन करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया, बाधा डालने पर दंड की चेतावनी दी और एक समर्पित पशु हेल्पलाइन की भी स्थापना करने का आह्वान किया।

3. कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों का विरोध

इस फैसले से हँगामा मच गया। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं, कल्याणकारी संगठनों और मेनका गांधी जैसे राजनीतिक नेताओं

ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे असंवैधानिक और अव्यावहारिक बताया। आलोचकों ने कहा: दिल्ली में लगभग दस लाख आवारा कुत्तों के लिए आश्रय स्थल का अभाव है। अनुमानित लागत ₹15,000 करोड़ से अधिक है, जिससे इसे लागू करना आर्थिक रूप से अव्यावहारिक हो गया है। कुत्तों को सामूहिक रूप से स्थानांतरित करने से पारिस्थितिकी तंत्र अस्थिर हो जाएगा, जिससे रेबीज के मामलों में वृद्धि हो सकती है। PETA और FIAPo जैसे संगठनों ने ज़ोर देकर कहा कि सामूहिक बंदी नहीं, बल्कि नसबंदी और टीकाकरण ही वैज्ञानिक रूप से सिद्ध और विश्व स्तर पर स्वीकृत उपाय हैं। इसके बाद विरोध प्रदर्शन, सोशल मीडिया अभियान और कानूनी चुनौतियाँ शुरू हो गईं, जिससे सुरक्षा अधिवक्ताओं और पशु प्रेमियों के बीच जनमत का ध्रुवीकरण हो गया।

4. राज्यों में कार्यान्वयन चुनौतियाँ

व्यावहारिक बाधाएँ जल्दी ही सामने आईं। भारत भर के नगर निकायों ने इन मुद्दों पर चिंता व्यक्त की: सीमित आश्रय स्थल और भीड़भाड़।

पशु चिकित्सकों और कुत्तों को पकड़ने वाले कर्मचारियों की कमी। पिंजरे, संशोधित परिवहन वाहन और टीके सहित रसद संबंधी ज़रूरतें।

उदाहरण के लिए, नागपुर के कार्यकर्ताओं ने ऐसे आदेशों को देश भर में लागू करने की घोर अव्यावहारिकता पर चिंता जताई। इसके बजाय, उन्होंने रोमानिया के मानवीय दृष्टिकोण जैसे मॉडलों पर विचार करने का सुझाव दिया, जिसमें नसबंदी, टीकाकरण और गोद लेने के अभियान शामिल हैं।

बॉम्बे उच्च न्यायालय के 2022 के फैसले ने पहले ही इन कमियों को उजागर कर दिया था, जिसमें नगरपालिकाओं को आश्रय स्थल बनाने और आवारा कुत्तों के भोजन को विनियमित करने का निर्देश दिया गया था। फिर भी, प्रवर्तन कमज़ोर रहा है, जिससे प्रणालीगत अक्षमता और भी उजागर हुई है।

5. संशोधित सर्वोच्च न्यायालय का आदेश: एक मध्य मार्ग

30 अगस्त, 2025 को, व्यापक आलोचना के बाद, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले पर पुनर्विचार किया। पहले के निर्देश को "बहुत कठोर" बताते हुए, न्यायालय ने अपने आदेश में संशोधन किया:

आवारा कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और कृमिनाशक दवा दी जानी चाहिए।

उपचार के बाद, उन्हें एबीसी नियम, 2023 के अनुसार उनके इलाकों में वापस छोड़ दिया जाना चाहिए।

अपवाद: रेबीज से संक्रमित या संदिग्ध कुत्तों, और आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि आश्रयों में रखा जाना चाहिए।

नगरपालिकाओं को प्रत्येक वार्ड में समर्पित आहार क्षेत्र बनाने होंगे, जहाँ सड़कों पर भोजन कराना सख्त वर्जित है।

सड़कों पर भोजन कराने या नगरपालिका अधिकारियों के काम में बाधा डालने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

उल्लंघनों के लिए समर्पित हेल्पलाइन स्थापित की जानी चाहिए। पीठ ने स्वीकार किया कि सभी आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के लिए "भारी मात्रा में रसद" की आवश्यकता होगी और इसलिए यह अव्यावहारिक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित सभी आवारा कुत्तों से संबंधित मामलों को भी अपने पास स्थानांतरित कर लिया, जिससे एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने के उसके इरादे का संकेत मिलता है।

6. मानवाधिकार और पशु कल्याण में संतुलन

इस बहस का केंद्रबिंदु संविधान के अनुच्छेद 21 — जीवन और सुरक्षा का अधिकार — को भारत के पशु कल्याण कानूनों के साथ समंजस्य बिठाना है।

भारत में सालाना 1.7 करोड़ से ज्यादा कुत्तों के काटने की घटनाएँ और 18-20,000 रेबीज से मौतें दर्ज की जाती हैं।

2025 की पहली छमाही में अकेले दिल्ली में 35,000 काटने की घटनाएँ और 49 रेबीज के मामले सामने आए।

कई नागरिकों के लिए, आवारा कुत्ते एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का प्रतीक हैं। फिर भी, पशु कल्याण के पैरोकारों का तर्क है कि आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के बाद, वे कोई बड़ा खतरा पैदा नहीं करते और विस्थापन मानवीय नैतिकता और सामुदायिक संतुलन को कमज़ोर करता है।

7. व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ

यह संघर्ष नया नहीं है। भारत का इतिहास इसके उदाहरण प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से 1832 के बॉम्बे डॉग दंगे, जहाँ सामूहिक वध के विरुद्ध जनाक्रोश के कारण नीतिगत बदलाव हुए और कुत्तों को दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित किया गया। जनवरों के प्रति धार्मिक और सांस्कृतिक श्रद्धा ने भी हिंसक उपायों के प्रति भारत की अनिच्छा को आकार दिया है।

8. आगे की राह: एक संतुलित समाधान की ओर

सुप्रीम कोर्ट का नवीनतम हस्तक्षेप एक संतुलनकारी कदम को दर्शाता है - मानवीय कानूनी ढाँचों का सम्मान करते हुए नागरिकों की सुरक्षा की तल्काल आवश्यकता को स्वीकार करना। विश्लेषकों का मानना है कि आगे बढ़ने का स्थायी रास्ता मिश्रित समाधानों में निहित है:

- देश भर में एबीसी कार्यक्रमों का विस्तार और गति प्रदान करना।
- केवल पागल या आक्रामक कुत्तों के लिए अच्छी तरह से वित्त पोषित आश्रय स्थल बनाना।
- परस्पर क्रिया को विनियमित करने के लिए समर्पित आहार क्षेत्र स्थापित करना।
- सामुदायिक भागीदारी के साथ गोद लेने के अभियानों को प्रोत्साहित करना।

- नगरपालिका के बुनियादी ढाँचे और जवाबदेही को मज़बूत करना।
 - देहरादून और लखनऊ जैसे शहरों के उदाहरण, जहाँ आक्रामक नसबंदी अभियानों ने आवारा कुत्तों की आबादी को कम किया है, वैज्ञानिक और मानवीय तरीकों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करते हैं।

निष्कर्ष

भारत का आवारा कुत्तों का संकट मानव सुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच एक नाजुक संतुलन का प्रतीक है। 11 अगस्त, 2025 के आदेश ने मानव-केंद्रित समाधानों की ओर एक निर्णायिक लेकिन चरम बदलाव को चिह्नित किया। 30 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए संशोधन ने एबीसी नियम, 2023 में विश्वास बहाल किया है, व्यावहारिक सीमाओं को स्वीकार किया है और मानवीय सिद्धांतों की पृष्ठी की है।

हालाँकि, आगे की राह अभी भी चुनौतीपूर्ण है। मज़बूत नगरपालिका क्षमता, पर्याप्त धन और सामुदायिक भागीदारी के बिना, सर्वोत्तम कानूनी ढाँचा भी अधूरा रह सकता है। भारत को इस दुविधा से करुणा, व्यावहारिकता और दूरदर्शिता के साथ निपटना होगा - यह सुनिश्चित करते हुए कि जन सुरक्षा और पशु कल्याण को प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में नहीं, बल्कि एक मानवीय समाज में सह-अस्तित्व वाली प्राथमिकताओं के रूप में देखा जाए।

जम्मू-कश्मीर के मनोनीत सदस्यों पर केंद्र का रुख

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) निर्वाचित मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना विधानसभा में अधिकतम पाँच सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। इस स्थिति ने केंद्र, केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी विधानसभाओं के बीच शक्ति संतुलन पर चर्चा को फिर से शुरू कर दिया है।

पुनर्गठन अधिनियम के तहत कानूनी आधार

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019, जिसे 2023 में संशोधित किया गया है, 90 सदस्यीय निर्वाचित विधानसभा के साथ-साथ एलजी को पाँच अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्रदान करता है। यह विशेषता अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से तुलना करने पर अलग है, जहाँ संसद द्वारा पारित सक्षम कानून के आधार पर नामांकन नियम भिन्न होते हैं।

अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तुलनात्मक स्थिति

वर्तमान में, केवल दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर में ही निर्वाचित विधानसभाएँ और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। दिल्ली विधानसभा में 70 निर्वाचित सदस्य हैं, लेकिन मनोनीत विधायकों की अनुमति नहीं है। दूसरी ओर, पुडुचेरी में 30 निर्वाचित सदस्य हैं और केंद्र सरकार को केंद्र शासित प्रदेश शासन अधिनियम, 1963 के तहत तीन विधायकों को मनोनीत करने की अनुमति है।

ये भिन्नताएँ इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों की विधायिकाएँ संविधान के बजाय संसदीय कानून की उपज हैं।

संसद और राज्य परिषदों में मनोनीत सदस्य

संविधान कुछ विधायिकाओं में मनोनीत सदस्यों का भी प्रावधान करता है। अनुच्छेद 80 के तहत, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से चुनकर राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ऐसे सदस्यों को सांसदों के अधिकांश विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, हालाँकि वे राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। अनुच्छेद 171 राज्यपालों को विधान परिषदों में सदस्यों के छठे हिस्से को मनोनीत करने का अधिकार देता है, लेकिन केवल मंत्रिमंडल की सलाह से। पहले, संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन प्रतिनिधित्व के प्रावधान मौजूद थे, लेकिन 2020 में 104वें संशोधन द्वारा इहें समाप्त कर दिया गया।

न्यायिक व्याख्या

अदालतों ने नामांकन से संबंधित शक्तियों को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुङ्चेरी मामले (के. लक्ष्मीनारायणन बनाम भारत संघ, 2018) में, मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के केंद्र शासित प्रदेशों की मन्त्रिपरिषद से परामर्श किए बिना विधायकों को नामित करने के अधिकार को बरकरार रखा, जिसकी बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भी पुष्टि की। इसके विपरीत, दिल्ली मामले (2023) में, सर्वोच्च न्यायालय ने लोकतांत्रिक शासन में "जवाबदेही की त्रिस्तरीय श्रृंखला" पर ज़ोर दिया और कहा कि उपराज्यपाल को विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों को छोड़कर, सामान्यतः मत्रियों की सलाह पर कार्य करना चाहिए।

व्यापक निहितार्थ

मनोनीत सदस्यों को लेकर चल रही बहस संघीय संतुलन, केंद्र-केंद्र शासित प्रदेश संबंधों और लोकतांत्रिक जवाबदेही के गहरे मुद्दों को दर्शाती है। जहाँ नामांकन विधायिकाओं में विशेषज्ञता और प्रतिनिधित्व लाने में मदद करता है, वहीं यह निर्वाचित सरकारों को दरकिनार करने की चिंता भी पैदा करता है। विकसित हो रहे न्यायशास्त्र और विधायी संशोधन भारत द्वारा अशिक राज्यत्व विशेषताओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के अपने अनूठे मॉडल के प्रबंधन को आकार दे रहे हैं।

दिल्ली में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की सीमित प्रगति

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) योजना 2019 के तहत बलात्कार और बाल यौन शोषण के मामलों से निपटने के लिए स्थापित होने के बावजूद, दिल्ली की अदालतें जून 2025 तक केवल 43% लंबित मामलों का ही निपटारा कर पाई हैं। इससे यह चिंता पैदा हो गई है कि क्या पीड़ितों को शोषण न्याय दिलाने का वादा पूरा हो रहा है, क्योंकि देरी से न्यायिक प्रणाली की प्रभावशीलता में जनता का विश्वास कम होता है।

योजना की उत्पत्ति और उद्देश्य

एफटीएससी योजना को निर्भया कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त विधि और न्याय मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। प्रत्येक अदालत से प्रतिवर्ष कम से कम 165 मामलों को निपटाने की अपेक्षा की जाती है। मूल रूप से तीन वर्षों के लिए शुरू की गई इस योजना को दो बार बढ़ाया जा चुका है, जिसकी वर्तमान समय सीमा मार्च 2026 निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य यौन अपराधों के लंबित मामलों के विशाल लंबित मामलों से निपटने के लिए देश भर में 790 ऐसी अदालतें स्थापित करना है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी

लम्बित बलाकार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) मामलों की बढ़ती संख्या के कारण समर्पित अदालतों की माँग बढ़ी। जुलाई 2019 में, सर्वोच्च न्यायालय ने 100 से अधिक लंबित POCSO मामलों वाले सभी जिलों को विशेष अदालतें स्थापित करने का निर्देश दिया। POCSO अधिनियम, 2012 में ही यह अनिवार्य है कि संज्ञान के एक वर्ष के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। इसका उद्देश्य न केवल पीड़ितों को समय पर न्याय प्रदान करना था, बल्कि शीघ्र दंड सुनिश्चित करके निवारण को भी बढ़ाना था।

कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति

जून 2025 तक, 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 392 विशेष POCSO अदालतों सहित 725 FTSC कार्यरत थे। इस योजना ने 2024 में लगभग 96% की निपटान दर के साथ उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। हालाँकि, दिल्ली की स्थिति दर्शाती है कि

प्रदर्शन असमान रहा है, जहाँ कई अदालतें मामलों के निपटारे के वांछित स्तर को प्राप्त करने में असमर्थ रही हैं।

लगातार बाधाएँ

एफटीएससी का कामकाज कई चुनौतियों से बाधित रहा है। 1,023 स्वीकृत अदालतों में से, केवल लगभग 700 ही कार्यरत हैं, जबकि अनुमान बताते हैं कि लंबित मामलों को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए लगभग 1,000 अतिरिक्त अदालतों की आवश्यकता है। आलोचकों का तर्क है कि कुछ मामलों को "तेज़ी से निपटाने" के परिणामस्वरूप अक्सर नियमित अदालतों से न्यायाधीशों का स्थानांतरण हो जाता है, जिससे अन्य मुकदमों की गति धीमी हो जाती है। इसके अलावा, पीड़ित-अनुकूल बुनियादी ढाँचे, जैसे कि कमज़ोर गवाह बयान केंद्र, बाल मनोवैज्ञानिक और विशेषज्ञ अभियोजकों की कमी, इन अदालतों की प्रभावशीलता को सीमित करती है।

तंत्र को मज़बूत करना

विशेषज्ञों ने एफटीएससी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लक्षित सुधारों की सिफारिश की है। पॉक्सो मामलों के लिए विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति, विशेष प्रशिक्षण और महिला अभियोजकों की तैनाती को आवश्यक माना जाता है। गवाही दर्ज करने के लिए बच्चों के अनुकूल स्थानों का निर्माण, साथ ही पीड़ितों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग, डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन और तेज़ फोरेंसिक सहायता जैसे तकनीकी उन्नयन भी मुकदमों में देरी को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

CURRENT AFFAIRS

"जिन्दगी में तकलीफ कितनी भी हो कभी हताश मत होना
क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ क्यों न हो समंदर कभी
सुखा नहीं होता !!

"संघर्ष इंसान को मज़बूत बनाता है !
फिर चाहे वह कितना भी कमज़ोर क्यों न हो !!

अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं घटनाएँ

मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का 107वाँ सदस्य बना

विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, मोल्दोवा गणराज्य आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का 107वाँ सदस्य बन गया है। आईएसए, भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान शुरू की गई एक वैश्विक पहल है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। मोल्दोवा ने भारत में अपनी राजदूत एना तबान और संयुक्त सचिव (आर्थिक कूटनीति) पी.एस. गंगाधर के बीच हुई बैठक के दौरान अनुसमर्थन पत्र प्रस्तुत किया। आईएसए का उद्देश्य 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देना, सौर प्रौद्योगिकी और वित्तपोषण की लागत को कम करना और कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन और बिजली उत्पादन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। आईएसए के सदस्य देश नीति-निर्माण, मानकीकरण, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सौर ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने के माध्यम से सहयोग करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए):

- प्रारंभकर्ता: भारत और फ्रांस
- प्रारंभ वर्ष: 2015
- प्रारंभ स्थान: COP21, पेरिस
- मुख्यालय: गुरुग्राम, हरियाणा, भारत
- उद्देश्य: सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, लागत कम करना, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना और सौर निवेश को प्रोत्साहित करना
- सदस्यता प्रकार: सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के लिए खुला
- कुल सदस्य: 107 देश (मोल्दोवा सहित)

मोल्दोवा:

- राजधानी: चिसीनात
- मुद्रा: मोल्दोवन ल्यू (एमडीएल)
- सीमाएँ: यूक्रेन, रोमानिया
- राष्ट्रपति: मैया संदू

दक्षिण कोरिया-वियतनाम ऊर्जा और आर्थिक सहयोग पर सहमत

दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति ली जे म्युंग और वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव टो लैम ने आर्थिक संबंधों को गहरा करने का संकल्प लिया, और नए अमेरिकी टैरिफ (दक्षिण कोरिया वस्तुओं पर 15% और वियतनामी वस्तुओं पर 20%) के कारण उत्पन्न वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया।

व्यापार और निवेश लक्ष्य

दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 150 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जो 2024 में 86.8 बिलियन

डॉलर था। वर्तमान में, लगभग 10,000 दक्षिण कोरियाई कंपनियाँ वियतनाम में कार्यरत हैं, जो वियतनाम के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। लैम ने विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में और अधिक दक्षिण कोरियाई निवेश का स्वागत किया।

हस्ताक्षरित समझौते

लैम की चार दिवसीय राजकीय यात्रा (जून में ली के पदभार ग्रहण करने के बाद से दक्षिण कोरिया के राजकीय अतिथि के रूप में उनकी पहली यात्रा) के दौरान, दोनों देशों ने 10 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें शामिल हैं:

- परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग
- मौद्रिक और वित्तीय नीतियाँ
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग
- उच्च गति रेल परियोजनाओं सहित बुनियादी ढाँचा विकास

दक्षिण कोरिया:

- राजधानी: सियोल
- मुद्रा: दक्षिण कोरियाई वोन (KRW)
- राष्ट्रपति: ली जे म्युंग (2025)
- प्रमुख उद्योग: इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, जहाज निर्माण, पेटोकेमिकल्स, इस्पात
- प्रमुख कंपनियाँ: सैमसंग, हुंडई, एलजी, कि.आ
- प्रमुख बंदरगाह: बुसान, इंचियोन
- पड़ोसी देश: उत्तर कोरिया (भूमि सीमा), चीन और जापान के साथ समुद्री सीमाएँ
- वैश्विक स्थिति: OECD, G20, WTO और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य

वियतनाम:

- राजधानी: हनोई
- मुद्रा: वियतनामी डोंग (VND)
- कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव: तो लाम (2025)
- प्रधानमंत्री: फाम मिन्ह चिन्ह
- प्रमुख उद्योग: कपड़ा, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, समुद्री भोजन
- प्रमुख निर्यात: इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, जूते, मशीनरी, कॉफी, चावल
- प्रमुख बंदरगाह: हाई फोंग, दा नांग, हो ची मिन्ह सिटी (कैट लाई)
- पड़ोसी देश: चीन, लाओस, कंबोडिया; दक्षिण चीन सागर के साथ तटरेखा
- वैश्विक स्थिति: आसियान, विश्व व्यापार संगठन, एपेक और आरसीईपी के सदस्य

ट्रम्प के साथ व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन में अज़रबैजान और आर्मेनिया ने शांति प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के दौरान शुक्रवार को वॉशिंगटन डी.सी. स्थित व्हाइट हाउस में अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच काकेशस शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति ट्रम्प की मध्यस्थता में हुए इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच दशकों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करना था और यह क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था।

मुख्य बिंदु:

अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान ने दशकों से चले आ रहे संघर्ष, विशेष रूप से नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र में, को समाप्त करने के लिए एक शांति प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए।

समझौते में शामिल हैं:

- शत्रुता का स्थायी समापन।
- दोनों देशों के बीच प्रमुख परिवहन मार्गों को फिर से खोलना।
- यात्रा, व्यापार और राजनयिक संबंधों की स्थापना।
- एक प्रमुख पारगमन गलियारे के निर्माण में अमेरिकी सहायता, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि के लिए ट्रम्प रूट नाम दिया गया है, जो अर्मेनियाई क्षेत्र के माध्यम से अज़रबैजान को उसके नखचिवन एक्सक्लेव से जोड़ता है।

पृष्ठभूमि:

अज़रबैजान और आर्मेनिया ने 1980 और 1990 के दशक के अंत में नागोर्नो-काराबाख को लेकर संघर्ष किया था; तब से छिप्पट हिंसा होती रही है। नखचिवन तक जाने वाले गलियारे पर नियंत्रण को लेकर पिछली वार्ताएँ रुकी हुई थीं।

महत्व:

- दोनों देशों के बीच 35 वर्षों में पहला बड़ा शांति समझौता।
- यह काकेशस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव का विस्तार करता है, रूस को दरकिनार करता है, जिसने ऐतिहासिक रूप से इस संघर्ष में मध्यस्थता की थी।
- ट्रंप ने ऊर्जा और प्रौद्योगिकी व्यापार का विस्तार करने के लिए दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए।
- भू-राजनीतिक टिप्पणी: पिछले शांति प्रयासों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मध्यस्थता की थी, लेकिन दोनों देशों ने अमेरिका के नेतृत्व वाले समाधान के पक्ष में मास्को के प्रस्तावों को त्याग दिया।

अज़रबैजान

- राजधानी - बाकू
- मुद्रा - अज़रबैजानी मनात (AZN)
- राष्ट्रपति - इल्हाम अलीयेव
- भूगोल - कैस्पियन सागर के किनारे तटरेखा को छोड़कर स्थल-रुद्ध; रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान की सीमाएँ।
- प्रमुख धर्म - इस्लाम (मुख्यतः शिया)।

- अर्थव्यवस्था - प्रमुख तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादक; ओपेक+ का सदस्य।

आर्मेनिया

- राजधानी - येरेवन
- मुद्रा - अर्मेनियाई ड्राम (एएमडी)
- आधिकारिक भाषा - अर्मेनियाई
- प्रधानमंत्री - निकोल पाशिनयान
- भूगोल - स्थलरुद्ध; जॉर्जिया, अज़रबैजान, ईरान और तुर्की से सीमाएँ।
- प्रमुख धर्म - ईसाई धर्म (अर्मेनियाई अपोस्टोलिक चर्च; सबसे पुराने ईसाई राष्ट्रों में से एक)।
- अर्थव्यवस्था - कृषि, खनन (तांबा, सोना), बढ़ता आईटी क्षेत्र।

भारत और संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को गति देने के लिए दर्दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने हेतु 'संयुक्त राष्ट्र-भारत वैश्विक क्षमता निर्माण पहल' शुरू की

भारत के विदेश मंत्रालय (एमईए) और भारत में संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त रूप से दर्दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में प्रगति में तेज़ी लाने के लिए संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र-भारत वैश्विक क्षमता निर्माण पहल नामक एक नई पहल शुरू की है। इस साझेदारी का उद्देश्य वैश्विक दर्दक्षिण देशों के साथ भारतीय विकास नवाचारों को उनकी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप साझा करना है।

इस पहल को निम्नलिखित माध्यमों से समर्थन प्राप्त होगा:

- संयुक्त राष्ट्र भारत सतत विकास लक्ष्य देश निधि (प्रारंभ में गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित)
 - भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम
- पहले बैच के अंतर्गत चयनित पायलट परियोजनाओं में शामिल हैं:
- डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा पहुँच - यूएनडीपी और सी.डैक, एनएचए और एनआईएचएफडब्ल्यू (जाम्बिया और लाओ पीडीआर) द्वारा समर्थित
 - फोर्टिफाइड चावल आपूर्ति श्रृंखला - डब्ल्यूएफपी और एनआईएफटीईएम, कुंडली (नेपाल)
 - जनगणना तैयारी संवर्धन - यूएनएफपीए और एनएसएसटीए, ओआरजीआई (कैरेबियाई राष्ट्र) द्वारा समर्थित
 - टीवीईटी पीपीपी पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण - यूनेस्को और एनआईईएसबीयूडी, एनएसडीसी (दक्षिण सूडान) द्वारा समर्थित

यह पहल सतत विकास लक्ष्य-17 (लक्ष्यों के लिए साझेदारी) पर ज़ोर देती है और भारत के वसूलीव कुटुम्बकम (विश्व एक परिवार है) के सिद्धांत को बढ़ावा देती है।

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) - मुख्य तथ्य

- स्थापना तिथि: 24 अक्टूबर 1945 (संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है)
- स्थापना तिथि: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, शांति को बढ़ावा देने और भविष्य के संघर्षों को रोकने के लिए
- कुल सदस्य देश: 193 सदस्य
- मुख्यालय: न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका

अमेरिका-चीन व्यापार युद्धविराम बढ़ाने पर सहमत

अमेरिका और चीन अपने व्यापार युद्धविराम को 10 नवंबर, 2025 तक बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। नए टैरिफ लागू होने से कुछ ही घंटे पहले यह कदम उठाया गया है। इस विस्तार से आगे की बातचीत के लिए 90 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है।

टैरिफ की स्थिति

इस समझौते के तहत, दोनों देश टैरिफ में बढ़ोतरी की योजना पर रोक लगा देंगे। अमेरिका का इरादा चीनी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 145% करने का था, जबकि चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर 125% टैरिफ लगाने की योजना बनाई थी। इसके बजाय, अमेरिका में चीनी आयात पर मौजूदा टैरिफ 30% और चीन को अमेरिकी निर्यात पर 10% ही रहेगा।

वार्ता में प्रमुख मुद्दे

इस विस्तारित वार्ता का उद्देश्य कई चिंताओं का समाधान करना है, जिनमें 2024 में चीन के साथ 300 अरब डॉलर का अमेरिकी व्यापार घाटा (किसी भी देश के साथ सबसे बड़ा), बाजार पहुँच, अनुचित व्यापार व्यवहार और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे शामिल हैं। अन्य विषयों में चीन द्वारा रूसी तेल की खरीद, दुर्लभ खनिजों तक पहुँच और प्रौद्योगिकी निर्यात पर अमेरिकी प्रतिबंध शामिल हैं।

अमेरिकी कार्रवाई

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने विस्तार को औपचारिक रूप देने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों को विवादों को सुलझाने और दीर्घकालिक समझौते की दिशा में काम करने के लिए अधिक समय मिल गया।

अमेरिका-चीन व्यापार संबंध:

- राजनयिक संबंध स्थापित: 1979
- सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार: चीन, वस्तुओं के मामले में अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
- चीन को अमेरिका के प्रमुख निर्यात: सोयाबीन, विमान, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर।
- अमेरिका को चीन के प्रमुख निर्यात: इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, वस्त्र, फर्नीचर, खिलौने।
- व्यापार घाटा: अमेरिका का चीन के साथ लगातार बड़ा व्यापार घाटा रहा है; 2022 में 382 अरब डॉलर का वस्तु व्यापार घाटा दर्ज किया गया।
- बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI): चीन की वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजना, जिसकी अक्सर व्यापारिक प्रभाव के संदर्भ में चर्चा होती है।

- पहले चरण का व्यापार समझौता: जनवरी 2020 में हस्ताक्षरित, जिसका उद्देश्य अमेरिकी वस्तुओं की चीनी खरीद को बढ़ाना और बौद्धिक संपदा संबंधी चिंताओं का समाधान करना था।
- प्रौद्योगिकी विवाद: राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण हुआवेई और टिकटॉक जैसी चीनी कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध।
- दुर्लभ मृदा खनिज: चीन वैश्विक उत्पादन के 60% से अधिक को निर्यात करता है, जिसका प्रभाव तकनीकी और रक्षा उद्योगों पर पड़ता है।
- वैश्विक व्यापार संगठन: दोनों विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्य हैं।
- सामरिक प्रतिद्वंद्विता: व्यापारिक मुद्दे दक्षिण चीन सागर, ताइवान और प्रौद्योगिकी प्रभुत्व में भू-राजनीतिक तनाव से जुड़े हैं।

लघु लेख**'मित्रता से मतभेद तक: 2025 में बदलते भारत-अमेरिका संबंध'****परिचय: तेज़ी से बदलता रणनीतिक परिवृश्य**

2025 में भारत-अमेरिका संबंध कुछ ही महीनों में आशावाद से तनाव में बदल गए हैं। वर्ष की शुरुआत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस यात्रा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ एक मजबूत व्यक्तिगत संबंध का संकेत दिया था, जिसके साथ महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी थे - 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 500 अरब डॉलर तक पहुँचाना, और रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल तकनीक में सहयोग का विस्तार करना।

हालाँकि, व्यापार वार्ता में रुकावट, रूस के साथ भारत के निरंतर संबंधों पर वाशिंगटन की नाराज़गी और साझेदारी में तनाव पैदा करने वाली कई आर्थिक और कूटनीतिक कार्रवाइयों के कारण यह सद्व्यवहार जल्दी ही कम हो गई।

ऐतिहासिक संदर्भ: चरणों में निर्मित एक रिश्ता

भारत-अमेरिका संबंध अलग-अलग चरणों में विकसित हुए हैं:

- 1990 का दशक - रणनीतिक शुरुआत: शीत युद्ध के बाद के सुधारों और आर्थिक उदारांकरण ने भारत को पश्चिमी व्यापार और निवेश के लिए खोल दिया।
- 2000 का दशक - असैन्य परमाणु समझौता: 2005 का समझौता एक रणनीतिक सफलता का प्रतीक था, जिसने भारत को परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद परमाणु तकनीक तक पहुँच प्रदान की।
- 2010 का दशक - हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तालमेल: चीन की आक्रामकता पर बढ़ती चिंता ने दोनों देशों को करीब ला दिया, जिसमें क्वाड सहयोग और प्रमुख हथियार सौदे शामिल हैं।

- 2020 का दशक - बहु-क्षेत्रीय साइडेनारी: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष तकनीक, अर्थचालक और रक्षा निर्माण में सहयोग गहरा हुआ। हालाँकि, व्यापार, जलवायु वित्त और रूस की भूमिका पर मतभेद उभरने लगे।

कारण: शुल्क और प्रतिउपाय

1 अगस्त, 2025 को, संयुक्त राज्य अमेरिका ने व्यापार असंतुलन का हवाला देते हुए भारतीय वस्तुओं पर 25% पारस्परिक शुल्क लगाया। इसके बाद भारत द्वारा रूसी तेल और रक्षा उपकरणों की निरंतर खरीद से जुड़े उत्पादों पर अतिरिक्त 25% जुर्माना लगाया गया, जिससे शुल्क प्रभावी रूप से 50% तक बढ़ गया। अमेरिकी सांसदों और अर्थशास्त्रियों ने चिंता व्यक्त की है कि इन उपायों से दशकों की कूटनीतिक प्रगति पर पानी फिर सकता है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने इस कदम को "सिर पर बंदूक तानकर बातचीत" जैसा बताया।

वाशिंगटन के दृष्टिकोण से, ये टैरिफ एक आर्थिक और राजनीतिक संदेश थे—भारत पर अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्यों के साथ और अधिक निकटता से जुड़ने का दबाव बनाने के लिए। दिल्ली के दृष्टिकोण से, ये रणनीतिक स्वायत्ता का उल्लंघन थे।

भारत के लिए आर्थिक परिणाम

टैरिफ में वृद्धि ने कई भारतीय निर्यात क्षेत्रों को प्रभावित किया है:

- रत्न और आभूषण (विशेषकर तराशे हुए हीरे)
- झींगा जैसे समुद्री उत्पाद
- वस्त्र और कालीन
- दवाएँ और रसायन

उच्च शुल्क लाभप्रदता के लिए खतरा हैं, अमेरिकी बाज़ार में प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करते हैं, और निर्यात मात्रा में उल्लेखनीय गिरावट ला सकते हैं। भारत सरकार ने निर्यातिकों - विशेष रूप से मछुआरों, किसानों और लघु-स्तरीय निर्माताओं - को बाज़ारों में विविधता लाने और अमेरिका पर निर्भरता कम करने की सलाह दी है।

उद्योग विशेषक व्यापक आर्थिक जोखिमों की चेतावनी देते हैं:

- जीडीपी वृद्धि में 1% तक की कमी
- रुपये के कमज़ोर होने की संभावना
- आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से बढ़ती मुद्रास्फीति
- निवेशकों का विश्वास कम होने पर पूँजी पलायन का जोखिम

भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक प्रतिक्रिया

नई दिल्ली की प्रतिक्रिया दृढ़ लेकिन संयमित रही है। सरकार:

- अमेरिका के इस दावे को खारिज किया कि उसकी रूस नीति द्विपक्षीय संबंधों को कमज़ोर करती है
- ऊर्जा और रक्षा खरीद में रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखने के अधिकार पर ज़ोर दिया
- "मेड इन इंडिया" अभियानों के माध्यम से घरेलू खपत को प्रोत्साहित किया

प्रतिक्रिया के रूप में अमेरिकी हथियारों की खरीद (जैवलिन मिसाइलों सहित) को संभावित रूप से स्थगित करने का संकेत दिया

महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। भारतीय सांसद लगातार इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि यह संबंध बहुआयामी है - जिसमें रक्षा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और जलवायु सहयोग शामिल हैं - और इसे केवल व्यापार विवादों के कारण पटरी से नहीं उतारना चाहिए।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए रणनीतिक निहितार्थ

शुल्क और ब्यानबाजी के द्विपक्षीय व्यापार से परे भी निहितार्थ हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में, और विशेष रूप से क्वाड (अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ) जैसे समूहों में भारत की भूमिका, वाशिंगटन के साथ तनाव के कारण जटिल हो सकती है।

यदि इसे संभाला नहीं गया, तो मौजूदा दरार संयुक्त समुद्री सुरक्षा पहलों, प्रौद्योगिकी सहयोग और चीन की आक्रामकता के प्रति समन्वित प्रतिक्रियाओं को प्रभावित कर सकती है।

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) का पदनाम

11 अगस्त, 2025 को, अमेरिकी विदेश विभाग ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और उसकी सशस्त्र शाखा, मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन (एफटीओ) घोषित किया।

हालाँकि बीएलए को पहले एक विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी इकाई के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, एफटीओ लेबल के कठोर कानूनी परिणाम हैं, जिनमें शामिल हैं:

- सभी प्रकार की सहायता (वित्तीय, भौतिक या रसद) को आपराधिक बनाना

संपत्तियों को ज़ब्त करना

समर्थकों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्तन को सक्षम बनाना

भारत-अमेरिका संबंधों के लिए प्रासंगिकता

पाकिस्तान के सुरक्षा परिवृत्ति के साथ तालमेल

पाकिस्तान लंबे समय से भारत पर बलूच अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगाता रहा है - भारत इन दावों से इनकार करता है। इस्लामाबाद के रुख को दोहराकर, वाशिंगटन को पाकिस्तान के क्षेत्रीय एजेंडे के साथ और अधिक निकटता से जुड़े होने का खतरा है।

भारत के लिए कूटनीतिक जटिलता

बीएलए को आतंकवादी समूह घोषित करने में भारत की अनिष्टा को और अधिक जांच का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उसे अपनी आतंकवाद-रोधी प्रतिबद्धताओं और क्षेत्रीय उग्रवाद पर अपने रुख के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

भू-राजनीतिक संकेत

नए अमेरिका-पाकिस्तान व्यापार और ऊर्जा समझौते के तुरंत बाद, इस पदनाम को दिल्ली में दक्षिण एशिया में अमेरिकी

रणनीतिक प्राथमिकताओं में व्यापक बदलाव के हिस्से के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है।

अमेरिका-पाकिस्तान व्यापार समझौता: एक समानांतर घटनाक्रम

अमेरिका और पाकिस्तान ने हाल ही में एक व्यापार और ऊर्जा सहयोग समझौते की घोषणा की है जिसमें शामिल हैं:

- पाकिस्तान के तेल भंडार का विकास
- अमेरिका को पाकिस्तानी निर्यात पर कम टैरिफ
- ऊर्जा अवसंरचना में निवेश का विस्तार

यह घटनाक्रम वार्षिंगटन द्वारा भारत के विरुद्ध टैरिफ वृद्धि के साथ मेल खाता है, जो ऐसे समय में अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों में अपेक्षाकृत गर्मजोशी का सकेत देता है जब भारत-अमेरिका संबंध बिगड़ रहे हैं।

भारत के वृष्टिकोण से, दिल्ली के विरुद्ध दंडात्मक उपायों और इस्लामाबाद के लिए प्रोत्साहनों का संयोजन क्षेत्र में अमेरिकी नीति के आंशिक पुनर्गठन का संकेत दे सकता है - एक ऐसा कदम जिसके रणनीतिक और प्रतीकात्मक दोनों परिणाम होंगे।

टैरिफ और अमेरिकी घाटा: आर्थिक बहस

अमेरिका में एक संबंधित घरेलू राजनीतिक दावे ने भी ध्यान आकर्षित किया है। वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने तर्क दिया कि ट्रम्प के टैरिफ "संघीय घाटे की भरपाई" कर सकते हैं। तथ्य-जांच से कुछ और ही पता चलता है:

- वर्तमान टैरिफ राजस्व: प्रति माह 30 अरब डॉलर (10 वर्षों में 2.8 ट्रिलियन डॉलर)
- इसी अवधि में अनुमानित घाटा: लगभग 21.8 ट्रिलियन डॉलर
- कर कटौती और खर्च से अतिरिक्त घाटा: लगभग 3.4 ट्रिलियन डॉलर

अर्थशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि केवल टैरिफ ही अमेरिकी राजकोषीय घाटे को कम नहीं कर सकते। इनके नकारात्मक दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं - उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि, व्यापार में मंदी और कुल कर राजस्व में कमी।

घरेलू अमेरिकी राजनीतिक गतिशीलता और विदेश नीति

कुछ विश्लेषक भारत के प्रति अमेरिकी नीति में हाल ही में आई कठोरता को आंशिक रूप से राष्ट्रपति ट्रम्प की राजनीतिक मंशा मानते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने पर उनके कथित ध्यान ने विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित किया है, जिसमें दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की तुलना में प्रतीकात्मक "जीत" को प्राथमिकता दी गई है।

"सफलता का मुख्य आधार !
सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है !!"

इसमें पाकिस्तान तक पहुँच और उच्च-स्तरीय मध्यस्थता के प्रयास शामिल हैं, जबकि भारत नेतृत्व संबंधों में पहले की गर्मजोशी के बावजूद टैरिफ और अन्य दंडात्मक आर्थिक उपायों का सामना कर रहा है।

विश्वास बहाली के संभावित रास्ते

इस गिरावट को दूर करने के लिए कई प्रस्ताव पेश किए गए हैं:

परमाणु ऊर्जा सहयोग

परमाणु परियोजनाओं में 49% तक विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए कानूनी सुधारों में तेजी लाकर और जोखिम-साझाकरण तंत्र को लागू करके, भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए घरेलू स्तर पर रिएक्टर बनाने के अवसर खोल सकता है।

यह 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता के भारत के लक्ष्य का समर्थन करेगा और दोनों पक्षों के लिए एक रणनीतिक "जीत" प्रदान करेगा।

टैरिफ में कमी

संभवतः चरणबद्ध समझौतों के माध्यम से दंडात्मक शुल्कों में पारस्परिक कमी, दोनों पक्षों को अपनी मूल नीतिगत स्थिति छोड़ने के लिए बाध्य किए बिना व्यापार स्थिरता बहाल कर सकती है।

रणनीतिक संचार माध्यम

रक्षा, प्रौद्योगिकी और जलवायु सहयोग पर उच्च-स्तरीय संवादों को पुनर्जीवित करने से सहयोग के संवेदनशील क्षेत्रों को व्यापार विवादों से अलग रखने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष: एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आगे बढ़ना

2025 में भारत-अमेरिका संबंध एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। महत्वाकांक्षी द्विपक्षीय लक्ष्यों के साथ शुरू हुआ यह वर्ष टैरिफ वृद्धि, भिन्न भू-राजनीतिक कदमों और दक्षिण एशिया में अमेरिकी रुख में बदलाव की धारणा के कारण फीका पड़ गया है।

साझेदारी को फिर से पटरी पर लाने के लिए, दोनों पक्षों को लेन-देन के दिखावे से आगे बढ़कर रणनीतिक स्वायत्तता के लिए पारस्परिक सम्मान की ओर बढ़ना होगा। भारत को अपने आर्थिक हितों और क्षेत्रीय नीतियों की रक्षा करनी होगी, जबकि अमेरिका को घरेलू राजनीतिक अनिवार्यताओं को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक स्थिर, विश्वसनीय साझेदार के दीर्घकालिक मूल्य के साथ संतुलित करना होगा।

"जीवन में ऊँचे उठते समय लोगों से अच्छा व्यवहार करें !

क्योंकि यदि आप फिर निचे आये तो सामना इन्हीं लोगों से करना होगा !!"

अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

जीएसटी सुधार - मंत्री समूह ने दो-स्लैब संरचना की सिफारिश की

जीएसटी पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने भारत के कर ढाँचे को सरल बनाने के केंद्र के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसके तहत मौजूदा जीएसटी स्लैब को घटाकर 5% और 18% की दो-स्लैब संरचना में कर दिया जाएगा।

- 5% जीएसटी: आवश्यक और योग्य वस्तुएँ।
- 18% जीएसटी: अधिकांश अन्य वस्तुएँ और सेवाएँ।
- 12% से कम कर वाली लगभग 99% वस्तुएँ 5% कर में बदल जाएँगी, और 28% से कम कर वाली वस्तुओं का एक बड़ा हिस्सा 18% कर में बदल जाएगा।

राजस्व हानि की चिंताएँ

हालाँकि सभी राज्यों ने इस सुधार को "जन-हितैषी निर्णय" बताते हुए इसका समर्थन किया, लेकिन उन्होंने राजस्व हानि को लेकर चिंताएँ भी जताई। चंद्रिमा भट्टाचार्य (वित्त मंत्री, पश्चिम बंगाल) ने ज़ोर देकर कहा कि राज्यों द्वारा राजस्व की हानि नागरिकों को भी प्रभावित करती है। राज्यों ने केंद्र से अंतिम मंजूरी से पहले अपेक्षित राजस्व हानि का अनुमान प्रस्तुत करने को कहा है।

पाप और विलासिता की वस्तुएँ

मंत्रिसमूह ने सिफारिश की कि विलासिता और पाप की वस्तुओं (जैसे पान मसाला, तंबाकू, महंगी कारों) पर 40% कर लागू होता रहे। पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों ने अति-विलासिता वस्तुओं पर कर के बोझ को कम करने के लिए 40% से अधिक अतिरिक्त शुल्क लगाने की संभावना का सुझाव दिया। ऐसे करों को लागू करने के लिए कानूनी संशोधनों की आवश्यकता हो सकती है।

बीमा प्रीमियम छूट

मंत्रिसमूह ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी से छूट का भी प्रस्ताव रखा, जिससे सालाना ₹9,700 करोड़ का राजस्व नुकसान होने का अनुमान है। राज्य सैद्धांतिक रूप से सहमत थे, लेकिन बीमा कंपनियों द्वारा पॉलिसीधारकों को लाभ पहुँचाने के लिए तंत्र की मांग की।

एसएंडपी ने 10 भारतीय वित्तीय संस्थानों की रेटिंग में सुधार किया

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने 18 वर्षों में पहली बार भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया है।

- नई सॉवरेन रेटिंग: 'बीबीबी/स्थिर/ए-2' (पहले 'बीबीबी-/सकारात्मक/ए-3')।
- कारण: मज़बूत आर्थिक बुनियाद, नीतिगत सुधार और बेहतर वित्तीय स्थिरता।

वित्तीय संस्थानों का उन्नयन

7 प्रमुख बैंक:

1. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)

2. आईसीआईसीआई बैंक
3. एचडीएफसी बैंक
4. एक्सिस बैंक
5. कोटक महिंद्रा बैंक
6. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
7. इंडियन बैंक

3 एनबीएफसी:

1. बजाज फाइनेंस
2. टाटा कैपिटल
3. एलएंडटी फाइनेंस

उन्नयन क्यों?

- कई भारतीय वित्तीय संस्थानों की रेटिंग सॉवरेन रेटिंग से निकटता से जुड़ी हुई हैं।
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के कारण दबावप्रस्त ऋणों की बेहतर वसूली:
- समाधान अवधि 6-8 वर्ष से घटकर 2 वर्ष से भी कम हो गई।
- वसूली मूल्यों में उल्लेखनीय सुधार हुआ।
- वित्त वर्ष 22-24 में भारत की अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि दर 8.8% रही, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेज़ है।
- अनुमानित वृद्धि: अगले 3 वर्षों के लिए 6.8% वार्षिक।
- मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं का बेहतर प्रबंधन, स्थिरता सुनिश्चित।

पहले अपग्रेड की गई अन्य संस्थाएँ:

सार्वजनिक क्षेत्र और कॉर्पोरेट संस्थाएँ:

- ONGC, NTPC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, टाटा पावर ('BBB' में अपग्रेड)।
- एक्जिम बैंक, IRFC (रेटिंग भी अपग्रेड)।

मुख्य बातें:

- 18 वर्षों में पहली बार सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड।
- 10 वित्तीय संस्थानों (7 बैंक + 3 NBFC) का अपग्रेड।
- संरचनात्मक सुधारों, आर्थिक विकास और वित्तीय क्षेत्र के बेहतर लचीलेपन से जुड़ा।

RBI ने रेपो दर को 5.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा, तटस्थ रुख बरकरार

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने घोषणा की कि मौद्रिक नीति समिति ने "तटस्थ" मौद्रिक नीति रुख पर कायम रहते हुए रेपो दर को 5.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है।

नीतिगत दरों पर एक नज़र

- नीतिगत रेपो दर: 5.50%
- स्थायी जमा सुविधा दर: 5.25%
- सीमांत स्थायी सुविधा दर: 5.75%
- बैंक दर: 5.75%
- स्थायी रिवर्स रेपो दर: 3.35%

- CRR: 4.00%
- SLR: 18.00%

निर्णय के पीछे तर्क

समाइ आर्थिक स्थितियों और विकास-मुद्रास्फीति गतिशीलता का विस्तृत मूल्यांकन।

तटस्थ रुख का अर्थ है:

कोई अतिरिक्त तरलता प्रोत्साहन नहीं।

कोई सख्त उपाय नहीं। मुद्रास्फीति नियंत्रण को विकास समर्थन के साथ संतुलित करने के उद्देश्य से।

मुद्रास्फीति और विकास की संभावना

कुल मिलाकर मुद्रास्फीति में गिरावट आई है, लेकिन खाद्य पदार्थों, खासकर सब्जियों, की कीमतों में उत्तर-चढ़ाव बना हुआ है।

मुख्य मुद्रास्फीति लगभग 4% पर स्थिर है।

पिछले नीतिगत कदम

- 6 जून: रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती की गई (6% से 5.5%)।
- नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए सीआरआर (नकद आरक्षित अनुपात) में 100 आधार अंकों की कटौती की गई।
- फरवरी 2025 से, रेपो दर में कुल 100 आधार अंकों की कटौती की गई है।

IRDAI ने पॉलिसीबाज़ार पर ₹5 करोड़ का जुर्माना लगाया

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने पॉलिसीबाज़ार वेब एप्रीगेट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका नाम अब पॉलिसीबाज़ार इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड हो गया है, पर ₹5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई बीमा अधिनियम, 1938 और अन्य संबंधित नियमों व विनियमों के उल्लंघन के लिए की गई है। IRDAI ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत यह जुर्माना लगाया है। जुर्माने के साथ, IRDAI ने कंपनी को एक निर्देश, सलाह और चेतावनी भी जारी की है।

नियामक ने कई नियामक खामियों का हवाला दिया है जिनके कारण यह दंडात्मक कार्रवाई आवश्यक हो गई।

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण

- स्थापना: 2000 (आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अंतर्गत)
- मुख्यालय: हैदराबाद, तेलंगाना
- प्रकार: वित्त मंत्रालय के अधीन वैधानिक निकाय
- अध्यक्ष: देबाशीष पांडा

RBI ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के सारस्वत बैंक में विलय को मंजूरी दी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने निम्नलिखित के स्वैच्छिक विलय को मंजूरी दे दी है:

- न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (NICBL), मुंबई
- सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई

अनुमोदन बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44A(4) सहपठित धारा 56 के अंतर्गत लागू किया गया है।

- परिचालन परिवर्तन: NICBL की सभी शाखाएँ प्रभावी तिथि से सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बारे में

- विरासत: 100 वर्ष से अधिक पुराना; भारत का सबसे बड़ा शहरी सहकारी बैंक

शाखा नेटवर्क (31 मार्च, 2025 तक):

- 312 शाखाएँ, 303 एटीएम
- 8 राज्यों में फैला: महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश

भारत के सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों पर एक नज़र:

संस्थान	2025	2026
नोमुरा	6.2%	—
गोल्डमैन सैक्स	6.5%	6.4%
आईएमएफ	6.7%	6.4%

भारत-ओमान मुक्त व्यापार समझौता खाड़ी देशों के साथ नए आर्थिक द्वार खोलेगा

भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर हस्ताक्षर प्रस्तावित।

कार्यक्षेत्र: वस्तुएँ, सेवाएँ, निवेश और श्रम गतिशीलता।

महत्व:

- दक्षिण एशिया और खाड़ी देशों के बीच एक रणनीतिक आर्थिक सेतु का निर्माण।
- एक महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार और सुरक्षा क्षेत्र में भारत की भू-राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करता है।
- खाड़ी देशों में चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव का मुकाबला करता है।

मुख्य विशेषताएँ:

शुल्क में कमी:

- लौह एवं इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, प्लास्टिक, ऑटोमोटिव कलपुर्जे और मशीनरी जैसे भारतीय निर्यातों पर 5% सीमा शुल्क की समाप्ति - प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और मेक इन इंडिया लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाना।
- ओमान से कच्चे तेल, एलएनजी और उर्वरकों के आयात की लागत कम करना, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना।

निवेश और बुनियादी ढाँचा:

भारतीय बुनियादी ढाँचे (बंदरगाह, औद्योगिक गलियारे, लॉजिस्टिक्स केंद्र) में खाड़ी पूँजी प्रवाह को प्रोत्साहित करता है।

दुक्कम बंदरगाह जैसी ओमानी परियोजनाओं में भारत को भागीदारी के अवसर प्रदान करता है, जिससे समुद्री संपर्क में सुधार होता है।

श्रम गतिशीलता:

ओमान में कार्यरत 4.8 लाख से अधिक भारतीय प्रवासियों के हितों की रक्षा के लिए ओमान की "ओमानीकरण" नीति के विरुद्ध सुरक्षा उपायों पर बातचीत की गई।

रणनीतिक महत्व:

होमर्ज जलडमरुमध्य (वैश्विक तेल शिपमेंट का 20% यहीं से होकर गुजरता है) से ओमान की निकटता समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग की संभावनाओं को बढ़ाती है।

ओमान:

- राजधानी: मस्कट
- मुद्रा: ओमानी रियाल (ओएमआर)
- वर्तमान सुल्तान: हैथम बिन तारिक अल सईद (जनवरी 2020 से)
- भूगोल: अरब प्रायद्वीप के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित; संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और यमन की सीमाएँ; अरब सागर और ओमान की खाड़ी के साथ तटरेखा।
- प्रमुख बंदरगाह: सुल्तान कबूस बंदरगाह, सलालाह बंदरगाह, दुक्कम बंदरगाह।
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध: जीसीसी (खाड़ी सहयोग परिषद), अरब लीग, संयुक्त राष्ट्र और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य।

प्रधानमंत्री मोदी और ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुईज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की और भारत-ब्राज़ील रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने अपनी ब्राज़ील यात्रा को याद करते हुए द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक प्रगति पर प्रकाश डाला।

भारत-ब्राज़ील संबंधों के बारे में मुख्य तथ्य

- राजनयिक संबंध: 1948 में स्थापित।
- रणनीतिक साझेदारी: 2006 में इस स्तर तक पहुँची।
- बहुपक्षीय मंच: दोनों ब्रिक्स, जी20, आईबीएसए, बैसिक और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं।
- व्यापार: ब्राज़ील को भारत द्वारा किए जाने वाले प्रमुख निर्यातों में डीज़ल, दवाइयाँ और रसायन शामिल हैं; आयातों में कच्चा तेल, चीनी और खाद्य तेल शामिल हैं।
- रक्षा सहयोग: इसमें प्रौद्योगिकी साझा करना और संयुक्त अभ्यास करना शामिल है।
- कृषि सहयोग: अनुसंधान, प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान और सतत कृषि पर केंद्रित।

ब्राज़ील:

ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा और दुनिया का पाँचवाँ सबसे बड़ा देश है।

- मुद्रा: ब्राज़ीलियन रियल (BRL)।
- राजधानी: ब्रासीलिया।

टाटा मोटर्स 38,240 करोड़ रुपये के सौदे में इतालवी कंपनी इवेको ग्रुप एनवी का अधिग्रहण करेगी।

टाटा मोटर्स इतालवी वाणिज्यिक वाहन निर्माता इवेको ग्रुप का अधिग्रहण करेगी, जिसमें उसका रक्षा व्यवसाय शामिल नहीं होगा।

मुख्य विशेषताएँ:

सौदे का अवलोकन:

- लक्ष्य: इवेको ग्रुप एन.वी. (रक्षा व्यवसाय को छोड़कर)
- सौदे का मूल्य: €3.8 बिलियन (लगभग ₹38,240 करोड़)
- प्रकार: पूर्णतः नकद स्वैच्छिक निविदा प्रस्ताव
- अनुमोदन स्थिति: टाटा मोटर्स के बोर्ड की कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित

रणनीतिक महत्व:

- उद्देश्य: मजबूत पहुँच, उत्पाद विविधता और औद्योगिक क्षमता के साथ एक वैश्विक वाणिज्यिक वाहन अग्रणी कंपनी बनाना
- ऑटोमोटिव क्षेत्र में टाटा मोटर्स का अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण
- पिछला सबसे बड़ा: जगुआर लैंड रोवर \$2.3 बिलियन (2008) में
- कुल मिलाकर, कोरस स्टील (\$12) के बाद टाटा समूह द्वारा दूसरा सबसे बड़ा अधिग्रहण अरब, 2007।

शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान भारतीय परिवारिक व्यवसाय 2025

अंबानी परिवार लगातार दूसरे वर्ष बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरुन इंडिया के सबसे मूल्यवान परिवारिक व्यवसायों की 2025 सूची में शीर्ष पर बना हुआ है, जिसका मूल्यांकन ₹28.23 लाख करोड़ है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग बारहवां हिस्सा है।

बिड़ला और जिंदल परिवार शीर्ष 3 में

कुमार मंगलम बिड़ला परिवार ₹6.47 लाख करोड़ के मूल्यांकन के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि जिंदल परिवार ₹5.71 लाख करोड़ के साथ पहली बार शीर्ष तीन में शामिल हुआ। कुल मिलाकर, शीर्ष तीन व्यावसायिक घरानों का कुल मूल्य ₹40.4 लाख करोड़ है, जो फिलीपींस के सकल घरेलू उत्पाद के बराबर है।

नए प्रवेशक और पहली पीढ़ी के नेता

एक उल्लेखनीय नया प्रवेशक अनिल अग्रवाल का परिवार है, जो ₹2.55 लाख करोड़ के साथ नौवें स्थान पर है। अडानी परिवार ₹14 लाख करोड़ के साथ पहली पीढ़ी के व्यवसाय श्रेणी में अग्रणी

बना हुआ है, उसके बाद पूनावाला परिवार ₹2.3 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है।

गैर-सूचीबद्ध कंपनियाँ

गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में, हल्दीराम परिवार ने ₹85,800 करोड़ के साथ लगातार दूसरे वर्ष सबसे मूल्यवान कंपनी का स्थान बरकरार रखा है।

शीर्ष व्यवसायों की संयुक्त संपत्ति

शीर्ष 300 पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसायों की संयुक्त संपत्ति 1.6 ट्रिलियन डॉलर (₹134 लाख करोड़) है, जो तुर्की और फ़िनलैंड के संयुक्त सकल घेरेलू उत्पाद से भी अधिक है।

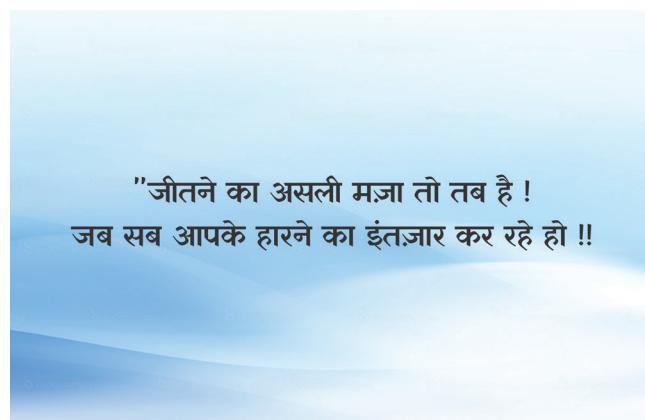
भारत के शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय (2025)

1. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड - अंबानी परिवार - ₹28,23,100 करोड़
2. आदित्य बिड़ला समूह - कुमार मंगलम बिड़ला परिवार - ₹6,47,700 करोड़
3. जेएसडब्ल्यू समूह - जिंदल परिवार - ₹5,70,900 करोड़
4. बजाज समूह - बजाज परिवार - ₹5,64,200 करोड़
5. महिंद्रा समूह - महिंद्रा परिवार - ₹5,43,800 करोड़
6. एचसीएल - नादर परिवार - ₹4,68,900 करोड़
7. चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस - मुरुगप्पा परिवार - ₹2,92,400 करोड़
8. विप्रो - प्रेमजी परिवार - ₹2,78,600 करोड़
9. हिंदुस्तान जिंक - अनिल अग्रवाल परिवार - ₹2,55,000 करोड़
10. एशियन पेंट्स - दानी, चौकसी और वकील परिवार - ₹2,20,900 करोड़

इंडोनेशिया-न्यूज़ीलैंड व्यापक साझेदारी 2025-2029

न्यूज़ीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैक्ले की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने इंडोनेशिया-न्यूज़ीलैंड व्यापक साझेदारी कार्य योजना 2025-2029 के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने पर सहमति व्यक्त की, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करना है।

व्यापार एवं निवेश सहयोग



इंडोनेशिया के आर्थिक मामलों के समन्वय मंत्री एयरलांगा हार्ट्ट और मंत्री मैक्ले ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा की, जिसमें बागवानी उत्पादों, पशुओं और पशु उत्पादों पर चल रहे विश्व व्यापार संगठन के विवादों को सुलझाने पर विशेष ध्यान दिया गया। यह प्रस्ताव दोनों देशों को रणनीतिक आर्थिक सहयोग के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाएगा।

क्षेत्रीय सहयोग

इंडोनेशिया ने खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक पोषण को बढ़ावा देने के लिए डेयरी प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए न्यूज़ीलैंड को आमंत्रित किया, और मैक्ले ने इन आवश्यकताओं को स्थायी रूप से पूरा करने की न्यूज़ीलैंड की क्षमता की पुष्टि की।

अद्यतन व्यापार लक्ष्य

नई योजना के तहत, द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को 2029 तक 6 बिलियन NZD तक संशोधित किया गया है, जो पहले 2024 तक 4 बिलियन NZD के लक्ष्य से बढ़कर 2029 तक 6 बिलियन NZD हो गया है, जो मज़बूत आर्थिक संबंधों के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इंडोनेशिया:

- राजधानी - जकार्ता
- मुद्रा - इंडोनेशियाई रुपिया (IDR)
- राष्ट्रपति - जोको विडोडो (2025 तक)
- भूगोल - दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपसमूह राष्ट्र, 17,000 से ज्यादा द्वीप।
- प्रमुख धर्म - इस्लाम (दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी)।
- अर्थव्यवस्था - G20 का सदस्य, पाम ऑयल, कोयला और रबर का प्रमुख निर्यातक।

न्यूज़ीलैंड:

राजधानी - वेलिंगटन

- मुद्रा - न्यूज़ीलैंड डॉलर (NZD)
- प्रधानमंत्री - क्रिस्टोफर लक्सन (2025 तक)
- भूगोल - दो मुख्य द्वीप (उत्तर और दक्षिण) और कई छोटे द्वीप।
- प्रमुख धर्म - ईसाई धर्म (सबसे बड़ा), लेकिन गैर-धार्मिक जनसंख्या भी बढ़ रही है।
- अर्थव्यवस्था - डेयरी उत्पादों, मांस और शराब का प्रमुख निर्यातक; मज़बूत पर्यटन क्षेत्र।

"यदि मज़िल न मिले तो रास्ते बदलो !
क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियाँ बदलते हैं जड़े नहीं !!"

रक्षा एवं सुरक्षा

डीआरडीओ ने एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (आईएडीडब्ल्यूएस) का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ओडिशा तट से एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (आईएडीडब्ल्यूएस) का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय सशस्त्र बलों और रक्षा उद्योग को बधाई दी।

आईएडीडब्ल्यूएस एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें शामिल हैं:

- त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (क्यूआरएसएम)
- अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली (वीएसएचओआरएडीएस)
- लेज़र-आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार

परीक्षण के दौरान, तीन हवाई लक्ष्यों - जिनमें उच्च गति वाले यूएवी और एक बहु-कॉर्टर ड्रोन शामिल थे - को अलग-अलग दूरी और ऊँचाई पर क्यूआरएसएम, वीएसएचओआरएडीएस और लेज़र हथियारों द्वारा एक साथ निशाना बनाया गया और नष्ट कर दिया गया। इस परीक्षण ने चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेज (आईटीआर) में निगरानी की गई मिसाइल प्रणालियों, ड्रोन पहचान और विनाश प्रणालियों, रडार, संचार और कमांड-एंड-कंट्रोल प्रणालियों के दोषरहित संचालन की पुष्टि की। इस उड़ान परीक्षण ने भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमता को स्थापित किया है, जिससे दुश्मन के हवाई खतरों के विरुद्ध महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की क्षेत्रीय रक्षा मज़बूत हुई है।

मुख्य संदर्भ और घटनाक्रम:

- अप्रैल 2025 में, भारत ने ड्रोन, स्वार्म ड्रोन और निगरानी उपकरणों को निष्क्रिय करने में सक्षम अपने स्वदेशी रूप से विकसित लेज़र हथियार का परीक्षण किया, जिससे वह ऐसी तकनीक वाले अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी और इजराइल जैसे विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया।
- आईएडीडब्ल्यूएस के लिए केंद्रीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (डीआरडीएल), हैदराबाद द्वारा किया गया था।

मिशन सुदर्शन चक्र: प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषित, इस मिशन का उद्देश्य महाभारत के सुदर्शन चक्र से प्रेरित एक शक्तिशाली रक्षा कवच का निर्माण करना है। भारत की दीर्घकालिक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के तहत 2035 तक इसका विस्तार और आधुनिकीकरण किया जाएगा।

आकाशतीर प्रणाली: 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025) के दौरान हाल ही में प्रदर्शित की गई। आकाशतीर ने कई पाकिस्तानी हवाई खतरों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने

में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एकीकृत वायु कमान एवं नियंत्रण प्रणाली (IACCS) के साथ मिलकर काम किया।

ध्यान देने योग्य बातें

- DRDO मुख्यालय: नई दिल्ली; 1958 में स्थापित; वर्तमान अध्यक्ष - डॉ. समीर वी. कामत।
- एकीकृत परीक्षण रेज (ITR), चांदीपुर: ओडिशा; मिसाइल और वायु रक्षा परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण स्थल।
- QRSAM: रेज - लगभग 25-30 किमी; हवाई खतरों के खिलाफ त्वरित तैनाती के लिए डिज़ाइन किया गया।
- VSHORADS: 6-7 किमी की रेज वाली मानव-पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली।
- निर्देशित ऊर्जा हथियार (DEW): दुश्मन के ठिकानों को निष्क्रिय/नष्ट करने के लिए उच्च-ऊर्जा लेज़रों का उपयोग करते हैं।
- भारत का वायु रक्षा ग्रिड: चार-स्तरीय, जिसमें आकाशतीर, IACCS, मिसाइल प्रणालियाँ और DEW शामिल हैं।

ऑस्ट्रेलिया और जापान ने स्टील्ट फ्रिगेट के लिए अब तक के सबसे बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए

ऑस्ट्रेलिया और जापान ने अब तक के सबसे बड़े द्विपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

- मुख्य परिणाम: ऑस्ट्रेलिया जापान की मिस्त्रिबिशी हेवी इंडस्ट्रीज से 11 मोगामी-श्रेणी के उन्नत स्टील्ट फ्रिगेट खरीदेगा।

विशिष्टताएँ:

- लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता वाले स्टील्ट युद्धपोत
- परिचालन सीमा: 10,000 समुद्री मील तक (वर्तमान एंजैक-श्रेणी की 6,000 की तुलना में)

महत्व:

- इस समझौते का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक क्षमताओं को मज़बूत करना है
- ऑस्ट्रेलिया-जापान रक्षा सहयोग में एक रणनीतिक मील का पत्थर माना जाता है
- यह भारत-प्रशांत भागीदारों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को दर्शाता है

ऑस्ट्रेलिया

- राजधानी: कैनबरा
- प्रमुख शहर: सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ
- स्थान: दक्षिणी गोलार्ध, हिंद और प्रशांत महासागरों से घिरा
- प्रधानमंत्री: एंथनी अल्बानीज़
- मुद्रा: ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD)

जापान

- राजधानी: टोक्यो
- प्रमुख द्वीप: होन्शू, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू

- "उगते सूरज की भूमि" के रूप में जाना जाता है
 - राजा: सम्राट नारुहितो
 - प्रधानमंत्री: फुमियो किशिदा
 - मुद्रा: जापानी येन (JPY)
- ऑस्ट्रेलिया-जापान संबंध**
- मज़बूत रणनीतिक, रक्षा और व्यापारिक संबंध
 - दोनों QUAD सदस्य हैं
 - 2022: रक्षा सहयोग के लिए पारस्परिक पहुँच समझौते (RAA) पर हस्ताक्षर

ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने AUKUS के तहत 50 साल की जिलॉना संधि पर हस्ताक्षर किए

ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम (यूके) ने AUKUS रक्षा संधि के लिए 50 साल की प्रतिबद्धता पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि अमेरिका इस संधि की समीक्षा कर रहा है।

जिलॉना संधि के बारे में:

- संधि का केंद्रबिंदु: AUKUS संभूति के अंतर्गत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग
- नाम: परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी साझेदारी और सहयोग संधि (जिलॉना संधि)

संधि के प्रमुख प्रावधान

निम्नलिखित पर पूर्ण-स्पेक्ट्रम सहयोग:

SSN-AUKUS पनडुब्बियों का डिज़ाइन, निर्माण, संचालन, रखरखाव और निपटान

विकास:

- कुशल कार्मिक
- कार्यबल और अवसंरचना
- ऑस्ट्रेलिया के SSN-AUKUS कार्यक्रम के लिए नियामक प्रणालियाँ

सक्षम बनाता है:

HMAS स्टर्लिंग (पनडुब्बी धूर्णन बल-पश्चिम) में ब्रिटेन की एस्ट्रूट-श्रेणी की पनडुब्बी की धूर्णन उपस्थिति

बंदरगाहों का दौरा और रसद सहायता

संदर्भ: अमेरिका की भूमिका समीक्षाधीन

अमेरिकी रक्षा विभाग ने "अमेरिका फ़र्स्ट" रणनीति के साथ सरेखण का आकलन करते हुए AUKUS की समीक्षा शुरू की है।

दीर्घकालिक AUKUS प्रतिबद्धताओं पर अमेरिका का रुख अनिश्चित बना हुआ है।

संयुक्त वक्तव्य की मुख्य विशेषताएँ (मार्लेस और हीली):

यह संधि AUKUS के अंतर्गत ब्रिटेन-ऑस्ट्रेलिया की 50-वर्षीय प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह अमेरिका के साथ त्रिपक्षीय सहयोग पर आधारित है। यह लचीली त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण का समर्थन करती है।

विवाद और चिंताएँ:

ऑस्ट्रेलिया एक गैर-परमाणु-हथियार संपन्न देश है; परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रमों में इसकी भूमिका ने निम्नलिखित प्रश्न उठाए हैं:

परमाणु अप्रसार संबंधी चिंताएँ

क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के प्रश्न

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संभावित सैन्य वृद्धि पर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना।

वित्तीय प्रतिबद्धता:

ऑस्ट्रेलिया ने AUKUS पनडुब्बी सौदे के तहत अमेरिका को 800 मिलियन AUD (लगभग 525.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का दूसरा भुगतान किया।

भारतीय नौसेना दो स्टील्यु फ्रिगेट - उदयगिरि और हिमगिरि - को कमीशन करेगी

भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में प्रोजेक्ट 17A के दो उन्नत स्टील्यु फ्रिगेट - उदयगिरि (F35) और हिमगिरि (F34) - को कमीशन करेगी। यह दो अलग-अलग भारतीय शिपयार्डों से दो प्रमुख सतही लड़ाकू जहाजों का एक साथ कमीशन होने वाला पहला जहाज होगा।

जहाज निर्माता

➤ उदयगिरि: दूसरा P17A फ्रिगेट, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL), मुंबई द्वारा निर्मित। यह नौसेना के युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किया गया 100वाँ जहाज भी है।

➤ हिमगिरि: गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता द्वारा निर्मित पहला P17A फ्रिगेट।

तकनीकी विशिष्टताएँ और विशेषताएँ

➤ विस्थापन: लगभग 6,700 टन (शिवालिक-श्रेणी से बड़ा)।

➤ पतवार डिज़ाइन: रडार क्रॉस-सेक्शन को कम करने के लिए सुधारा गया।

➤ प्रणोदन: संयुक्त डीज़ल या गैस (CODOG) प्रणाली - डीज़ल इंजन + गैस टर्बाइन, एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली (IPMS) द्वारा नियंत्रित।

आयुध:

➤ सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें

➤ मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें

➤ 76 मिमी मध्यम दूरी की तोप

➤ 30 मिमी और 12.7 मिमी निकट-अंतर हथियार प्रणालियाँ

➤ पनडुब्बी-रोधी और पानी के भीतर काम करने वाले हथियार।

स्वदेशी योगदान

200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के सहयोग से निर्मित, लगभग 4,000 प्रत्यक्ष और 10,000 अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित।

हाल ही में नौसेना में शामिल (2025)

➤ विध्वंसक: INS सूरत

➤ फ्रिगेट: INS नीलगिरि

➤ पनडुब्बी: INS वाघशीर

➤ ASW उथले पानी का जहाज: INS अनर्ला

➤ गोताखोरी सहायता पोत: INS निस्तार

परीक्षण और तैयारी

उदयगिरि और हिमगिरि दोनों ने सफलतापूर्वक समुद्री परीक्षण पूरे कर लिए हैं, जिससे उनके पतवार, मशीनरी और युद्ध प्रणालियों का सत्यापन हो गया है।

भारतीय दूत को स्पेन में अंतिम 16 एयरबस C-295 सैन्य परिवहन विमान प्राप्त हुए

भारत को स्पेन से एयरबस C-295 सैन्य परिवहन विमान की अंतिम (16वीं) इकाई प्राप्त हुई। इसके साथ ही भारत को एयरबस की फ्लाईअवे डिलीवरी की प्रतिबद्धता पूरी हो गई।

C-295 एक सामरिक परिवहन विमान है जिसमें:

- 5-10 टन पेलोड क्षमता
- आधुनिक एवियोनिक्स
- 11 घंटे तक की उड़ान क्षमता
- कई सैन्य अभियानों (सैनिक परिवहन, कार्गो, एयरड्रॉप, मेडिक, आदि) के लिए उपयुक्त
- C-295 भारतीय वायु सेना (IAF) के पुराने एवरो विमान बेड़े की जगह लेगा।

अनुबंध अवलोकन

- कुल हस्ताक्षरित अनुबंध: सितंबर 2021
- कुल ऑर्डर किए गए विमान: 56 C-295MW विमान
- 16 विमान स्पेन से उड़ान भरने की स्थिति में वितरित किए जाएँगे
- 40 विमान टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) द्वारा भारत में निर्मित किए जाएँगे

इस कार्यक्रम को एयरोस्पेस निर्माण में आमनिर्भरता को बढ़ावा देने वाले एक ऐतिहासिक रक्षा सहयोग के रूप में देखा जा रहा है।

तुर्की ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर-परमाणु बम 'गजैप' का अनावरण किया

तुर्की ने अपने दो सबसे उन्नत विमान बम विकसित किए हैं, जो उसकी सैन्य प्रहार क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार दर्शाते हैं।

अवलोकन:

- विकसितकर्ता: तुर्की के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान एवं विकास केंद्र
- अनावरण: 17वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले में
- प्रमाणन: दोनों बम योग्यता और प्रमाणन प्रक्रियाओं से गुज़रे हैं
- उद्देश्य: उन्नत हवाई हथियारों से प्रहार क्षमताओं को बढ़ाना
- संगत विमान: तुर्की के F-16 और F-4 लड़ाकू विमान; भविष्य में ड्रोन तैनाती की योजना

गजैप (क्रोध) बम:

- वज़न: 970 किलोग्राम (2,000 पाउंड)
- प्रकार: संशोधित MK-84 विखंडन बम

विखंडन क्षमता:

- 10,000 स्टील के टुकड़े छोड़ता है
- 1 किमी के दायरे में बिखरता है

- प्रति वर्ग मीटर 10.16 टुकड़े — मानक MK-श्रृंखला बमों से 3 गुना अधिक शक्तिशाली

ह्यालेट (घोस्ट) बम:

इसे NEB-1 / NEB-2 के नाम से भी जाना जाता है

प्रकार: उन्नत बंकर-बस्टर

भेदन:

- C50 कंक्रीट में 7 मीटर (मानक 1.8-2.4 मीटर के विपरीत)
- चट्टान/पृथ्वी में 90 मीटर तक प्रवेश किया
- प्रबलित स्टील, रेत, कंक्रीट में प्रवेश किया और विस्फोट के बाद 600 मीटर तक यात्रा की परीक्षण किया गया; कृत्रिम किलेबंद वातावरण में तैनाती और रणनीति:
- भविष्य में उपयोग: विकासाधीन ड्रोन के साथ एकीकरण
- तकनीक महत्व: तुर्की की स्वदेशी मारक क्षमताओं को बढ़ावा देता है

भारतीय तटरक्षक बल का तीव्र गश्ती पोत 'अटल' गोवा में लॉन्च किया गया

भारतीय तटरक्षक बल का छठा स्वदेश निर्मित तीव्र गश्ती पोत (FPV), 'अटल', गोवा शिप्यार्ड लिमिटेड (GSL), गोवा में लॉन्च किया गया।

ICGS 'अटल' तीव्र गश्ती पोत (FPV) का लॉन्च:

श्री रोजी अग्रवाल, IDAS, PIFA (तटरक्षक मुख्यालय) की उपस्थिति में श्रीमती शिल्पा अग्रवाल द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य: तटीय सुरक्षा, तस्करी विरोधी और खोज एवं बचाव में भारतीय तटरक्षक बल की क्षमता को बढ़ाना।

'अटल' FPV की मुख्य विशेषताएँ:

- स्वदेशी सामग्री: 60% से अधिक घटक घरेलू स्तर पर प्राप्त किए गए हैं।
- डिज़ाइन: तटरक्षक बल की ज़रूरतों के लिए GSL द्वारा पूरी तरह से आंतरिक रूप से डिज़ाइन किया गया।
- बेड़े की भूमिका: GSL में निर्माणाधीन 8 FPV की श्रृंखला में छठा।

भारतीय तटरक्षक बल: बेड़ा और विकास:

- स्थापना: 1977 में 7 प्लेटफॉर्म के साथ।
- वर्तमान क्षमता: 151 जहाज और 76 विमान।
- 2030 का लक्ष्य: 200 जहाज और 100 विमान।
- संचालन आदर्श वाक्य: "वर्यं रक्षामः" (हम रक्षा करते हैं)।

माह के रक्षा/सैन्य अभ्यास

SLINEX-25

द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास SLINEX-25 (श्रीलंका-भारत नौसैनिक अभ्यास) का 12वां संस्करण पश्चिमी जलक्षेत्र में कोलंबो के तट पर अपने समुद्री चरण में प्रवेश कर गया।

भाग लेने वाले जहाज़:

➤ भारतीय नौसेना: बेड़े का टैंकर आईएनएस ज्योति, विधंसक आईएनएस राणा

➤ श्रीलंका नौसेना: एसएलएनएस विजयबाहु, एसएलएनएस संयुक्त

समुद्री चरण की गतिविधियाँ:

- भ्रमण, बोर्डिंग, खोज और जब्ती (वीबीएसएस) संचालन
- तोपखाना और स्क्रीनिंग अभ्यास
- ऊर्ध्वाधर पुनःपूर्ति
- फ्लैशिंग अभ्यास
- ईंधन भरने के रास्ते

बंदरगाह चरण (कोलबो बंदरगाह):

- संचार और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर संयुक्त ब्रीफिंग
- श्रीलंका वायु सेना के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान और हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण
- खेल प्रतियोगिताएँ, योग सत्र और सांस्कृतिक आदान-प्रदान
- नौसैनिक अभियानों का प्रदर्शन करने के लिए स्कूली बच्चों के लिए जहाज का दौरा

अतिरिक्त:

- एसएलआईएनईएक्स पहली बार आयोजित: 2005
- आवृत्ति: द्विवार्षिक अभ्यास (प्रत्येक दो वर्ष में एक बार)
- उद्देश्य: भारतीय और श्रीलंकाई नौसेनाओं के बीच अंतर-संचालन, समुद्री सुरक्षा सहयोग और आपसी समझ को बढ़ाना।
- आईएनएस ज्योति: बेड़े पुनःपूर्ति टैंकर, 1996 में कमीशन किया गया; नौसेना के बेड़े को रसद सहायता प्रदान करता है।
- आईएनएस राणा: राजपूत श्रेणी का विधंसक, 1982 में कमीशन किया गया; यह वायु-रोधी, पनडुब्बी-रोधी और सतह-रोधी युद्ध के लिए सुसज्जित है।
- एसएलएनएस संयुक्त: पूर्व भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत, 1994 में श्रीलंका को हस्तांतरित किया गया।
- एसएलएनएस विजयबाहु: पूर्व अमेरिकी तटरक्षक कटर शेरमेन, 2019 में श्रीलंका को हस्तांतरित किया गया।
- महत्व: भारत के सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) दृष्टिकोण को मजबूत करता है, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री कूटनीति का समर्थन करता है।

अन्य भारत-श्रीलंका अभ्यास:

मित्र शक्ति

- प्रकार: द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास
- पहली बार आयोजित: 2013
- आवृत्ति: वार्षिक
- फोकस: उग्रवाद-रोधी और आतंकवाद-रोधी अभियान, सैन्य सहयोग को बढ़ाना।

दोस्ती (मालदीव के साथ भी)

- प्रकार: त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास (भारत-श्रीलंका-मालदीव)
- पहली बार आयोजित: 1991
- आवृत्ति: द्विवार्षिक

- फ़ोकस: समुद्री खोज एवं बचाव, प्रदूषण नियंत्रण और मानवीय सहायता।
- P-8I समुद्री गश्ती एवं पनडुब्बी रोधी प्रशिक्षण (कभी-कभार, नियमित नहीं)
- समुद्री क्षेत्र जागरूकता और निगरानी सहयोग के लिए संयुक्त रूप से आयोजित।

सिम्बेक्स

पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक संदर्भ

सिंगापुर-भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास (सिम्बेक्स) का 32वां संस्करण 1 अगस्त, 2025 को संपन्न हुआ।

1994 में पहली बार शुरू किया गया,

सिम्बेक्स:

किसी भी देश के साथ भारत का सबसे लंबा निरंतर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। सिंगापुर के लिए सबसे लंबे समय तक चलने वाले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यासों में से एक।

रणनीतिक समय

सिम्बेक्स 2025 का आयोजन भारत और सिंगापुर के राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया था। यह दोनों देशों के बीच मजबूत होते रक्षा सहयोग को दर्शाता है। यह अक्टूबर 2024 में द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण समझौते के अगले पाँच वर्षों के लिए नवीनीकरण के साथ मेल खाता है।

अभ्यास स्थल

- तटीय चरण: आरएसएस सिंगापुर-चांगी नौसैनिक अड्डे पर आयोजित।
- समुद्री चरण: दक्षिण दक्षिण चीन सागर में आयोजित।
- भारत-सिंगापुर रक्षा अभ्यास पर एक नज़र

अभ्यास का नाम	प्रकार	प्रतिभागी	प्रारंभ	फोकस क्षेत्र
SIMBEX (सिंगापुर-भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास)	नौसेना	भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना	1994	नौसेना युद्ध, समुद्री सुरक्षा, वायु/सतह/उप-सतह संचालन
बोल्ड कुरुक्षेत्र	सेना	भारतीय सेना और सिंगापुर सेना	2005	कमांड पोस्ट अभ्यास, संयुक्त युद्ध योजना
संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण (JMT)	वायु सेना	भारतीय वायु सेना और सिंगापुर गणराज्य की वायु सेना	2007	वायु युद्ध, सामरिक अभ्यास, अंतर-संचालन

अभ्यास का नाम	प्रकार	प्रतिभागी	प्रारंभ	फोकस क्षेत्र
त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास (भारत-सिंगापुर-थाईलैंड)	नौसेना (बहुपक्षीय)	भारतीय नौसेना, RSN, रॉयल थाई नौसेना	2019	समुद्री समुद्री विरोधी, सुरक्षा, डकैती हिंदु-प्रशांत क्षेत्र में समन्वय

दिव्य दृष्टि अभ्यास

भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊँचाई वाले क्षेत्रों में 'दिव्य दृष्टि अभ्यास' का आयोजन किया ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से लैस सेंसर और ड्रोन सहित नई तकनीकों का परीक्षण किया जा सके।

उद्देश्य और फोकस:

भविष्य के युद्धक्षेत्र की परिस्थितियों का अनुकरण, इन पर ध्यान केंद्रित करते हुए:

- वास्तविक समय निगरानी
- स्थितिजन्य जागरूकता
- जटिल भूभाग में त्वरित निर्णय लेना

तकनीकी एकीकरण:

अगली पीढ़ी की प्रणालियों का संयोजन:

- मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी)
- ड्रोन
- भूमि-आधारित प्लेटफॉर्म

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)-सक्षम सेंसरों का उपयोग, जो निम्न के साथ एकीकृत हैं:

- उत्तर संचार नेटवर्क
- कमांड सेंटर कनेक्टिविटी
- सुरक्षित और निर्बाध डेटा प्रवाह सक्षम

परिचालन संबंधी मुख्य विशेषताएँ:

- उच्च-ऊँचाई वाले वातावरण में यथार्थवादी युद्ध परिवर्षों का अनुकरण
- तेज़ लक्ष्यीकरण के लिए सेंसर-टू-शूटर लिंक को मज़बूत किया गया



KUMAR
EDUTAINMENT

- बेहतर डेटा संलयन, जिससे युद्धक्षेत्र में तेज़ी से निर्णय लेना संभव हुआ
- खतरों का पता लगाने, आकलन करने और उन पर तुरंत कार्रवाई करने की क्षमता में वृद्धि

बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025

भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों ने राजस्थान के जोधपुर के रेगिस्तानी क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास 'बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025' शुरू किया है।

स्थान एवं अवधि:

- जोधपुर, राजस्थान, भारत के रेगिस्तानी क्षेत्र में आयोजित
- तिथियाँ: जारी, 30 जुलाई, 2025 तक जारी रहने की योजना

प्रतिभागी:

- भारतीय सेना
- सिंगापुर सशस्त्र बल (SAF)

अभ्यास के उद्देश्य:

- दोनों देशों के बीच अंतर-संचालनीयता और रक्षा सहयोग को बढ़ाना
- लगभग वास्तविक युद्ध स्थितियों में आधुनिक युद्ध रणनीतियों का परीक्षण
- शहरी युद्ध और आतंकवाद-रोधी अभियानों में संयुक्त परिचालन दक्षता का निर्माण

मुख्य फोकस क्षेत्र:

- शहरी युद्ध सिमुलेशन और आतंकवाद-रोधी अभ्यास
 - नकली युद्धक्षेत्र स्थितियों में समन्वित सामरिक युद्धाभ्यास
 - खुफिया जानकारी साझा करना, वास्तविक समय में निर्णय लेना और समन्वित अभियान
 - अत्याधुनिक हथियारों और उत्तर संचार तकनीकों का उपयोग
- प्रौद्योगिकी और रणनीति:**
- आधुनिक रणनीति, तकनीकी समन्वय और डिजिटल युद्धक्षेत्र संचार पर ज़ोर
 - एकीकृत प्लेटफॉर्म्स और लगभग वास्तविक समय के युद्ध परिवर्षों का उपयोग करके संयुक्त रणनीतियों का क्रियान्वयन

"जब तक किसी काम को किया नहीं जाता !
तब तक वह असंभव ही लगता है !!"

"जितने वाले कुछ अलग चीज़े नहीं करते !
बस वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं !!"

सामाजिक मुद्दे एवं योजनाएँ

महाराष्ट्र ने बौद्धिक दिव्यांग छात्रों की समान शिक्षा के लिए 'दिशा अभियान' लागू किया

महाराष्ट्र ने बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के लिए एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की पहल, 'दिशा अभियान' को सफलतापूर्वक लागू किया है। यह कार्यक्रम राज्य भर के 453 विशेष विद्यालयों में शुरू किया गया है।

पाठ्यक्रम के बारे में

यह पाठ्यक्रम जय वकील फाउंडेशन (स्थापना 1944) द्वारा विकसित किया गया है और राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (NIEPID) द्वारा अनुमोदित है। यह विशेष शिक्षा के लिए 80 वर्षों के शोध और सार्वभौमिक शिक्षण विधियों पर आधारित है।

महत्व

महाराष्ट्र एक समान पाठ्यक्रम के माध्यम से बौद्धिक दिव्यांग छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह पहल 'विकसित भारत 2047' मिशन के तहत एक समावेशी और आत्मनिर्भर समाज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

उद्देश्य

एक मानकीकृत, शोध-आधारित शिक्षण ढाँचा प्रदान करना जो बौद्धिक अक्षमताओं वाले छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करे, समावेशी और समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करे।

महाराष्ट्र:

- स्थापना: 1 मई 1960 (महाराष्ट्र दिवस)।
- राजधानी: मुंबई (ग्रीष्मकालीन राजधानी: कुछ सत्रों के लिए नागपुर)।
- राज्यपाल: रमेश बैस
- मुख्यमंत्री: एकनाथ शिंदे।
- भूगोल: पश्चिमी भारत में स्थित; गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और अरब सागर से घिरा।
- प्रमुख शहर: मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद।
- प्रमुख नदियाँ: गोदावरी, कृष्णा, तापी, भीमा, वर्धा।
- वन्यजीव अभ्यारण्य/राष्ट्रीय उद्यान: ताडोबा-अंधारी बाघ अभ्यारण्य, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पेंच बाघ अभ्यारण्य (महाराष्ट्र का हिस्सा), नवगांव राष्ट्रीय उद्यान।
- त्यौहार: गणेश चतुर्थी, गुड़ी पड़वा, दिवाली, मकर संक्रांति।

सिक्किम के मुख्यमंत्री ने पहले अम्मा सम्मान दिवस पर 'नारी अदालत' का शुभारंभ किया

सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पहले अम्मा सम्मान दिवस के उपलक्ष्य में रोंगपो में 'नारी अदालत' का शुभारंभ किया।

'नारी अदालत' के बारे में

'नारी अदालत' महिलाओं द्वारा संचालित एक समुदाय-आधारित मंच है जिसका उद्देश्य सिक्किम के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सुलभ और अनौपचारिक न्याय प्रदान करना है।

उद्देश्य

महिलाओं को उन विवादों और सामाजिक मुद्दों से निपटने के लिए सशक्त बनाना जो उन्हें सीधे प्रभावित करते हैं। स्थानीय स्तर पर विवादों को सुलझाने के लिए एक सहायक, भयमुक्त वातावरण प्रदान करना। छोटे-मोटे मामलों के लिए औपचारिक न्यायालय प्रणाली पर निर्भरता कम करना।

मामलों का दायरा

यह निम्नलिखित मामलों से संबंधित है:

- परिवारिक मतभेद
- गंभीर धरेलू हिंसा के मामले
- वैवाहिक मामले
- अन्य छोटे-मोटे विवाद

औपचारिक अदालतों से मुख्य अंतर

नियमित अदालतों के विपरीत, जो औपचारिक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करती हैं और लंबी प्रक्रियाएँ अपनाती हैं, 'नारी अदालत' शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए लचीले, संवाद-आधारित तरीके से कार्य करती है।

सिक्किम:

- राज्य का दर्जा: 16 मई 1975 को भारत का 22वाँ राज्य बना।
- राजधानी: गंगटोक।
- राज्यपाल: लक्ष्मण प्रसाद आचार्य।
- मुख्यमंत्री: प्रेम सिंह तमांग।
- भूगोल: पूर्वोत्तर भारत में एक स्थलरुद्ध राज्य; भूटान, चीन (तिब्बत), नेपाल और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ।
- सबसे ऊँची चोटी: कंचनजंगा (8,586 मीटर) - दुनिया का तीसरा सबसे ऊँचा पर्वत।
- प्रमुख नदियाँ: तीस्ता, रंगीत।
- वन्यजीव अभ्यारण्य/राष्ट्रीय उद्यान: कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान (यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल), शिंगबा रोडोडेंड्रोन अभ्यारण्य, फम्बोंग लो वन्यजीव अभ्यारण्य।
- प्रसिद्धि: जैविक खेती (भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य), समृद्ध जैव विविधता, बौद्ध मठ और मनोरम परिवेश।
- त्यौहार: लोसर, सागा दावा, पंग ल्हाबसोल, माघे संक्रांति।

असम ने लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 'मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना 2.0' योजना शुरू की

असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में 'मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना 2.0' योजना की शुरुआत की, जिसका

उद्देश्य लड़कियों को उच्च शिक्षा में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

योजना विवरण:

उद्देश्य:

- लड़कियों में स्कूल छोड़ने की दर को कम करना
- छात्राओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना
- पारिवारिक आय की परवाह किए बिना वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना

पात्रता:

- सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में हाई स्कूल से पीजी स्तर तक पढ़ने वाली छात्राएँ
- कोई आय-आधारित प्रतिबंध नहीं

वित्तीय लाभ:

- शिक्षा स्तर मासिक सहायता कुल (10 महीने)
- हाई स्कूल (कक्षा 11) ₹1,000 ₹10,000
- स्नातक ₹1,250 ₹12,500
- स्नातकोत्तर ₹2,500 ₹25,000

वित्त वर्ष 2025-26 में, इस योजना से 4 लाख से अधिक छात्राएँ लाभान्वित होंगी।

असम:

- स्थापना दिवस: 15 अगस्त 1947 (भारत का एक घटक राज्य बना)
- राजधानी: दिसपुर
- सबसे बड़ा शहर: गुवाहाटी
- मुख्यमंत्री: हिमंत बिस्वा सरमा
- राज्यपाल: लक्ष्मण आचार्य
- राज्य पश्च: एक सींग वाला गैंडा
- राज्य पक्षी: सफेद पंखों वाला बत्तख
- राज्य नृत्य: बिहू
- राज्य पुष्टि: फॉक्सटेल आर्किड
- राज्य वृक्ष: होलोंग

सीमाएँ:

- भारतीय राज्य: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल
- देश: बांग्लादेश और भूटान
- प्रमुख नदियाँ: ब्रह्मपुत्र, बराक

प्रधानमंत्री मोदी ने 'कर्तव्य भवन-3' का उद्घाटन किया - सेंट्रल विस्टा परियोजना में एक महत्वपूर्ण कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित आधुनिक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरियट भवन, कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन किया।

उद्देश्य: यह पहल सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और चुस्त शासन को बढ़ावा देना है।

विशेषताएँ:

- 1.5 लाख वर्ग मीटर में निर्मित, 2 बेसमेंट और 7 मंजिलें

➤ आईटी-तैयार, सुरक्षित कार्यस्थल, आईडी-कार्ड एक्सेस, सेंट्रल कमांड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से सुसज्जित केन्द्रित किए जाने वाले मंत्रालय:

- गृह मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- एमएसएमई मंत्रालय
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी)
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय

संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के 6 महीने के विस्तार को मंजूरी दी

संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के 6 महीने के विस्तार को मंजूरी दी है, जो 13 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा।

विवरण:

राज्यसभा ने ध्वनिमत से वैधानिक प्रस्ताव पारित कर दिया। लोकसभा पहले ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी थी।

पृष्ठभूमि:

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पहली बार 13 फरवरी 2025 को लगाया गया था।

सरकार का रुखः

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से केवल एक हिस्क घटना हुई है और पिछले चार महीनों में किसी की जान नहीं गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मणिपुर में विकास कार्यों पर ज़ोर दिया गया।

विपक्ष का दृष्टिकोण:

मुजिबुल्ला खान (बीजद) ने विस्तार का विरोध करते हुए कहा कि यह उचित नहीं है।

मणिपुर

- राजधानी: इम्फाल

सीमाएँ:

- भारतीय राज्य: नागालैंड, असम, मिजोरम
- अंतर्राष्ट्रीय सीमा: म्यांमार (लगभग 398 किमी)
- प्रमुख नदियाँ: बराक, इम्फाल, थौबल, इरिल
- महत्वपूर्ण झीलें: लोकतक झील - पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मठीं पानी की झील
- उल्लेखनीय विशेषता: केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान - दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान

राष्ट्रपति शासन - (संक्षिप्त टिप्पणियाँ)

- अनुच्छेद: भारतीय संविधान का 356
- कारण: राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता
- द्वारा लगाया गया: राज्यपाल की रिपोर्ट पर या स्वप्रेरणा से राष्ट्रपति द्वारा
- प्रारंभिक अवधि: 6 महीने
- अधिकतम अवधि: 3 वर्ष (शर्तों के साथ)

1 वर्ष से अधिक विस्तार की शर्तें:

राष्ट्रीय आपातकाल लागू

चुनाव आयोग द्वारा चुनावों को प्रमाणित करना नहीं रखा जा सकता

प्रभाव:

- राज्य सरकार बखास्त
- राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से शासन करते हैं
- राज्य विधानमंडल भंग/निलंबित किया जा सकता है
- न्यायिक समीक्षा: अनुमति प्राप्त (एस.आर. बोम्मई मामला, 1994)
- पहला प्रयोग: पंजाब, 1951
- हाल ही में प्रयोग: मणिपुर, 2025

प्रधानमंत्री मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण हेतु 'ज्ञान भारतम मिशन' का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण हेतु ऐतिहासिक 'ज्ञान भारतम मिशन' पहल की घोषणा की।

मुख्य विशेषताएँ:

- उद्देश्य: भारत भर की 1 करोड़ से अधिक प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और संरक्षण।
- दृष्टिकोण: भारत के पारंपरिक ज्ञान तक वैश्विक पहुँच के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार का निर्माण करना।
- लक्ष्य: दुनिया भर के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत तक पहुँच को सुगम बनाना।

केंद्रीय बजट 2025:

- मिशन की घोषणा: 9 जून, 2025
- बजट आवंटन ₹3.5 करोड़ से बढ़ाकर ₹60 करोड़ किया गया।

नालसा ने रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कानूनी सहायता को मजबूत करने हेतु योजना शुरू की

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने 'वीर परिवार सहायता योजना' शुरू की है।

योजना शुभारंभ विवरण:

- अवसर: उत्तर क्षेत्र क्षेत्रीय सम्मेलन, श्रीनगर
- सम्मेलन का विषय: रक्षा कर्मियों और आदिवासियों के लिए न्याय के संवैधानिक दृष्टिकोण की पुष्टि
- अध्यक्षता: न्यायमूर्ति सूर्यकांत, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष

योजना के उद्देश्य:

- रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कानूनी सहायता को मजबूत बनाना
- ज़िला, राज्य और केंद्रीय सैनिक बोर्डों में एक समर्पित कानूनी सहायता नेटवर्क का निर्माण

➤ सैनिक बोर्डों को कल्याण केंद्रों के अलावा कानूनी सेवा केंद्रों के रूप में कार्य करने के लिए सुसज्जित करना

प्रदत्त दायरा और सहायता:**निम्नलिखित मुद्दों के लिए कानूनी सहायता:**

- भूमि विवाद
- वैवाहिक मामले
- सेवा अधिकार
- उपरोक्त विवाद (जैसे, बढ़े हुए बिजली बिल)
- दूरस्थ स्थानों पर तैनात उन कर्मियों पर ध्यान केंद्रित करना जो व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकते
- भौगोलिक और रसद संबंधी बाधाओं से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना

लघु लेख

विकसित भारत 2047 के लिए प्रमुख घोषणाओं और विज्ञन पर एक व्यापक नज़र

15 अगस्त 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया। यह भाषण केवल औपचारिक नहीं था, बल्कि एक रोडमैप भी था, जिसमें सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, शासन और रोजगार जैसे विविध आयामों में भारत के भविष्य के लिए सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया था।

नीचे सभी प्रमुख घोषणाओं, प्रासंगिक विश्लेषण और 2047 तक भारत के एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में उनके महत्व का विस्तृत अवलोकन दिया गया है।

1. दिशा निर्धारित करना: एक गतिशील राष्ट्र

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और 1947 से अब तक की यात्रा को याद करते हुए की। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत, जिसे कभी बाहरी शक्तियों पर निर्भर एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता था, अब रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और शासन सुधारों में एक वैश्विक नेता के रूप में पहचाना जा रहा है।

उन्होंने इस परिवर्तन को "विकसित भारत 2047" के विजन से जोड़ा—एक ऐसा भारत जो स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक समृद्ध, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और समावेशी हो।

2. मिशन सुदर्शन चक्र: रक्षा आत्मनिर्भरता**घोषणा**

प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान कृष्ण के पौराणिक अस्त्र से प्रेरित एक अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा कार्यक्रम "मिशन सुदर्शन चक्र" का अनावरण किया। इस मिशन का उद्देश्य राष्ट्र को उभरते खतरों से बचाने के लिए अगली पीढ़ी की तकनीकों का विकास करना है।

महत्व

रक्षा निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता को मज़बूत करता है। स्वदेशी हथियार प्रणालियों, साइबर सुरक्षा, ड्रोन और मिसाइल-रोधी तकनीकों पर केंद्रित है। रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भर भारत के साथ संरेखित है।

परिणाम

स्वदेशी प्रणालियों पर भारत का ध्यान आयात पर निर्भरता को कम करेगा, घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देगा और आने वाले दशकों में भारत को एक रक्षा निर्यातिक बना सकता है।

3. जीएसटी सुधार - राष्ट्र को दिवाली का उपहार**घोषणा**

प्रधानमंत्री ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में व्यापक सुधारों का वादा किया और इसे नागरिकों के लिए "दिवाली का उपहार" बताया।

मुख्य विशेषताएँ

छोटे व्यवसायों और विक्रेताओं के लिए कर दाखिल करने का सरलीकरण।

एमएसएमई के लिए अनुपालन बोझ में कमी।

मध्यम वर्ग और उपभोक्ताओं पर बोझ कम करने के लिए कर स्लैब का पुनर्गठन।

निहितार्थ

यह घोषणा सीधे तौर पर व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा दे सकती है और आम नागरिकों की क्रय शक्ति बढ़ा सकती है। यह कराधान को अधिक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और विकासोनुभवी बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत देती है।

4. सेमीकंडक्टर मिशन: तकनीकी संप्रभुता**घोषणा**

प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि भारत का पहला घरेलू निर्मित सेमीकंडक्टर चिप 2025 के अंत तक उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि छह सेमीकंडक्टर संयंत्र विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से चार को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।

महत्व

आयात पर निर्भरता कम करता है, खासकर ताइवान और चीन से।

भारत के बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और स्मार्टफोन उद्योगों को सशक्त बनाता है।

भारत को चिप निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करता है—जो डिजिटल संप्रभुता के लिए महत्वपूर्ण है।

संदर्भ

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के पहले के प्रयास विफल रहे थे। नए सरकारी समर्थन और वैश्विक साझेदारियों के साथ, भारत अब इस मिशन को "मिशन मोड" में आगे बढ़ा रहा है।

5. परमाणु ऊर्जा विस्तार - 2047 तक दस गुना वृद्धि**घोषणा**

प्रधानमंत्री ने भारत में 10 नए परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना की घोषणा की, जिसका लक्ष्य 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को दस गुना बढ़ाना है।

तर्क

परमाणु ऊर्जा कोयले का एक स्वच्छ, स्थिर और दीर्घकालिक विकल्प है।

जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता को मज़बूत करता है।

सौर, पवन और हाइड्रोजन के साथ-साथ ऊर्जा पोर्टफोलियो में विविधता लाता है।

परिणाम

भारत सतत ऊर्जा परिवर्तन में एक वैश्विक नेता के रूप में उभर सकता है, कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए औद्योगिक विकास को गति प्रदान कर सकता है।

6. शासन और अर्थव्यवस्था के लिए सुधार कार्य बल**घोषणा**

शासन को आधुनिक बनाने, नौकरशाही को सुव्यवस्थित करने और संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए एक नया सुधार कार्य बल स्थापित किया जाएगा।

फोकस क्षेत्र

व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए लालफीताशाही को कम करना। वैश्विक मानकों के अनुरूप नियमों को नया स्वरूप देना।

सरकारी कामकाज में तेज मंजूरी और बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करना।

महत्व

इस कदम का उद्देश्य एक व्यापार-अनुकूल गंतव्य के रूप में भारत की वैश्विक छवि को मज़बूत करना और व्यापार सुगमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में रैंकिंग में सुधार करना है।

7. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना - 3 करोड़**युवाओं के लिए रोज़गार****घोषणा**

इसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना थी, जो 3 करोड़ युवाओं के लिए ₹1 लाख करोड़ की एक विशाल रोज़गार योजना है।

विवरण

प्रति व्यक्ति प्रति माह ₹15,000 की वित्तीय सहायता।

बुनियादी ढाँचे, विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और सेवाओं जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री मोदी का 79वें स्वतंत्रता दिवस का संबोधन एक औपचारिक भाषण से कहीं बढ़कर था—यह भारत के परिवर्तन का एक रणनीतिक रोडमैप था। रक्षा और रोज़गार से लेकर कराधान और प्रौद्योगिकी तक, हर घोषणा 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के साथ भारत के विकास को जोड़ने की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।

आत्मनिर्भरता, युवा सशक्तिकरण, ऊर्जा स्वतंत्रता और वैश्विक नेतृत्व जैसे विषयों को एक साथ बुनकर, प्रधानमंत्री ने भारत के लिए एक साहसिक, महत्वाकांक्षी और भविष्योन्मुखी एजेंडा निर्धारित किया है।

अब चुनौती क्रियान्वयन की है—इन घोषणाओं को ठोस परिणामों में बदलना। अगर इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो यह भाषण 1991 के आर्थिक सुधारों की तरह एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है, जो 21वीं सदी में भारत के भाग्य को आकार देगा।

जल जीवन मिशन - छठी वर्षगांठ

15 अगस्त 2025 को, भारत ने जल जीवन मिशन (JJM) की छठी वर्षगांठ मनाई। इस मिशन ने 15 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों तक पाइप से पेयजल पहुँचाया है, जिससे 2019 में केवल 17% से बढ़कर 2025 में लगभग 80% हो गया है। इस वर्षगांठ पर स्वास्थ्य सुधार, महिलाओं के लिए कठिन परिश्रम कम करने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

उत्पत्ति और रूपरेखा

यह मिशन 15 अगस्त 2019 को जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण घर में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। शुरुआत में इसे 2024 के लिए लक्षित किया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2028 कर दिया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी का हकदार है।

फोकस क्षेत्र

जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों, जैसे सूखाग्रस्त और रेगिस्तानी क्षेत्रों, के साथ-साथ गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों, जहाँ प्रदूषण आम है, पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह कार्यक्रम स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायतों और सामुदायिक भवनों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के माध्यम से महिलाएँ केंद्रीय भूमिका निभाती हैं, जिनमें 50% प्रतिनिधित्व महिलाओं का होता है।

तकनीकी और सामाजिक हस्तक्षेप

"इंतेज़ार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है !
जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं !!"

यह मिशन आपूर्ति और गुणवत्ता पर नज़र रखने के लिए रीयल-टाइम डैशबोर्ड, IoT सेंसर और JJM-IMIS पोर्टल का उपयोग करता है। ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं, को जल गुणवत्ता परीक्षण का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। जागरूकता अभियान और श्रमदान जैसे स्वैच्छिक योगदान ने JJM को केवल सरकारी पहल के बजाय एक जन आंदोलन में बदल दिया है।

कार्यान्वयन में समस्याएँ

प्रगति के बावजूद, चुनौतियाँ बनी हुई हैं। 12,000 से अधिक ग्रामीण बस्तियाँ अभी भी लौह, आर्सेनिक, नाइट्रेट और फ्लोराइड के प्रदूषण का सामना कर रही हैं। संसदीय समितियों ने पाइपलाइन बिछाने के बाद सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे की खराब बहाली की ओर इशारा किया है। कई राज्यों में अभी भी व्यापक रखरखाव नीतियों का अभाव है, और कार्यान्वयन में देरी प्रगति को धीमा कर देती है। आँकड़ों और निगरानी तंत्र की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाए गए हैं।

सुदृढ़ीकरण के उपाय

विशेषज्ञ बुनियादी ढाँचे में कड़े गुणवत्ता मानकों, ठेकेदारों के भुगतान को परिणामों से जोड़ने और पारदर्शिता के लिए जियोटैगिंग के साथ तृतीय-पक्ष ऑडिट अपनाने का सुझाव देते हैं। प्रदर्शन-आधारित वित्त पोषण पिछड़े राज्यों में प्रगति को गति दे सकता है। सुरक्षित जल प्रथाओं के बारे में अधिक जागरूकता, अटल भूजल योजना जैसी योजनाओं के साथ वित्तीय एकीकरण और राष्ट्रव्यापी मरम्मत नीतियों को स्थिरता के लिए आवश्यक माना जाता है।

संघीय और कानूनी संदर्भ

संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत जल एक राज्य विषय है, जो राज्य सरकारों को जल योजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार देता है। केंद्र वित्तीय और तकनीकी सहायता के माध्यम से उनका समर्थन करता है, जिससे जल जीवन मिशन व्यवहार में सहकारी संघवाद का एक उदाहरण बन जाता है।

व्यापक महत्व

यह मिशन स्वच्छ जल और स्वच्छता पर सतत विकास लक्ष्य 6 में सीधे योगदान देता है। ₹3.6 लाख करोड़ से अधिक के परिव्यय के साथ, यह दुनिया के सबसे बड़े ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में से एक है। "हर घर जल" प्रमाणन, कैच द रेन अभियान और सार्वजनिक उपयोग के लिए जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएँ खोलने जैसी पहलों ने इसकी पहुँच को और बढ़ाया है। जल जीवन मिशन ग्रामीण भारत में जल सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

"कोशिश हमेशा आखरी सांस तक करनी चाहिए !
या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव !!"

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

क्या धराली में बादल फटा था या हिमनद झील का फटना हुआ था ? अंतर जानिए

धराली गाँव, उत्तराखण्ड में अचानक आई बाढ़

- दिनांक: 5 अगस्त, 2025
- स्थान: धराली गाँव, उत्तराखण्ड जिला, उत्तराखण्ड
- घटना: अचानक आई बाढ़ से गाँव में पानी, कीचड़ और मलबा भर गया।
- क्षति: आधा गाँव दब गया, होटल, घर और दुकानें नष्ट हो गईं।
- हताहत: कम से कम 4 लोग मारे गए, 60-70 लोग फँसे या लापता।
- बचाव के लिए चुनौतियाँ: अवरुद्ध सड़कें, खराब संचार और उबड़-खाबड़ इलाका।

बादल फटने का प्रारंभिक सिद्धांत

- प्रारंभिक अनुमान: बादल फटने (100 मिमी/घंटा से अधिक अत्यधिक वर्षा) के कारण बाढ़ आई।
- कुछ रिपोर्टों में 24 घंटों में 210 मिमी बारिश का दावा किया गया है।

आईएमडी के आंकड़े कुछ और ही कहते हैं:

- हरिल: 6.5 मिमी (1 दिन), 9 मिमी (24 घंटे)
- भटवारी: 11 मिमी
- ज़िला अधिकतम: 27 मिमी (बादल फटने के स्तर से काफ़ी नीचे)।

विशेषज्ञों की राय में बदलाव

- आईएमडी और भूवैज्ञानिक: इस तरह के विनाश के लिए वर्षा बहुत कम थी।
- नया सिद्धांत: बाढ़ संभवतः हिमनद गतिविधि के कारण हुई है - हिमनद का टूटना या हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ)।
- परिकल्पना: 6,000 मीटर से ऊपर विशाल हिमनद के फटने से मलबा और पानी नीचे की ओर बह गया।
- उपग्रह चित्र: खीर गाड़ धारा के पास ऊपर की ओर बढ़े हिमनद और 2 हिमनद झीलें दिखाई दे रही हैं।

हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) क्या है?

एक हिमनद झील में जमा पानी का अचानक बाहर निकलना, एक प्राकृतिक बांध (मोरेन) को तोड़ना।

कारण:

- हिमनद/बार्फ का टूटना
- झील में भूस्खलन
- भूकंपीय गतिविधि
- बढ़ते तापमान के कारण तेज़ी से पिघलना।
- प्रभाव: तेज़, शक्तिशाली बाढ़, भारी बारिश से जुड़ी नहीं।
- अंतर: बादल फटना बनाम हिमनद झील फटना

विशेषता	बादल फटना (Cloudburst)	हिमनद झील फटना (GLOF)
कारण	तीव्र स्थानीय वर्षा (100 मिमी/घंटा से अधिक)	भूवैज्ञानिक (ग्लैशियर का टूटना, बांध का टूटना)
उत्पत्ति	मौसम संबंधी	भूवैज्ञानिक
वर्षा से संबंध	प्रत्यक्ष	अक्सर न के बराबर या न्यूनतम
गति और विनाश	तल्काल, वर्षा-चालित	अचानक, भारी बल, अधिक विनाशकारी

हिमनद झील फटने के कारण

- कटाव, भारी बारिश या भूस्खलन के कारण हिमोढ़ बांध का टूटना।
- हिमस्खलन, भूकंपीय झटके, तेज़ी से पिघलना।
- जलवायु परिवर्तन: ग्लैशियर का पीछे हटना और झील का आकार बढ़ना।

भारत में पिछले उदाहरण

- केदारनाथ 2013 (चोराबारी झील): हिमोढ़ बांध के फटने से मिनटों में 262 मिलियन लीटर पानी बह गया, जिससे भारी तबाही हुई।
- सिक्किम 2023 (दक्षिण ल्होनक झील): भारी बारिश के कारण तीस्ता III बांध टूट गया, जिससे शहर और पुल नष्ट हो गए।
- चमोली 2021 (रोंती गाड़): चट्टान-बर्फ के हिमस्खलन से मलबा और बाढ़ आई, कई लोग हताहत हुए।

पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्रदूषण के लिए ज़िम्मेदार लोगों द्वारा दूषित स्थलों के उपचार हेतु पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया है।

उद्देश्य:

प्रदूषण के लिए ज़िम्मेदार लोगों द्वारा दूषित स्थलों के उपचार हेतु एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।

संदर्भ: असम में 2020 के बाघजन तेल विस्फोट जैसी घटनाओं से प्रेरित।

शामिल प्रदूषक:

कृषि, आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में 189 प्रदूषक इसमें शामिल हैं: हैलोजनयूक्त सुर्गंधित पदार्थ, कीटनाशक, पीएच, ऑर्गेनोफ्लोरीन, भारी धातुएँ

छूट (सर्तर):

- रेडियोधर्मी अपशिष्ट (परमाणु ऊर्जा नियम, 1987)
- खनन कार्य (खान अधिनियम, 1957)

- हालाँकि, यदि तेल रिसाव, रेडियोधर्मी मिश्रण आदि के कारण संदूषण सीमा से अधिक हो जाता है, तो उपचार लागू होता है।

स्थल की पहचान और रिपोर्टिंग:

- स्थानीय निकाय/जिला प्रशासन संदिग्ध स्थलों की पहचान और रिपोर्ट करेंगे (स्वयं या सार्वजनिक शिकायत)
- केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल पर डेटा अपलोड किया जाएगा
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) को अर्धवार्षिक रिपोर्ट

एसपीसीबी की जिम्मेदारियाँ:

- 90 दिनों में प्रारंभिक मूल्यांकन
- 30 दिनों में सीपीसीबी के साथ संभावित स्थलों को साझा करें
- स्थलों पर गतिविधि प्रतिबंधित करें; 60 दिनों के भीतर जनता की टिप्पणियाँ प्राप्त करें
- 90 दिनों में जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान करें
- यदि स्थल स्थानांतरित किया जाता है, तो हस्तांतरित व्यक्ति उत्तरदायी होगा
- सुधार योजनाओं को अनुमोदित और निगरानी करें
- यदि कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है: एसपीसीबी 6 महीने में योजना तैयार करेगा

सुधार और वित्तपोषण:

जिम्मेदार व्यक्ति लागत वहन करेगा; एसपीसीबी द्वारा चयनित एजेंसी का उपयोग करता है।

प्रवर्तन:

एसपीसीबी निम्नलिखित पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगा सकता है:

- अनुपालन न करना
- उपचार में देरी/विफलता
- स्वास्थ्य/पर्यावरणीय जोखिम पैदा करने वाले स्थल

काजीरंगा बाघ घनत्व में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर

काजीरंगा टाइगर रिजर्व (केटीआर) अब दुनिया में बाघों के घनत्व के मामले में तीसरे स्थान पर है।

जनसंख्या मील का पथर:

बाघों की जनसंख्या (2024): 148 वयस्क बाघ (2022 में 104 से बढ़कर)

- मादाँ: 83
- नर: 55
- अनिर्धारित: 10
- रिपोर्ट जारी: अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस (29 जुलाई)
- रिपोर्ट का शीर्षक: "काजीरंगा में बाघों की स्थिति 2024"

विभागवार बाघ गणना:

- पूर्वी असम वन्यजीव प्रभाग: 104 (2022) से बढ़कर 115 (2024)
- नागांव वन्यजीव प्रभाग: 6 बाघों पर स्थिर
- विश्वनाथ वन्यजीव प्रभाग: 27 बाघ (पहली बार नमूना)

वैश्विक बाघ घनत्व रैंकिंग:

1. बांदीपुर टाइगर रिजर्व: (भारत): 19.83 बाघ प्रति 100 वर्ग किमी।
2. कॉर्बट राष्ट्रीय उद्यान: (भारत): 19.56 बाघ प्रति 100 वर्ग किमी।
3. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान: (भारत): 18.65 बाघ प्रति 100 वर्ग किमी।

लघु लेख

भारत की एथनॉल-मिश्रण पहल: अवसर, चुनौतियाँ और आगे का मार्ग

1. भारत का इथेनॉल विज़न: लक्ष्य और तर्क

भारत ने 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल (E20) मिलाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर काम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य तेल आयात कम करना, किसानों को सहायता प्रदान करना और उत्सर्जन में कटौती करना है। यह नीति 1970 के दशक के वैश्विक जैव ईंधन परिवर्तन की विरासत पर आधारित है और ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में देश की "ब्रिज प्यूल" रणनीति के हिस्से के रूप में इथेनॉल को शामिल करती है।

इथेनॉल फीडस्टॉक्स में C-भारी गुड़, टूटे चावल और मक्का शामिल हैं—ये फसलें आमतौर पर खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं से बाहर होती हैं—जिनसे विदेशी मुद्रा में लगभग 10 बिलियन डॉलर (₹80,000 करोड़) की वार्षिक बचत और कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ होने का अनुमान है।

2. तकनीकी और परिचालन संबंधी चिंताएँ

आलोचक—विशेषकर वाहन मालिक—दावा करते हैं कि E20 माइलेज कम करता है, इंजनों को नुकसान पहुँचाता है और रखरखाव लागत बढ़ाता है, खासकर पुराने या गैर-संगत वाहनों में। सरकार और उद्योग निकाय जैसे SIAM, ARAI और IOCL इन दावों का खंडन करते हैं, कई अध्ययनों का हवाला देते हुए, जो कई आधुनिक कारों में केवल मापूली दक्षता में गिरावट (~1–2%) और बेहतर सवारी गुणवत्ता दिखाते हैं। E20 की उच्च ऑक्टेन रेटिंग (~108.5 RON) उच्च-संपीड़न इंजनों में प्रदर्शन और एंटी-नॉकिंग को भी बढ़ाती है। E20 के इस्तेमाल के लिए बीमा से इनकार नहीं किया जाता; इंजन क्षति से जुड़ी पुरानी आशंकाएँ अब बेमानी हो गई हैं।

3. उपभोक्ता अनुभव और मूल्य पारदर्शिता

सैद्धांतिक लागत लाभों के बावजूद, उपभोक्ता रिपोर्ट करते हैं कि ईंधन स्टेशनों पर कीमतों में कमी नहीं होती है, और कुछ वाहनों का माइलेज अब कम हो गया है—जिससे चिंता और संदेह पैदा हो रहा है।

4. खाद्य सुरक्षा और बाज़ार संतुलन

हालाँकि इथेनॉल उत्पादन में गैर-खाद्य बायोमास का उपयोग किया जाता है, लेकिन हितधारक आगाह करते हैं कि मक्का जैसी

फीडस्टॉक फसलों की ओर तेज़ी से बढ़ते रक्खे से खाद्य तेल आत्मनिर्भरता रणनीति को खतरा हो सकता है। वास्तव में, मक्के के विस्तार ने तिलहन की खेती और खाद्य तेलों के उत्पादन को पहले ही प्रभावित किया है। इसके अलावा, इथेनॉल उत्पादन—तेल आयात में कमी के बावजूद—उर्वरक आयात पर निर्भर बना हुआ है, जिससे विदेशी मुद्रा बचत आंशिक रूप से प्रभावित हो रही है।

5. वैश्विक मिश्नों और तकनीकी तत्परता

ब्राज़ील, अमेरिका और यूरोप जैसे देश लंबे समय से इथेनॉल मिश्नों (ब्राज़ील में E27 तक) का उपयोग करते आ रहे हैं, जो मानकों के पूरा होने पर तकनीकी व्यवहार्यता और वाहन सुरक्षा को प्रदर्शित करते हैं। भारत ने 2001 में BS-II मानदंडों को अपनाया, और 2023 से वाहनों को E20 अनुकूलता के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। हालाँकि, कई पुराने मॉडलों में ऐसे विनिर्देशों का अभाव था, जिससे मिश्न अनुकूलता और शमन रणनीतियों पर निर्माता पारदर्शिता की आवश्यकता पड़ी।

6. आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ

ऊर्जा सुरक्षा के अलावा, इथेनॉल मिश्न ग्रामीण आय को बढ़ावा देता है और CO₂ उत्सर्जन को 50-65% तक कम करता है (पेट्रोल की तुलना में), विशेष रूप से गन्ना और मक्का आधारित उत्पादन से। जल उपयोग, जैव विविधता हानि और अप्रत्यक्ष भूमि उपयोग परिवर्तन जैसे पर्यावरणीय प्रभावों—जो वैश्विक जैव ईंधन बहसों में आम हैं—के लिए भी जागरूकता की आवश्यकता है, हालाँकि भारत अपशिष्ट फीडस्टॉक्स का उपयोग करके इन्हें कम करता है।

7. सरकार की प्रतिक्रिया और रोडमैप

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने नीति आयोग की अंतर-मंत्रालयी समिति के माध्यम से हितधारकों के साथ परामर्श का हवाला देते हुए, E20 पहल का लगातार बचाव किया है। हालाँकि इथेनॉल खरीद लागत बढ़कर ₹71.32 प्रति लीटर (2024-25) हो गई है, इसके रणनीतिक लाभों के कारण मिश्न जारी है। सरकार ने 31 अक्टूबर 2026 तक E20 अधिदेश की पुष्टि की है, जिसमें 20% से आगे जाने का कोई भी निर्णय शामिल नहीं है। (उदाहरण के लिए, E27) हितधारकों के परामर्श और वैश्वानिक मूल्यांकन पर आधारित होगा।

8. आगे बढ़ना: प्रमुख उपाय

कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए, संपादकीय इस पर ज़ोर देता है:

वाहन निर्माताओं द्वारा इथेनॉल अनुकूलता के बारे में पूर्ण पारदर्शिता।

बीमा कवरेज सहित उपभोक्ता सहायता तंत्र।

पुराने वाहनों के लिए स्पष्ट शमन मार्गदर्शन और प्रतिस्थापन सहायता।

सरकार, उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच मजबूत संवाद।

9. ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और समता में संतुलन

भारत के इथेनॉल मिश्न लक्ष्य महत्वाकांक्षी हैं और दीर्घकालिक ऊर्जा परिवर्तन और ग्रामीण आजीविका लक्ष्यों के अनुरूप हैं। हालाँकि, सफलता खाद्य सुरक्षा, मूल्य निर्धारण पारदर्शिता, वाहन अनुकूलता और जनता का विश्वास बनाने जैसी चुनौतियों का समाधान करने पर निर्भर करती है।

एक संतुलित, व्यावहारिक दृष्टिकोण—जो विज्ञान, निष्पक्षता और नीति पारदर्शिता पर आधारित हो—गति को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि इथेनॉल मिश्न समान और स्थायी रूप से लाभ प्रदान करे।

सारांश तालिका

विषय अंतर्दृष्टि

- राष्ट्रीय उद्देश्य E20 मिश्न 2025-26 के लिए निर्धारित; सालाना 10 अरब डॉलर की बचत
- तकनीकी व्यवहार्यता: आधुनिक इंजनों में दक्षता; माइलेज में मामूली गिरावट (~1-2%)
- उपभोक्ता चिंताएँ: कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई नहीं दे रही; पुराने वाहनों और माइलेज से जुड़ी समस्याओं की सूचना
- पर्यावरणीय प्रभाव: CO₂ में कमी; खाद्य बनाम ईंधन संबंधी चिंताओं पर नज़र
- वैश्विक अभ्यास: ब्राज़ील जैसे देश: MSM उच्च मिश्नों के साथ सफल
- नीति ढाँचा: E20, 2026 तक अनिवार्य; किसी भी वृद्धि पर परामर्श और अंशांकन किया जाएगा
- भविष्य की कार्रवाई: निर्माता पारदर्शिता; उपभोक्ता आश्वासन; नीतिगत स्पष्टता आवश्यक

भारत का आगामी कार्बन बाज़ार

भारत 2026 में अपना घरेलू कार्बन बाज़ार शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिससे उत्सर्जन में कमी के लिए एक संरचित प्रणाली का निर्माण होगा। इस ढाँचे के अंतर्गत, बायोचार जैसी कार्बन निष्कासन प्रौद्योगिकियाँ, औद्योगिक विकास और जलवायु प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाने के लिए महत्वपूर्ण समाधान के रूप में उभर रही हैं। कृषि और नगरपालिका के कचरे को स्थिर कार्बन सिंक में परिवर्तित करके, बायोचार भारत को प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन चुनौतियों का समाधान करते हुए जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है।

भारत का उत्सर्जन प्रोफ़ाइल

हालाँकि 1850 और 2019 के बीच वैश्विक संचयी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारत का योगदान केवल 4% है, फिर भी यह चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत का एक-तिहाई बना हुआ है, जो इसकी विकासात्मक स्थिति को दर्शाता है। 2005 से 2020 तक, देश ने अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी हासिल की। क्षेत्रवार,

बिजली क्षेत्र का दबदबा है, जहाँ कोयला आधारित संयंत्र कुल CO₂ उत्सर्जन में लगभग आधे का योगदान करते हैं, जबकि परिवहन क्षेत्र लगभग 12% का योगदान देता है। ये ऑकड़े स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तनों के पूरक के रूप में स्केलेबल निष्कासन तकनीकों की तात्कालिकता को रेखांकित करते हैं।

कार्बन समाधान के रूप में बायोचार

बायोचार एक कार्बन-समृद्ध उत्पाद है जो कृषि अवशेषों और जैविक कचरे के पायरोलाइज़ेशन से प्राप्त होता है। भारत में प्रतिवर्ष 600 मिलियन टन से अधिक फसल अवशेष और लगभग 60 मिलियन टन नगरपालिका अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसका अधिकांश भाग जला दिया जाता है या त्याग दिया जाता है। इस फीडस्टॉक के आधे हिस्से का भी बायोचार के लिए उपयोग करने से हर साल लगभग 0.1 गीगाटन CO₂-समतुल्य उत्सर्जन की भरपाई हो सकती है, जिससे कार्बन-मुक्ति का एक प्रभावी मार्ग उपलब्ध होता है।

पर्यावरणीय और कृषि लाभ

बायोचार की ताकत सैकड़ों वर्षों तक मिट्टी में कार्बन को संचित रखने और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने की इसकी क्षमता में निहित है। कृषि भूमि पर प्रयोग करने पर, बायोचार जल धारण क्षमता को बढ़ाता है और नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन को 30-50% तक कम करता है, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड में CO₂ की तुलना में 273 गुना अधिक तापन क्षमता होती है। अर्ध-शुष्क और क्षरित मिट्टी के लिए, बायोचार जलवायु और आजीविका दोनों के लिए लाभ प्रदान करता है।

औद्योगिक और ऊर्जा क्षमता

कृषि के अलावा, बायोचार उत्पादन से सिंथेटिक गैस और जैव-तेल जैसे मूल्यवान उपोत्पाद उत्पन्न होते हैं। ये दोनों मिलकर सालाना 8-13 TWh बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और 12-19 मिलियन टन डीजल या मिट्टी के तेल का विकल्प बन सकते हैं, जिससे कच्चे तेल के आयत में कमी आएगी और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता 2% से अधिक कम होगी। निर्माण क्षेत्र में, कंक्रीट में थोड़ी मात्रा में बायोचार मिलाने से न केवल ताप प्रतिरोध और मजबूती में सुधार होता है, बल्कि अतिरिक्त CO₂ भी अवशेषित

होता है, जिससे इमारतें निष्क्रिय कार्बन भंडारण इकाइयों में बदल जाती हैं।

अपशिष्ट जल और प्रदूषण नियंत्रण

भारत में प्रतिदिन 70 अरब लीटर से अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है, जिसमें से लगभग तीन-चौथाई अनुपचारित रह जाता है, बायोचार एक सस्ता नियंत्रण माध्यम प्रदान करता है। इसकी छिद्रयुक्त संरचना इसे प्रदूषकों को अवशेषित करने के लिए उपयुक्त बनाती है, जिससे पर्यावरणीय और जन स्वास्थ्य दोनों लक्ष्यों की पूर्ति होती है। जल उपचार में बायोचार को शामिल करने से शहरी स्थिरता रणनीतियों को पूरक बनाया जा सकता है और साथ ही ग्रीनहाउस गैसों को कम किया जा सकता है।

वैकल्पिक CO₂ निष्कासन विधियाँ

बायोचार जहाँ एक ओर आशाजनक है, वहीं कार्बन निष्कासन की अन्य विधियाँ भी लोकप्रिय हो रही हैं। जैव-आधारित विधियों में वनरोपण, कृषि वानिकी और मृदा कार्बन संवर्धन शामिल हैं। समुद्री शैवाल की खेती और कृत्रिम अपवेलिंग जैसी महासागर-आधारित विधियों का अध्ययन किया जा रहा है। कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के साथ बायोएनर्जी (BECCS), डायरेक्ट एयर कैप्चर (DAC), और कार्बन कैप्चर, यूटिलाइज़ेशन और स्टोरेज (CCUS) जैसी तकनीकी विधियों का विश्व स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें स्विट्जरलैंड और कनाडा की कंपनियाँ अग्रणी हैं। प्रत्येक विकल्प अलग-अलग स्तर की मापनीयता, लागत-प्रभावशीलता और स्थायित्व प्रदान करता है।

ब्यापक महत्व

भारत के लिए 2070 तक अपनी शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धता को पूरा करने हेतु बायोचार और इसी तरह के समाधानों को अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। यह पहल अपशिष्ट प्रबंधन को नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि लचीलेपन से जोड़ती है, जिससे एक चक्रीय कार्बन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। बायोचार को "हरित भविष्य के लिए काला सोना" के रूप में स्थापित करके, भारत स्थायी प्रौद्योगिकियों में अपने वैश्विक नेतृत्व को मजबूत कर सकता है और एक विकेन्द्रीकृत कृषि-से-ईंधन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर सकता है जो जलवायु और ग्रामीण आजीविका दोनों के लिए लाभकारी हो।

"सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतज़ार मत करो !
बल्कि अपने हर समय को खास बनालो !!"

"निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े !
क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय
बदल जाती है !!



विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने गगनयान मिशन के लिए पैराशूट-आधारित मंदन प्रणाली की पुष्टि हेतु पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण (IADT-01) सफलतापूर्वक किया।

- उद्देश्य: अंतरिक्ष यात्रियों को पुनः प्रवेश और स्पैलैशडाउन के दौरान सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए डिज़ाइन की गई संपूर्ण पैराशूट पुनर्प्राप्ति प्रणाली का प्रदर्शन करना।
- सहयोग: यह परीक्षण भारतीय वायु सेना, डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के साथ संयुक्त रूप से किया गया।

परीक्षित प्रणाली:

- दो ड्रोग पैराशूट (प्रारंभिक धीमा करने के लिए)।
- पायलट पैराशूट (स्थिरता के लिए)।
- तीन मुख्य पैराशूट (सुरक्षित अवतरण और लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए)।

महत्व: भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और पुनर्प्राप्ति तंत्र की पुष्टि करता है।

आगामी उपलब्धियाँ:

- परीक्षण वाहन प्रदर्शन मिशन (TV-D2)।
- पहला मानवरहित गगनयान मिशन (G1)।
- अंतिम चरण गगनयान कार्यक्रम के तहत भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान होगा।

गगनयान मिशन:

भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम।

- उद्देश्य: तीन सदस्यीय दल को 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा में तीन दिनों के लिए भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना।
- प्रक्षेपण यान: मानव-चालित LVM3 रॉकेट (HLVM3)।
- लक्ष्य समय-सीमा: 2025-26 तक।
- बजट: लगभग ₹10,000 करोड़।

इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन):

- स्थापना: 1969।
- मुख्यालय: बैंगलुरु।
- वर्तमान अध्यक्ष: एस. सोमनाथ।

संबंधित उपलब्धियाँ:

- चंद्रयान-3 (2023): भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उत्तरने वाला पहला देश बना।
- आदित्य-L1 मिशन (2023): भारत की पहली सौर वेधशाला।
- पीएसएलवी, जीएसएलवी और एलवीएम3 इसरो के प्रमुख प्रक्षेपण यान हैं।

भारतीय दूत को स्पेन में अंतिम 16 एयरबस C-295 सैन्य परिवहन विमान प्राप्त हुए

भारत को स्पेन से एयरबस C-295 सैन्य परिवहन विमान की अंतिम (16वीं) इकाई प्राप्त हुई। इसके साथ ही भारत को एयरबस की फ्लाईअवे डिलीवरी की प्रतिबद्धता पूरी हो गई।

C-295 एक सामरिक परिवहन विमान है जिसमें:

- 5-10 टन पेलोड क्षमता
- आधुनिक एवियोनिक्स
- 11 घंटे तक की उड़ान क्षमता
- कई सैन्य अभियानों (सैनिक परिवहन, कार्गो, एयरड्रॉप, मेडिक, आदि) के लिए उपयुक्त
- C-295 भारतीय वायु सेना (IAF) के पुराने एवरो विमान बेड़े की जगह लेगा।

अनुबंध अवलोकन

- कुल हस्ताक्षरित अनुबंध: सितंबर 2021
- कुल ॲर्डर किए गए विमान: 56 C-295MW विमान
- 16 विमान स्पेन से उड़ान भरने की स्थिति में वितरित किए जाएँगे
- 40 विमान टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) द्वारा भारत में निर्मित किए जाएँगे

इस कार्यक्रम को एयरोस्पेस निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाले एक ऐतिहासिक रक्षा सहयोग के रूप में देखा जा रहा है।

रूस ने नया अंतरिक्ष मिशन डिज़ाइन शुरू किया, 2036 से पहले शुक्र ग्रह पर दोबारा जाने की योजना

रूस 2036 से पहले शुक्र ग्रह पर अपने वेनेरा-डी अंतरग्रहीय मिशन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस परियोजना को आधिकारिक तौर पर देश के नए राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

प्रारंभिक डिज़ाइन और समय-सीमा

डिज़ाइन चरण की शुरुआत: जनवरी 2026, जो रूस की राष्ट्रीय अंतरिक्ष परियोजना की शुरुआत के साथ मेल खाता है। प्रारंभिक डिज़ाइन अवधि: दो वर्ष लगने की उमीद है। प्रक्षेपण समय-सीमा: अंतिम प्रक्षेपण तिथि डिज़ाइन चरण के बाद, लेकिन निश्चित रूप से 2036 से पहले निर्धारित की जाएगी। प्रारंभिक अनुमान: वैज्ञानिक निदेशक लेव ज़ेलेनी के अनुसार, प्रक्षेपण वास्तविक रूप से 2034-2035 के आसपास हो सकता है।

प्रमुख संस्थान शामिल

अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (आईकेआई), रूसी विज्ञान अकादमी: वैज्ञानिक योजना का नेतृत्व।

- ओलेग कोराबलेव: आईकेआई में ग्रह भौतिकी विभाग के प्रमुख, सक्रिय रूप से प्रगति की निगरानी कर रहे हैं।

- लावोक्चिन एसोसिएशन: रूसी अंतरिक्ष उद्योग उद्यम मिशन विकास पर सहयोग कर रहा है।

मिशन घटक

- लैंडर: शुक्र ग्रह का सतही अन्वेषण करने के लिए।
- बैलून प्रोब: शुक्र ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए।
- कक्षीय अंतरिक्ष यान: शुक्र ग्रह की कक्षा से उसका अवलोकन और विश्लेषण करने के लिए।

अरुणाचल प्रदेश में इसरो समर्थित अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन

अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री पासंग दोरजी सोना ने शि-योमी ज़िले के मेचुका सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इसरो और मुस्कान फ़ाउंडेशन के सहयोग से स्थापित इस प्रयोगशाला का उद्देश्य छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है।

मुख्य विशेषताएँ

- प्रयोगशाला का नाम: पासंग वांगचुक सोना इसरो अंतरिक्ष प्रयोगशाला (मंत्री के पिता के नाम पर)
- उद्घाटनकर्ता: पासंग दोरजी सोना (शिक्षा मंत्री, अरुणाचल प्रदेश)
- स्थान: मेचुका, शि-योमी ज़िला, अरुणाचल प्रदेश
- भागीदार: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) + मुस्कान फ़ाउंडेशन
- उद्देश्य: छात्रों में जिज्ञासा, नवाचार और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना; अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रुचि को बढ़ावा देना।
- महत्व: सुदूर क्षेत्र में इस तरह की पहली सुविधा, जिसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों को प्रेरित करना है।

राजस्थान में भारत का पहला ड्रोन-आधारित क्लाउड सीडिंग परीक्षण

राजस्थान, जयपुर के रामगढ़ बांध के पास भारत का पहला ड्रोन-आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग करने जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा करेंगे। यह पायलट परियोजना राजस्थान कृषि विभाग और जेनएक्स एर्स (अमेरिका और बेंगलुरु स्थित एक प्रौद्योगिकी फर्म) के बीच एक सहयोग है।

परीक्षण विवरण

वर्षा को प्रोत्साहित करने के लिए नमी से भरे बादलों में विशेष रसायनों को छिड़कने के लिए लगभग 60 ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। यह कार्यक्रम स्थानीय लोगों के लिए खुला रहेगा। मूल रूप से 31 जुलाई 2024 के लिए निर्धारित, इसे भारी बारिश की चेतावनी के कारण स्थगित कर दिया गया था। डीजीसीए,

आईएमडी, जिला प्रशासन और कृषि विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

क्लाउड सीडिंग के बारे में

क्लाउड सीडिंग एक मौसम परिवर्तन तकनीक है जिसमें पानी की बूदों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या सूखी बर्फ जैसे रसायनों को बादलों में छोड़ा जाता है। जब बूदें भारी हो जाती हैं, तो वे बारिश के रूप में गिरती हैं। परंपरागत रूप से, इस प्रक्रिया के लिए विमान या हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है।

ड्रोन-आधारित क्लाउड सीडिंग के लाभ

ड्रोन, विमानों की तुलना में अधिक लागत-प्रभावी, सटीक और तेज़ होते हैं। ये स्थानीय स्तर पर वर्षा कराने के लिए उपयुक्त हैं, खासकर राजस्थान जैसे सूखाप्रस्त क्षेत्रों में। इस परीक्षण का उद्देश्य कृषि के लिए समय पर वर्षा उपलब्ध कराना है और यह जलवायु अनुकूलन का एक प्रमुख साधन बन सकता है।

पृष्ठभूमि और लागत

- 2023: चित्तौड़गढ़ के भैसुंडा बांध पर विमानों का उपयोग करके कृत्रिम वर्षा कराने के प्रयास पर ₹10 करोड़ की लागत आई, लेकिन बादलों में पर्याप्त नमी न होने के कारण यह प्रयास विफल रहा।
- दिल्ली: वायु प्रदूषण कम करने के लिए संशोधित विमानों का उपयोग करके 30 अगस्त से 10 सितंबर 2024 के बीच ₹3.21 करोड़ की लागत से पहला क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने की योजना है।

इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को प्रक्षेपित किया

इसरो ने जीएसएलवी-एफ16 रॉकेट का उपयोग करके नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (निसार) उपग्रह प्रक्षेपित किया।

इसरो के आगामी मिशन और अपडेट:

- नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (निसार) उपग्रह प्रक्षेपण तिथि: 30 जुलाई, 2025
- प्रक्षेपण यान: जीएसएलवी-एफ16 रॉकेट
- मिशन: सिंथेटिक अपर्चर रडार से पृथ्वी अवलोकन
- कक्षा कवरेज: हर 12 दिनों में पूरे ग्रह का स्कैन
- इमेजिंग: उच्च-रिज़ॉल्यूशन, दिन-रात, 242 किलोमीटर के क्षेत्र में सभी मौसमों में
- रडार बैंड: नासा का एल-बैंड और इसरो का एस-बैंड रडार
- उद्देश्य: जलवायु परिवर्तन अनुसंधान, आपदा प्रतिक्रिया, पृथ्वी विज्ञान
- क्षमताएँ: सेंटीमीटर स्तर की सटीकता के साथ सतही परिवर्तनों पर नज़र रखना, ग्लोशियरों, वनस्पतियों, भूकंपों, पर्यावरणीय क्षरण और बुनियादी ढाँचे पर दबाव की निगरानी करना

गगनयान मिशन (मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम):

- उद्देश्य: भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों (गगनांट्स) को अंतरिक्ष में भेजना
- नियोजित चालक दल प्रक्षेपण: मार्च 2027

- पूर्ववर्ती मिशन: तीन मानवयुक्त प्रक्षेपण से पहले मानवरहित मिशन
- मानवीय मिशन: दिसंबर 2025 के लिए निर्धारित
- रोबोट: व्योममित्र (महिला मानवरूपी रोबोट)
- क्षमताएँ: मॉड्यूल मापदंडों की निगरानी, अलर्ट जारी करना, जीवन रक्षक कार्य करना, छह पैनल संचालित करना, प्रश्नों का उत्तर देना

ईरान ने रूसी सोयुज रॉकेट से नाहिद-2 दूरसंचार उपग्रह प्रक्षेपित किया

ईरान ने अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद-2 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।

- प्रक्षेपण: नाहिद-2 उपग्रह को रूसी सोयुज रॉकेट से एक बहु-पेलोड मिशन के तहत प्रक्षेपित किया गया, जिसमें रूस के आयनोस्फेरा-एम3 और एम4 तथा 18 अन्य उपग्रह शामिल थे।
- कक्षा: 500 किमी पर पृथ्वी की निचली कक्षा, 5 वर्षों के परिचालन जीवन के लिए डिज़ाइन किया गया।

उपग्रह की विशेषताएँ:

- विकसितकर्ता: ईरानी अंतरिक्ष एजेंसी, घरेलू अनुसंधान केंद्रों और फर्मों के साथ।
- प्रणोदन: स्वदेशी प्रणाली जो गर्म गैस थ्रस्टर्स और ईरान निर्मित घटकों के साथ कक्षा को 50 किमी तक समायोजित करती है।
- शक्ति और सामग्री: घरेलू लिथियम-आयन बैटरी, पॉलीमर कोटिंग्स और तापीय आसजक।
- उप-प्रणालियाँ: त्रि-अक्षीय अभिवृत्ति नियंत्रण, बहु-बैंड द्विमार्गी संचार, डेटा प्रबंधन, विद्युत वितरण।

रणनीतिक महत्व:

सोयुज पर प्रदर्शित प्रतीक राष्ट्रीय क्षमता को दर्शाता है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान को एयरोस्पेस तकनीक को आगे बढ़ाता है। राष्ट्रीय उपग्रह नेटवर्क, LEO तारामंडल और भविष्य के GEO मिशनों के लिए ईरान के लक्ष्यों का समर्थन करता है।

भविष्य की योजनाएँ और संदर्भ:

- 2025 में और प्रक्षेपणों की योजना: ईरानी प्रक्षेपकों का उपयोग करके ज़फर-1, पयाम और अगली पीढ़ी के नाहिद उपग्रह।
- अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत यह उपलब्धि ईरान को स्वतंत्र दूरसंचार उपग्रह तकनीक वाले कुछ देशों में शामिल करती है—जो वैज्ञानिक लचीलेपन और रणनीतिक प्रगति का प्रतीक है।

लघु लेख

भारत का दीर्घकालिक अंतरिक्ष दृष्टिकोण

भारत सरकार ने 'विकसित भारत @2047' के व्यापक लक्ष्य के तहत बाह्य अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। इस योजना में 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) की स्थापना और 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय चालक दल मिशन भेजना शामिल है। इन उपलब्धियों का उद्देश्य वैज्ञानिक और आर्थिक अवसरों का विस्तार करते हुए एक वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है।

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की परिकल्पना भारत के अपने कक्षीय प्लॉटफॉर्म के रूप में की गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के समान है। यह पृथ्वी से 400-450 किमी की ऊँचाई पर परिक्रमा करेगा और सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में विभिन्न प्रकार के प्रयोगों की मेजबानी करने की उम्मीद है। इस स्टेशन का निर्माण चरणों में किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 2028 में बेस मॉड्यूल के प्रक्षेपण से होगी, और उसके बाद 2035 तक इसे पूरी तरह कार्यात्मक बनाने के लिए अतिरिक्त मॉड्यूल का निर्माण किया जाएगा।

उद्देश्य और लाभ

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और पदार्थ विज्ञान में उन्नत अनुसंधान के लिए सुविधाएँ प्रदान करेगा, साथ ही जलवायु अध्ययन और आपदा प्रबंधन में सहायता के लिए पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को भी बढ़ाएगा। लंबी अवधि के मानव अंतरिक्ष उड़ान का समर्थन करके, बीएस भविष्य के गहन अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक आधारशिला के रूप में कार्य करेगा। इससे भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देने और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में नई पीढ़ियों को प्रेरित करने की भी उम्मीद है।

अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से सीख

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) भारत की अंतरिक्ष स्टेशन योजनाओं के लिए एक उपयोगी मिसाल पेश करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सदस्यों सहित 15 देशों के सहयोग से स्थापित, आईएसएस पृथ्वी की निचली कक्षा में सबसे बड़ी रहने योग्य संरचना बन गया है। इसने 100 से अधिक देशों के शोधकर्ताओं के 3,000 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोगों की मेजबानी की है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को दर्शाता है।

भारत की रणनीतिक बढ़त

अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाकर, भारत का लक्ष्य न केवल वैश्विक सुविधाओं पर निर्भरता कम करना है, बल्कि अपने नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के रास्ते भी खोलना है। प्रस्तावित चंद्र मिशन के साथ-साथ बीएस परियोजना, क्षेत्रीय अंतरिक्ष शक्ति से वैश्विक अंतरिक्ष प्रशासन में अग्रणी बनने की भारत की तत्परता को दर्शाती है। यह 2047 तक आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत भारत के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करेगी।

संस्कृति एवं इतिहास

मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया

श्री गंगानगर, राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा को 18 अगस्त, 2025 को जयपुर में आयोजित ग्रैंड फिनाले में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया। उन्हें यह ताज निर्वत्तमान विजेता रिया सिंघा ने प्रदान किया। मनिका अब नवंबर 2025 में थाईलैंड में आयोजित होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।

मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की उपविजेता

- तान्या शर्मा (उत्तर प्रदेश) - प्रथम उपविजेता
- महक ढींगरा (हरियाणा) - द्वितीय उपविजेता
- अमीशी कौशिक - तृतीय उपविजेता

मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफएम) 2025 पुरस्कार

मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफएम) 2025 के 16वें संस्करण का समापन नीरज घायवान की फिल्म होमबाउंड के सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक दोनों पुरस्कारों के साथ हुआ। भारत के बाहर सबसे बड़े भारतीय फिल्म महोत्सव माने जाने वाले इस महोत्सव ने फिल्मों, शृंखलाओं और लघु फिल्मों में सिनेमा की उत्कृष्टता का जश्न मनाया।

प्रमुख पुरस्कार

- सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक: नीरज घेवान की होमबाउंड
- सिनेमा में उत्कृष्टता पुरस्कार: आमिर खान
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (पुरुष - फिल्म): अभिषेक बच्चन (आई वांट टू टॉक)
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (महिला - फिल्म): गीता कैलासम (अंगमाल)
- सर्वश्रेष्ठ इंडी फिल्म: अंगमाल
- सर्वश्रेष्ठ शृंखला: ब्लैक वारंट (निर्देशक: विक्रमादित्य मोटवानी)
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (पुरुष - शृंखला): जयदीप अहलावत (पाताल लोक सीज़न 2)
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (महिला - शृंखला): निमिषा सजयन (डब्बा कार्टेल)
- डिसरेट पुरस्कार: वीर दास
- सिनेमा में विविधता पुरस्कार: अदिति राव हैदरी
- सिनेमा में नेतृत्व पुरस्कार: अरविंद स्वामी
- सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म (भारत): कलार पेंसिल्स (निर्देशक: धनंजय संतोष गोरेगांवकर)
- सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म (ऑस्ट्रेलिया): ड्रिफ्टर्स (निर्देशक: डेविड लियू)

आईएफएफएम 2025:

- संस्करण: 16वां
- स्थल: मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया
- भारत के बाहर सबसे बड़ा भारतीय फिल्म समारोह
- समापन तिथि: 24 अगस्त 2025
- समापन फिल्म: होमबाउंड

रक्षा वीरता एवं विशिष्ट सेवा पुरस्कार 2025

- अवसर: स्वतंत्रता दिवस 2025 की पूर्व संध्या
- द्वारा: राष्ट्रपति द्वौपदी मुर्मू
- स्वीकृत पुरस्कार: 127 वीरता पुरस्कार + 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कार + 290 मेंशन-इन-डिस्पैच

वीरता पुरस्कारों का विवरण

- कीर्ति चक्र: 4
- वीर चक्र: 15
- शौर्य चक्र: 16
- सेना पदक (वीरता) के लिए बार: 2
- सेना पदक (वीरता): 58
- नौसेना पदक (वीरता): 6
- वायु सेना पदक (वीरता): 26
- सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक: 7
- उत्तम युद्ध सेवा पदक: 9
- युद्ध सेवा पदक: 24

अतिरिक्त:

- मेंशन-इन-डिस्पैच: 290
- सेना - 115
- नौसेना - 5
- वायु सेना - 167
- सीमा सङ्करण विकास बोर्ड - 3
- तटरक्षक पदक: 5 (भारतीय तटरक्षक)
- प्रमुख पुरस्कार विजेता
- सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक (असाधारण युद्धकालीन सेवा)
- लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा - उत्तरी कमान
- लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई - डीजीएमओ
- वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह - नौसेना
- एयर मार्शल नमदिश्वर तिवारी - वायु सेना उप प्रमुख
- एयर मार्शल नागेश कपूर - एओसी-इन-सी एसडब्ल्यूएसी
- एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा - एओसी-इन-सी डब्ल्यूएसी
- एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती - डीजी एयर ऑप्स
- कीर्ति चक्र (दुश्मन से आमने-सामने की लड़ाई के अलावा विशिष्ट वीरता)
- कैटन लालरिनावमा सेलो - 4 पैरा (एसएफ), सेना
- लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी - सिक्किम स्काउट्स, सेना
- एल/एनके मीनाची सुंदरम ए - आर्टिलरी रेजिमेंट, सेना

- सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर - महार रेजिमेंट, सेना
- वीर चक्र (शत्रु की उपस्थिति में वीरता)
- कर्नल कोशांक लांबा - 302 मीडियम रेजिमेंट, सेना
- लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट - 1988 इंडिपेंडेंट मीडियम बैटरी, सेना
- नायब सूबेदार सतीश कुमार - 4 डोगरा, सेना
- राइफलमैन सुनील कुमार - 4 जम्मू-कश्मीर एलआई, सेना
- प्लस: 9 IAF फाइटर पायलट (ऑपरेशन सिंदूर)
- शौर्य चक्र (दुश्मन का सामना करने के अलावा अन्य वीरता)
- लेफ्टिनेंट कर्नल नीतेश भारती शुक्ला - 19 सिख, सेना
- मेजर भार्वि कलिता - कुमाऊं रेजिमेंट
- मेजर आशीष कुमार - 7 पैरा (एसएफ)
- मेजर आदित्य प्रताप सिंह - असम राइफल्स
- सहायक कमांडेंट मोहम्मद शाफीक - असम राइफल्स
- सूबेदार शमशेर सिंह - 4 पैरा (एसएफ)
- लांस नायक राहुल सिंह - 4 पैरा (एसएफ)
- राइफलमैन भोज राम साहू - असम राइफल्स
- युद्ध सेवा पदक (संचालन में विशिष्ट सेवा)
- मेजर जनरल संदीप सुदर्शन शारदा - सेना
- ब्रिगेडियर राकेश नायर - सेना
- ब्रिगेडियर विवेक गोयल - सेना
- ब्रिगेडियर सुरजीत कुमार सिंह - सेना
- ब्रिगेडियर सोनेदर सिंह - सेना
- ब्रिगेडियर विवेक पुरी - सेना
- ब्रिगेडियर मुदित महाजन - सेना
- सूबेदार विनोद कुमार - सेना
- नायब सूबेदार रलेश्वर घोष - सेना
- विशेष उल्लेख
- बीएसएफ: ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी के लिए 16 कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया
- भारतीय वायुसेना: लड़ाकू पायलटों और एस-400 सिस्टम ऑपरेटरों को वीरता पुरस्कार (ऑपरेशन सिंदूर)

प्रधानमंत्री ने खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक एम. एस. स्वामीनाथन पुरस्कार की शुरुआत की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर एम. एस. स्वामीनाथन की स्मृति में एक वैश्विक पुरस्कार की शुरुआत की। यह पुरस्कार विकासशील देशों के उन वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने "खाद्य एवं शांति" में योगदान दिया है। यह घोषणा नई दिल्ली में एम. एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान की गई। पहला एम. एस. स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार नाइजीरियाई वैज्ञानिक डॉ. एरेनारे को नाइजीरिया में भुखमरी से निपटने में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया।

एम. एस. स्वामीनाथन के बारे में

- पूरा नाम: मोनकोम्बु संबासिवन स्वामीनाथन
- जन्म: 7 अगस्त 1925

- मृत्यु: 23 सितंबर 2023 (आयु 98 वर्ष)
- भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रसिद्ध
- प्रमुख योगदान: भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के आंदोलन का नेतृत्व किया।
- अवधारणा प्रस्तुत: "जैव-खुशी" - जैव विविधता संरक्षण को मानवीय खुशी से जोड़ना।
- पुरस्कार: 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न।

पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ को लगातार दूसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ रोट्टो पुरस्कार मिला

पीजीआईएमईआर (स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान) ने लगातार दूसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (रोट्टो) पुरस्कार जीता। 2019 में इस पुरस्कार की शुरुआत के बाद से यह संस्थान का तीसरा राष्ट्रीय रोट्टो पुरस्कार है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में 15वें भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया, जिसका आयोजन एनओटीटीओ (राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन) द्वारा किया गया था।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पीजीआईएमईआर टीम को यह पुरस्कार प्रदान किया।

ROTTO पुरस्कार

- पूर्ण रूप: क्षेत्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन पुरस्कार
- द्वारा प्रदान किया गया: NOTTO (राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन)
- उद्देश्य: अंगदान और प्रत्यारोपण समन्वय में उल्लंघन के लिए क्षेत्रीय संस्थानों को सम्मानित करना
- पुरस्कार: भारतीय अंगदान दिवस
- मानदंड: नैतिक दाता प्रबंधन, मस्तिष्क मृत्यु घोषणा, क्षेत्रीय जागरूकता और प्रत्यारोपण सुविधा

71वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 2025

71वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में की गई। विधु विनोद चोपड़ा की फ़िल्म "द ट्रैटीथ फ़ेल" ने सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फ़िल्म का पुरस्कार जीता, जबकि सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार "जवान" के लिए शाहरुख खान और "द ट्रैटीथ फ़ेल" के लिए विक्रांत मैसी को साझा रूप से मिला। वहीं, रानी मुखर्जी को "मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे" में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

- सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फ़िल्म: 12वीं फेल
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (साझा):
- शाहरुख खान (जवान)
- विक्रांत मैसी (12वीं फेल)
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री: रानी मुखर्जी (मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे)
- सर्वश्रेष्ठ निर्देशक: सुदीपो सेन (द केरल स्टोरी)

सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता:

- विजयराघवन (पुक्कलम)
- मुख्यपेट्रुई सोमू भास्कर (पार्किंग)

सबसे अच्छी सह नायिका:

- उर्वशी (उल्लोझुक्कू)
- जानकी बोदीवाला (वाश)
- संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म: रॉकी और रानी की प्रेम कहानी
- सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म: कथाल: ए जैकफूट मिस्ट्री
- सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म: उल्लोझुक्कू
- सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म: पार्किंग
- सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म: भगवंत के सरी
- राष्ट्रीय एवं सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म: सैम बहादुर

सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार:

- सुकृति वेणी बांद्रेड्डी
- कबीर खानदाने
- त्रिश ठोसर
- सर्वश्रेष्ठ गीत: बालागम
- सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन (गीत): वाथी (तमिल)
- सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर: एनिमल-हर्षवर्धन रामेश्वर
- सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी: ढिढोरा बाजे रे - वैभवी मर्चंट
- सर्वश्रेष्ठ मेक-अप आर्टिस्ट: श्रीकांत देसाई (सैम बहादुर)
- सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन: सैम बहादुर - सचिन लोवालेकर, दिव्या, निधि गंभीर
- सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन: हनु-मन (तेलुगु)

भाषा के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्में

- असमिया: रोंगतापु 1982
- बंगाली: डीप फ्रिज
- हिंदी: कटहल
- कन्नड़: कंदील्यु
- मलयालम: उल्लोझुक्कू
- मराठी: श्यामची आई
- उडिया: पुष्कर
- पंजाबी: गोडडे गोडडे चा
- तमिल: पार्किंग
- तेलुगु: भगवंत के सरी
- गुजराती: वाश
- ताई फेक: पै तांग... का कदम आशा
- गारो: रिमडोगिटांगा

गैर-फीचर फिल्म श्रेणी की मुख्य विशेषताएं

- सर्वश्रेष्ठ गैर-काल्पनिक फिल्म: फ्लावरिंग मैन
- सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म: गिर्द - द स्कैवेंजर
- सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फिल्म: गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन
- सामाजिक/पर्यावरणीय मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म: द साइलेंट एपिडेमिक
- सर्वश्रेष्ठ कला एवं संस्कृति फिल्म: टाइमलेस तमिलनाडु
- निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म: द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चेराव

- सर्वश्रेष्ठ जीवनी फिल्म: मो बौ मो गान, लैंटिना एओ

विशेष उल्लेख

- नेकल - क्रॉनिकल ऑफ द पैडी मैन
- द सी एंड द सेवन विलेजेज
- अन्य उल्लेखनीय तथ्य
- पुरस्कार प्राप्ताता: 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 2023 के बीच सीबीएफसी द्वारा प्रमाणित फिल्में
- पुरस्कार समारोह स्थल: राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली
- निर्माता रॉनी स्कूवाला की फिल्मों सैम बहादुर और उल्लोझुक्कू ने प्रमुख पुरस्कार जीते

संसदीय प्रदर्शन के लिए 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

सत्रह सांसदों को उनके उल्लेख प्रदर्शन के लिए नई दिल्ली में संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया।

मुख्य विशेषताएं:

- उद्देश्य: उल्लेख और निरंतर संसदीय प्रदर्शन के लिए सांसदों को सम्मानित करना।
- आयोजक: प्राइम पॉइंट फाउंडेशन (एनजीओ)।
- आधार: 16वीं लोकसभा के बाद से उच्च प्रदर्शन; तीन कार्यकालों में निरंतर उल्लेखना के लिए विशेष जूरी पुरस्कार।

उल्लेखनीय विजेता:

- भर्तृहरि महताब - भाजपा, ओडिशा
- एन.के. प्रेमचंद्रन - रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, केरल
- सुप्रिया सुले - एनसीपी-शरद पवार, महाराष्ट्र
- श्रीरंग अप्पा बार्न-शिवसेना, महाराष्ट्र
- रवि किशन- बीजेपी
- निशिकांत दुबे- बीजेपी
- अरविंद सावंत-शिवसेना (यूबीटी)
- स्मिता उदय वाघ - बीजेपी
- नरेश महस्के-शिवसेना
- वर्षा गायकवाड़ - कांग्रेस
- मेधा कुलकर्णी- बीजेपी
- प्रवीण पटेल- बीजेपी
- विद्युत बरन महतो - भाजपा
- दिनेश शर्मा- बीजेपी
- दिलीप सैकिया - बीजेपी
- पी.पी. चौधरी-बीजेपी
- मदन राठोड़- बीजेपी
- सी.एन. अन्नादुर्दई - डीएमके

समिति पुरस्कार:

- वित्त संबंधी स्थायी समिति (अध्यक्ष: भर्तृहरि महताब) - प्रभावशाली रिपोर्टों के लिए
- कृषि संबंधी स्थायी समिति (अध्यक्ष: चरणजीत सिंह चन्नी) - विधायी निगरानी के लिए

इसरो प्रमुख डॉ. वी. नारायणन को जीपी बिड़ला स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया

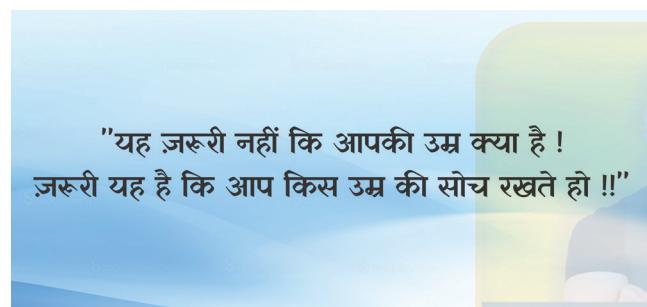
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉ. वी. नारायणन को प्रतिष्ठित जीपी बिड़ला स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

पुरस्कार का महत्व:

इसे पहले लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। यह पुरस्कार शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में योगदान के लिए जाने जाने वाले दूरदर्शी व्यक्ति जीपी बिड़ला की स्मृति में स्थापित किया गया था।

सम्मान समारोह:

जीपी बिड़ला पुरातत्व, खगोलीय और वैज्ञानिक संस्थान की अध्यक्ष निर्मला बिड़ला द्वारा संचालित।



QUIT INDIA MOVEMENT DAY

CURRENT

By: Mahatma Gandhi

8 August

Importance

To mark the inception of the Quit India Movement that was launched at the Bombay session of the All India Congress Committee on August 8, 1942.

Motto

To pay tribute to freedom fighters with national integration speeches and other events.

Also Known as

August Kranti or Bharat Chodo Andolan.

Note

- The Quit India Movement took place right in the middle of World War II.
- In 1992 RBI issued a 1 rupee commemorative coin to mark the Golden Jubilee of the movement.



पुरस्कार विरासतः

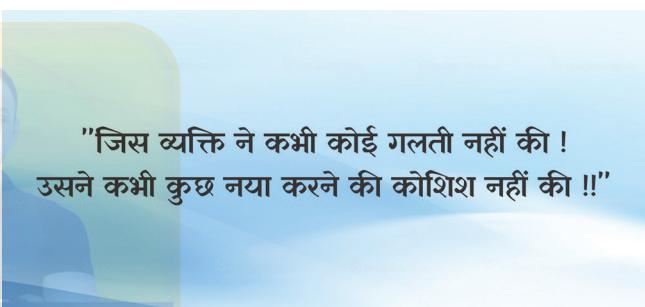
32 नोबेल पुरस्कार विजेताओं सहित कई प्रतिष्ठित वैश्विक हस्तियों को प्रदान किया गया।

उल्लेखनीय पूर्व प्राप्तकर्ता:

- डॉ. वैंकटरमन रामकृष्णन - रसायन विज्ञान में भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता
- प्रो. जोगेश पति - प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी
- डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम - भारत के पूर्व राष्ट्रपति
- डॉ. के. कस्तुरीरंगन - इसरो के पूर्व अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव

डॉ. नारायणन की भूमिका:

भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख के रूप में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित।



NAGASAKI DAY

Edition: 80th

9 August

Importance

To pay tribute to the victims of the people who died when US dropped atomic bomb on the Nagasaki city of Japan in 1945 during World War II.

History Behind

- Bomb that was dropped on Nagasaki was known as "Fat Man".
- The "Fat Man" bomb was plutonium based nuclear bomb.
- This bomb was more powerful than used at Hiroshima.
- The weight of the bomb was nearly 10,000 pounds and was built to produce a 22-kiloton blast.

Note

After this Japan surrendered to US in World War II.

खेल-कूट

नॉर्थईस्ट यूनाइटेड ने 134वां द्वूरंड कप 2025 जीता

नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी (NEUFC) ने कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में पहली बार खेल रही डायमंड हार्बर एफसी (DHFC) को हराया। इसके साथ ही, NEUFC ने अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया और द्वूरंड कप के 137 साल के इतिहास में मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और सीमा सुरक्षा बल के बाद ट्रॉफी जीतने वाली चौथी टीम बन गई।

प्रमुख प्रदर्शन

NEUFC के लिए गोल अशीर अख्तर (30वें मिनट), पार्थिव गोगोई (45+1वें मिनट), थोई सिंह (50वें मिनट), जाइरो सैम्पेरियो (82वें मिनट), आंद्रे रेडिंग्ज (86वें मिनट) और अलाउद्दीन अजराय (90+3वें मिनट पेनल्टी) ने किए। DHFC के लिए एकमात्र गोल लुका माजसेन ने 68वें मिनट में किया।

पुरस्कार और पुरस्कार राशि

- विजेता (NEUFC): ₹1.21 करोड़
 - उपविजेता (DHFC): ₹60 लाख
 - गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट: अलाउद्दीन अजराय (टूर्नामेंट में 8 गोल, भारत में 40 मैचों में 40 गोल)
 - गोल्डन ग्लोब: गुरमीत सिंह (NEUFC)
 - व्यक्तिगत पुरस्कार: ₹3 लाख प्रत्येक + महिंद्रा XUV 3XO
- ऐतिहासिक महत्व**
- द्वूरंड कप: एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट, 1888 (शिमला) में शुरू हुआ, वर्तमान में 137 साल पुराना है।
 - NEUFC सात पूर्वत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र ISL टीम है।
 - स्वामी: जॉन अब्राहम (बॉलीवुड अभिनेता)
 - कोच: जुआन पेड्रो बेनाली।

अजीत अगरकर का कार्यकाल बढ़ा

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर का कार्यकाल जून 2026 तक बढ़ा दिया है। उनका कार्यकाल जून 2023 में शुरू हुआ था, जिसके दौरान भारत ने टी20 विश्व कप 2024 और चैपियंस ट्रॉफी 2025 जीतकर आईसीसी टूर्नामेंटों में अपनी जीत का सुखा खत्म किया। भारत घेरे लू मैदान पर 2023 के एकदिवसीय विश्व कप के फाइनल में भी पहुँचा और टेस्ट क्रिकेट में भी आसानी से बदलाव किया।

उनके अध्यक्ष पद के दौरान, टीम इंडिया एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजरी:

विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन की विदाई (अश्विन ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, जबकि कोहली और

रोहित अब केवल एकदिवसीय मैच खेलते हैं)। नए कप्तान नियुक्त: शुभमन गिल (टेस्ट) और सूर्यकुमार यादव (टी20ई)।

वर्तमान सीनियर चयन समिति

- अजीत अगरकर (अध्यक्ष)
- एसएस दास
- सुब्रतो बनर्जी
- अजय रात्रा
- एस शरथ

बीसीसीआई:

- स्थापना: दिसंबर 1928
- मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
- वर्तमान राष्ट्रपति: रोजर बिन्नी
- वर्तमान सचिव: देवजीत सैकिया

कार्लोस अल्काराज़ ने सिनसिनाटी ओपन 2025 का पहला खिताब जीता

अमेरिका के ओहायो में आयोजित सिनसिनाटी ओपन (एटीपी मास्टर्स 1000) में, विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्काराज़ ने पुरुष एकल का खिताब जीता। उन्होंने गत चैपियन और विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के जैनिक सिनर को हराया।

महत्व:

अल्काराज़ ने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता। कार्लोस मोया और राफेल नडाल के बाद सिनसिनाटी खिताब जीतने वाले तीसरे स्पेनिश खिलाड़ी बने। यह उनके करियर का 22वां खिताब था। मास्टर्स 1000 स्तर पर अपने अपराजित अभियान को 17 मैचों तक बढ़ाया। 2025 में एटीपी टूर में 6 खिताब जीते, जिनमें 4 बड़े खिताब शामिल हैं। मोंटे-कार्लो, रोम, सिनसिनाटी (2025) में मास्टर्स 1000 खिताब। रोलैंड गैरोस 2025 में ग्रैंड स्लैम खिताब जीता।

सिनसिनाटी ओपन:

इसे वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन भी कहा जाता है। अमेरिका के अपने मूल शहर में खेला जाने वाला सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट (1899 से)। एटीपी मास्टर्स 1000 सीरीज़ और डब्ल्यूटीए 1000 सीरीज़ का हिस्सा।

- संस्करण: 124वाँ (पुरुष) / 97वाँ (महिला)
- श्रेणी: एटीपी टूर मास्टर्स 1000 (पुरुष) और डब्ल्यूटीए 1000 (महिला)
- स्थान: मेसन, ओहायो, अमेरिका

2025 विजेता:

- पुरुष एकल: कार्लोस अल्काराज़
- महिला एकल: इगा स्वियाटेक
- पुरुष युगल: निकोला मेकटिक / राजीव राम
- महिला युगल: गैब्रिएला डाब्रोव्स्की / एरिन रूटलिफ़

भारतीय शटलर देविका सिहाग ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 जीता

देविका सिहाग (20 वर्ष) ने मलेशिया के इपोह में आयोजित मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल स्पर्धा जीतकर अपना पहला इंटरनेशनल चैलेंज खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में पाँचवीं वरीयता प्राप्त इशारानी बरुआ (भारत) को 15-7, 15-12 के स्कोर से हराया। यह टूर्नामेंट BWF के प्रायोगिक 3×15 स्कोरिंग प्रारूप (सामान्य 21 अंकों के बजाय 15 अंकों तक खेले गए खेल) के तहत खेला गया था। यह स्वीडिश ओपन 2024 और पुर्तगाल इंटरनेशनल 2024 (दोनों इंटरनेशनल सीरीज़ इवेंट) जीतने के बाद उनकी सफलता की श्रृंखला में और इजाफा करता है। वह बैंगलुरु में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैपियनशिप 2024 की भी विजेता हैं।

BWF (बैडमिंटन विश्व महासंघ)

- मुख्यालय: कुआलालंपुर, मलेशिया
- अध्यक्ष: पॉल-एरिक होयर लार्सन

नम्रता बत्रा ने विश्व खेलों में भारत का पहला वुशु पदक जीता

भारत की नम्रता बत्रा ने चीन के चेंगदू में 2025 के विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। यह विश्व खेलों में वुशु में भारत का पहला पदक है।

विश्व खेलों के इतिहास में भारत की कुल पदक तालिका:

- स्वर्ण: 1
- रजत: 2 (नम्रता सहित)
- कांस्य: 4

वुशु:

- मूल: चीन (पारंपरिक मार्शल आर्ट और युद्ध खेल)
- शासी निकाय: अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ (IWUF)

विश्व खेल:

- पहली बार आयोजित: 1981 (सांता क्लारा, अमेरिका)
- आवृत्ति: हर 4 साल में
- आयोजक: अंतर्राष्ट्रीय विश्व खेल संघ (IWGA)
- उद्देश्य: ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं होने वाले खेलों/प्रतियोगिताओं को प्रदर्शित करना

एशियाई सर्फिंग चैपियनशिप 2025

तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एशियाई सर्फिंग चैपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया, जहाँ भारतीय सर्फर रमेश बुधियाल ने ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। वह इस स्पर्धा के पदक दौर तक पहुँचने वाले पहले भारतीय भी बने।

ऐतिहासिक उपलब्धि

रमेश बुधियाल ने 12.60 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता, जो भारतीय सर्फिंग के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ।

विजेता

- स्वर्ण: कनोआ हीजे (कोरिया) – 15.17 अंक
- रजत: पजार अरियाना (इंडोनेशिया) – 14.57 अंक
- कांस्य: रमेश बुधियाल (भारत) – 12.60 अंक

कैनेडियन ओपन: म्बोको ने ओसाका को हराकर पहला WTA 1000 खिताब जीता

18 वर्षीय कनाडाई वाइल्ड कार्ड विजेता विक्टोरिया म्बोको ने चार बार की ग्रैंड स्लैम चैपियन नाओमी ओसाका को हराकर कैनेडियन ओपन जीता। यह म्बोको का पहला WTA 1000 खिताब है, और उन्होंने इसे मॉन्ट्रियल में अपने घरेलू मैदान पर जीता।

श्रीर्ष चैपियन को हराना

म्बोको ने एक ही टूर्नामेंट में चार ग्रैंड स्लैम चैपियन को हराया:

- सोफिया केनिन
- कोको गॉफ (विश्व नंबर 1 वरीयता प्राप्त)
- एलेना रयबाकिना (विश्व नंबर 3 वरीयता प्राप्त)
- नाओमी ओसाका

2025 नेशनल बैंक ओपन

- संस्करण: 135वाँ (पुरुष) / 123वाँ (महिला)
- श्रेणी: एटीपी टूर मास्टर्स 1000 (पुरुष) और डब्ल्यूटीए 1000 (महिला)
- पुरस्कार राशि: \$9,193,540 (पुरुष) और \$5,152,599 (महिला)

2025 चैपियन:

- पुरुष एकल: बेन शेल्टन (संयुक्त राज्य अमेरिका)
- महिला एकल: विक्टोरिया म्बोको (कनाडा)
- पुरुष युगल: जूलियन कैश / लॉयड ग्लासपूल (यूनाइटेड किंगडम)
- महिला युगल: कोको गॉफ / मैककार्टनी केसलर (संयुक्त राज्य अमेरिका)

हॉकी: पैन अमेरिकन कप 2025 में अर्जेंटीना का जलवा

पैन अमेरिकन कप 2025 उरुवे के मोटेवीडियो में संपन्न हुआ, जिसमें अर्जेंटीना की पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोनों प्रतियोगिताओं में रजत पदक जीत, जबकि कनाडा की पुरुष और उरुवे की महिला टीमों ने कांस्य पदक जीते।

विश्व कप योग्यता

एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा।

योग्य टीमें (पैन अमेरिकन कप से):

- पुरुष: अर्जेंटीना (चैपियन)
- महिला: अमेरिका (उपविजेता; अर्जेंटीना पहले ही प्रो लीग के माध्यम से क्लासीफाई कर चुका है)

अन्य योग्य टीमें:

- मेजबान: बेल्जियम और नीदरलैंड
- प्रो लीग विजेता (2023-24): ऑस्ट्रेलिया
- अब इसमें शामिल हैं: अर्जेंटीना (पुरुष)

2025 पुरुष पैन अमेरिकन कप

- मेजबान देश: उरुग्वे
- शहर: मोंटेवीडियो
- टीमें: 8 (1 संघ से)
- चैपियन: अर्जेंटीना (पाँचवाँ खिताब)
- उपविजेता: संयुक्त राज्य अमेरिका
- तीसरा स्थान: कनाडा
- शीर्ष स्कोरर: टॉमस डोमेने (अर्जेंटीना) (13 गोल)

फँर्मूला 1: नॉरिस ने पियास्ती की चुनौती को दरकिनार कर हंगेरियन ग्रां प्री जीत ली, मैकलारेन 1-2 से बराबरी पर रहा

- विजेता: लैंडो नॉरिस (मैकलारेन) ने एक चतुर वन-स्टॉप रणनीति के साथ रेस जीती।
- दूसरा स्थान: ऑस्कर पियास्ती (मैकलारेन) रेस के आखिर में कड़ी टक्कर के बाद उनके ठीक पीछे रहे।
- पोल पोजिशन: चार्ल्स लेक्लर (फेरारी) ने पहले चरण में शुरूआत की और शुरूआती चरणों में बढ़त बनाए रखी।
- शुरूआती रेस: लेक्लर पहले पिट स्टॉप के बाद पियास्ती से आगे रहे।

हंगेरियन ग्रां प्री

- आयोजित संख्या: 41
- पहली बार आयोजित: 1936
- सबसे ज्यादा जीत (ड्राइवर): लुईस हैमिल्टन (8)
- सबसे ज्यादा जीत (कंस्ट्रक्टर): मैकलारेन (13)

2025 के विजेता

1. एल. नॉरिस मैकलारेन-मर्सिडीज
2. ओ. पियास्ती मैकलारेन-मर्सिडीज
3. जी. रसेल मर्सिडीज

दिव्या देशमुख ने रचा इतिहास: FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता

19 वर्षीय दिव्या देशमुख ने जॉर्जिया के बटुमी में आयोजित फ़ाइनल के रैपिड टाईब्रेक में भारत की नंबर 1 और मौजूदा विश्व रैपिड चैपियन कोनेरू हम्पी को हराकर FIDE महिला विश्व कप जीत लिया।

टूर्नामेंट का सफर:

15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी के रूप में प्रवेश किया। पूरे टूर्नामेंट में कई उच्च रैकिंग वाली अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को हराया। क्लासिक फ़ाइनल गेम दो डॉ पर समाप्त हुए।

ग्रैंडमास्टर का खिताब हासिल किया:

इस जीत के साथ, दिव्या ने अपना अंतिम ग्रैंडमास्टर (जीएम) मानदंड हासिल कर लिया। जीएम खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला और कुल मिलाकर 88वीं भारतीय बन गई।

आयु का पड़ाव:

मात्र 19 वर्ष की आयु में, दिव्या ने भारतीय शतरंज में इतिहास रच दिया है।

मोटर रेसिंग- वेरस्टैपेन ने स्पा स्प्रिंट जीत के साथ रेड बुल के नए युग की शुरूआत की

फ़ॉर्मूला 1 वन चैपियन मैक्स वेरस्टैपेन ने लॉरेंट मेकीज़ के नेतृत्व में रेड बुल की पहली रेस में 2025 बेल्जियम ग्रां प्री स्प्रिंट जीती।

- पोडियम: ऑस्कर पियास्ती (मैकलारेन) दूसरे, लैंडो नॉरिस (मैकलारेन) तीसरे
- स्प्रिंट: स्पा-फ्रैकोरचैम्प्स में 100 किमी, सबसे लंबा और दूसरा सबसे तेज़ टैक
- वर्स्टैपेन ने पहले लैप पर पियास्ती को पीछे छोड़ा, 15 लैप में 0.753 सेकंड की बढ़त बनाए रखी
- मई की इमोला रेस के बाद वर्स्टैपेन की पहली स्प्रिंट या ग्रां प्री जीत

2025 बेल्जियम ग्रां प्री विजेता

1. ऑस्कर पियास्ती मैकलारेन-मर्सिडीज
2. लैंडो नॉरिस मैकलारेन-मर्सिडीज
3. चार्ल्स लेक्लर फेरारी

अन्य प्रदर्शन:

- चार्ल्स लेक्लर चौथे स्थान पर रहे, नॉरिस से कुछ देर आगे रहे
- मर्सिडीज को संघर्ष करना पड़ा: जॉर्ज रसेल 12वें, किमी एंटोनेली 17वें
- लुईस हैमिल्टन (फेरारी) 18वें स्थान से शुरूआत करने के बाद 15वें स्थान पर रहे

इंग्लैंड महिलाओं ने यूरो 2025 जीता: एक ऐतिहासिक जीत

यूर्झाएफए महिला यूरो 2025 के फाइनल में इंग्लैंड ने विश्व चैपियन स्पेन को हराया।

स्थान: बासेल, स्विटज़रलैंड

ऐतिहासिक उपलब्धि:

- लगातार दो बार चैपियन: यूर्झाएफए महिला यूरो खिताब बरकरार रखने वाली केवल दूसरी टीम।
- पहली उपलब्धि: अपना पहला मैच हारने के बाद यूरो जीतने वाली पहली टीम।
- पहला विदेशी मेजर खिताब: विदेशी धरती पर कोई बड़ी ट्रॉफी जीतने वाली पहली इंग्लैंड सीनियर टीम (पुरुष या महिला)।



निधन

भारतीय मूल के ब्रिटिश उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का निधन



कपारो समूह के संस्थापक, भारतीय मूल के ब्रिटिश उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का 94 वर्ष की आयु में लंदन में निधन हो गया।

प्रारंभिक जीवन

- जालंधर, पंजाब (भारत) में जन्मे।
- 1960 के दशक में अपनी बेटी अंबिका के कैंसर के इलाज के लिए यूके चले गए।
- 4 वर्ष की आयु में अंबिका की मृत्यु के बाद, उन्होंने अंबिका पॉल फाउंडेशन की स्थापना की, जो बच्चों और युवाओं के कल्याण के लिए एक धर्मार्थ ट्रस्ट है।

व्यावसायिक करियर

लंदन में मुख्यालय वाली एक बहुराष्ट्रीय इस्पात और इंजीनियरिंग कंपनी, कपारो समूह की स्थापना की। कपारो यूके, उत्तरी अमेरिका, भारत और मध्य पूर्व में 40 से अधिक स्थानों से संचालित होता है। उनके पुत्र आकाश पॉल, कपारो इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष और कपारो समूह के निदेशक हैं।

मान्यता और संपत्ति

संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2024 में 2 बिलियन GBP की अनुमानित संपत्ति के साथ 81वें स्थान पर।

यूके के भारतीय प्रवासियों के सबसे धनी और प्रभावशाली सदस्यों में से एक।

नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन



नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का 80 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया।

राजनीतिक जीवन

ला गणेशन भाजपा के एक वरिष्ठ नेता थे जिनका सार्वजनिक जीवन से लंबा जुड़ाव था। उन्हें फरवरी 2023 में नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इससे पहले, उन्होंने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। उन्होंने कुछ समय के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था।

राज्यपाल के पद के बारे में

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का प्रावधान है।

- **कार्यकाल:** सामान्यतः 5 वर्ष (लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर)।
- **नियुक्ति:** भारत के राष्ट्रपति द्वारा।
- **राज्य के संवैधानिक प्रमुख और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि** के रूप में कार्य करता है।

स्पांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति का 74 वर्ष की आयु में निधन



2021 से स्पांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे मिंट स्वे का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

मृत्यु का कारण: तंत्रिका संबंधी और तंत्रिका अपक्षीय विकारों से लंबी बीमारी। जुलाई 2024 से वे गंभीर रूप से बीमार थे, और उन्हें बुखार, संज्ञानात्मक गिरावट और भूख न लगने जैसे लक्षण थे।

कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना

सेना द्वारा निर्वाचित नागरिक सरकार को अपदस्थ करने के बाद, 1 फरवरी, 2021 को पदभार ग्रहण किया। राष्ट्रपति विन मिंट और आंग सान सू की की नज़रबंदी के बाद, तख्तापलट के कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रपति बने। वे पहले उपराष्ट्रपति और सैन्य समर्थक यूएसडीपी पार्टी के सदस्य थे।

नियुक्ति पर विवाद

कानूनी विशेषज्ञों ने उनकी वैधता पर सवाल उठाया क्योंकि विन मिंट ने इस्तीफा नहीं दिया था या उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया गया था। नियुक्ति ने सैन्य नेतृत्व वाली राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद को आपातकाल की स्थिति घोषित करने की अनुमति दी। इससे प्रभावी रूप से सैन्य प्रमुख मिन आंग हाइंग को पूर्ण नियंत्रण मिल गया।

राष्ट्रपति के रूप में भूमिका

अधिकांशतः औपचारिक शक्तियाँ धारण कीं; मुख्य कार्य आपातकालीन शासन को बढ़ाने के लिए आदेश जारी करना था। वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण मिन अंग ह्लाइंग के पास रहा।

सैन्य करियर और प्रमुख घटनाएँ

दशकों तक म्यांमार की सेना में सेवा की; पूर्व जुंटा नेता थान श्वे के निकट सहयोगी। 2011 से 2016 तक यांगून क्षेत्र के मुख्यमंत्री। 2007 में भिक्षुओं के नेतृत्व वाले भगवा क्रांति विरोध प्रदर्शनों के दौरान यांगून की क्षेत्रीय सेना के कमांडर, जिन्हें हिंसक रूप से कुचल दिया गया था।

प्रमुख दमन अभियानों में शामिल:

2002 में पूर्व तानाशाह ने विन के परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी।

2004 में सैन्य शुद्धिकरण के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री खिन च्युंट को हिरासत में लिया गया। बाद में म्यांमार की सैन्य खुफिया सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।

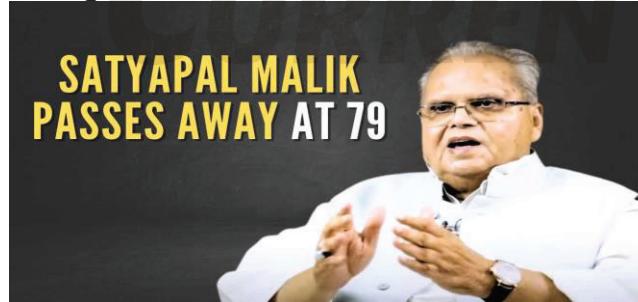
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और विरासत

2021 के तख्तापलट के बाद, अमेरिकी वित्त विभाग ने लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया। उनकी मृत्यु ऐसे समय में हुई है जब म्यांमार में नागरिक अशांति और सशस्त्र प्रतिरोध जारी है। सैन्य जुंटा ने 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में चुनाव कराने की योजना की घोषणा की है।

म्यांमार:

- राजधानी: नेपीडॉ
- मुद्रा: म्यांमार क्यात
- आधिकारिक भाषा: बर्मी

जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का 79 वर्ष की आयु में निधन



जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का लंबी बीमारी के बाद नई दिल्ली में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

राजनीतिक जीवन की मुख्य विशेषताएँ:

5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के दौरान जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल (2018-2019) के रूप में कार्य किया।

राज्यपाल के पदों पर रहे:

- बिहार (2017)
- जम्मू और कश्मीर (2018-2019)
- गोवा (2019-2020)
- मेघालय (2020-2022)

पूर्व केंद्रीय संसदीय कार्य और पर्यटन राज्य मंत्री (1989-1990) अपने करियर के विभिन्न चरणों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य।

राजनीतिक यात्रा:

1974 में बागपत से विधायक के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। भारतीय क्रांति दल, लोकदल, कांग्रेस, जनता दल और भाजपा से जुड़े। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हुए।

संसदीय भूमिका:

मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान भूमि अधिग्रहण का विरोध करने वाले एक संसदीय पैनल का नेतृत्व किया। अधिग्रहण विधेयक

बाद के वर्ष:

सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र सरकार के मुखर आलोचक बने किसानों के विरोध प्रदर्शनों का समर्थन किया और पुलवामा हमले (2019) से निपटने की आलोचना की, खुफिया विफलता और सच्चाई को दबाने का आरोप लगाया।

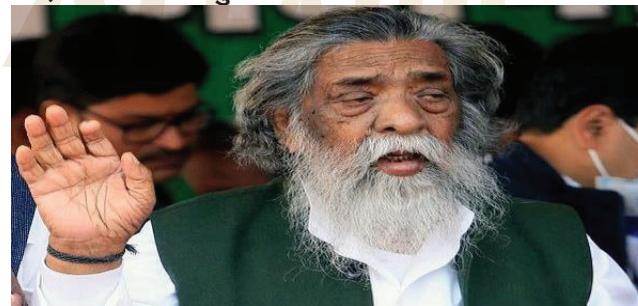
जम्मू और कश्मीर

केंद्र शासित प्रदेश: 31 अक्टूबर 2019 से (अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद)

सीमाएँ:

- भारत: हिमाचल प्रदेश, पंजाब, लद्दाख
- अंतर्राष्ट्रीय: पाकिस्तान, चीन (नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा)
- नदियाँ: झेलम, चिनाब, रावी, तवी
- महत्वपूर्ण झीलें: डल झील, वुलर झील, मानसर झील

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का लंबी बीमारी के बाद 81 वर्ष की आयु में निधन



झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन का लंबी बीमारी के बाद 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे गुर्जे की बीमारी से पीड़ित थे और डेढ़ महीने पहले उन्हें स्टोक भी हुआ था। पिछले एक महीने से वे जीवन रक्षक प्रणाली पर थे।

राजनीतिक यात्रा

प्रारंभिक सक्रियता:

18 वर्ष की आयु में संथाल नवयुवक संघ की स्थापना की।

1972 में, ए.के. राय और बिनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की सह-स्थापना की।

झारखंड आंदोलन:

एक अलग आदिवासी राज्य की मांग में केंद्रीय भूमिका निभाई।

लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए, 2000 में झारखंड को आधिकारिक तौर पर बिहार से अलग कर दिया गया।

नेतृत्वकारी भूमिकाएँ

ज्ञामुग्नी अध्यक्ष: 1987 में पदभार ग्रहण किया, अप्रैल 2025 तक निविवाद नेता रहे।

झारखंड के मुख्यमंत्री:

- पहला कार्यकाल: मार्च 2005 (बहुमत की कमी के कारण 9 दिन तक चला)।
- दूसरा कार्यकाल: अगस्त 2008 - जनवरी 2009।
- तीसरा कार्यकाल: दिसंबर 2009 - मई 2010।
- राजनीतिक अस्थिरता के कारण कभी पूरा कार्यकाल पूरा नहीं किया।

संसदीय करियर:

1980 से 2005 के बीच आठ बार लोकसभा के लिए चुने गए। राज्यसभा में तीन बार कार्यकाल दिया। राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख आदिवासी प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं।

केंद्रीय कैबिनेट मंत्री:

2004 से 2006 के बीच तीन बार केंद्र सरकार में कोयला मंत्रालय का कार्यभार संभाला।

उपाधियाँ और प्रभाव

अपने समर्थकों के बीच प्यार से 'टिशूम गुरु' के नाम से जाने जाते हैं। झारखंड की राजनीति में एक प्रमुख आदिवासी नेता और संस्थापक व्यक्ति के रूप में देखे जाते हैं। भूमि और आदिवासी अधिकारों के लिए, विशेष रूप से शोषक जमींदारों के विरुद्ध, संघर्ष किया।

विवाद और कानूनी मुद्दे

1975 के चिरुडीह नरसंहार और 1994 में अपने निजी सचिव की हत्या के आरोपी; बाद में बरी। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई दोषसिद्धि दर्ज नहीं की गई।

आईडीबीआई के अध्यक्ष और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित टी एन मनोहरन का निधन



भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के पूर्व अध्यक्ष और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित टी एन मनोहरन का निधन हो गया है।

पेशेवर योगदान:

आईसीएआई अध्यक्ष: 2006-07

आईसीएआई का लेखा अनुसंधान प्रतिष्ठान

- भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की राष्ट्रीय लेखा मानक समिति
- बोर्ड की सदस्यताएँ और समितियाँ:
- भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) (2006-07)

प्रख्यात अर्थशास्त्री मेघनाद देसाई का 85 वर्ष की आयु में लंदन में निधन



प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, लेखक और ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य, लॉर्ड मेघनाद देसाई का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

विरासत: प्रख्यात अर्थशास्त्री, लेखक, ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य और भारत-ब्रिटेन संबंधों के पैरोकार।

योगदान:

- 200 से अधिक शैक्षणिक शोधपत्र और 8 पुस्तकें
- प्रमुख कृतियाँ: मार्क्सवादी आर्थिक सिद्धांत, मार्क्स का प्रतिशोध, भारत की पुनर्जोन, भगवद् गीता किसने लिखी?
- विषय: मार्क्सवादी अर्थशास्त्र, आर्थिक विकास, वैश्वीकरण
- राजनीतिक एवं सार्वजनिक सेवा

हाउस ऑफ लॉर्ड्स:

- 1991 में नियुक्त
- भारतीय मूल के पहले लेबर पार्टी के सदस्य
- विश्वास: ब्रिटेन की राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष सोसायटी के मानद सहयोगी, धर्मनिरपेक्ष और मानवतावादी मूल्यों को दर्शाते हुए।

भारत-ब्रिटेन संबंधों में योगदान

मुंबई में मेघनाद देसाई अर्थशास्त्र अकादमी की स्थापना लंदन के पार्लियामेंट स्कायर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा की स्थापना सहित सांस्कृतिक कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

क्योटो प्रोटोकॉल के निर्माता और भारत के पूर्व मुख्य जलवायु वार्ताकार विजय शर्मा का निधन

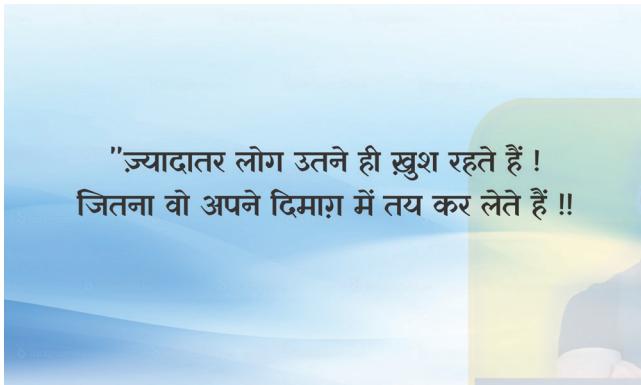
वैश्विक मंच पर भारत के पूर्व मुख्य जलवायु वार्ताकार, जो क्योटो प्रोटोकॉल के भी निर्माता थे, विजय शर्मा का 75 वर्ष की आयु में अमेरिका में निधन हो गया।

करियर की मुख्य विशेषताएँ:

- आईएएस अधिकारी, 1974 बैच



- भारत के पर्यावरण सचिव (2008 से) के रूप में कार्यरत
- भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कार्यरत



INTERNATIONAL DAY OF THE WORLD'S INDIGENOUS PEOPLES



9 August

Importance

To mark the first meeting, in 1982, of the UN Working Group on Indigenous Populations of the Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights.

History Behind

To mark the first meeting, in 1982, of the UN Working Group on Indigenous Populations of the Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights.

Organisation Involved

UNGA

Who are Indigenous peoples?

- Indigenous peoples are inheritors and practitioners of unique cultures and ways of relating to people and the environment.
- They have retained social, cultural, economic and political characteristics that are distinct from those of the dominant societies in which they live.

KUMAR
EDUTAINMENT

Inception: 1995

INTERNATIONAL YOUTH DAY



12 August

Inception: 1999

2025 Theme:
Youth Empowerment for a Sustainable Future

Importance

- To mark the proclamation by UNGA on recommendations made by the World Conference of Ministers Responsible for Youth in 1998.
- This day is an initiative that celebrates the qualities of young people and that recognises the challenges that today's youth can face.

Motto

To highlight the ways in which the engagement of young people at the local, national and global levels is enriching national and multilateral institutions.

Organisation Involved

UN & UNICEF 2024

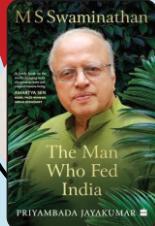
Note

This day brings youth issues to the attention of the international community and celebrating the potential of youth as partners in today's global society.

परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण दिन

दिवस	मनाया जाता है	महत्व/थीम
2 सितम्बर	नारियल दिवस	यह दिन गरीबी उन्मूलन में इस फल के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद करता है।
5 सितम्बर	अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस	मदर टेरेसा की पुण्य तिथि मनाने हेतु
5 सितम्बर	शिक्षक दिवस	भारत रत्न प्राप्तकर्ता डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती मनाने हेतु
8 सितम्बर	अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस	डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना।
10 सितम्बर	विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस	आत्महत्या की कहानी बदलना
14 सितम्बर	हिंदी दिवस	14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिये जाने हेतु।
15 सितम्बर	इंजीनियर दिवस	महानतम भारतीय इंजीनियर भारत रत्न मोक्षगुंडम विशेष्वरैया की याद और श्रद्धांजलि के रूप में।
16 सितम्बर	ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस	विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक
21 सितम्बर	अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस (यूएन)	शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें
21 सितम्बर	विश्व अल्जाइमर दिवस	अल्जाइमर से संबंधित मनोध्रंश से जुड़े आम कलंक की चुनौतियों के बीच जागरूकता बढ़ाना।
23 सितम्बर	सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस	1951 में बधिरों के विश्व महासंघ की स्थापना को चिह्नित करने हेतु।
26 सितम्बर	विश्व समुद्री दिवस	हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर
27 सितम्बर	विश्व पर्यटन दिवस	27 सितंबर 1970 को यूएनडब्ल्यूटीओ कानून को अपनाने की वर्षगांठ मनाने हेतु।
28 सितम्बर	विश्व रेबीज़ दिवस	फ्रांसीसी रसायनक्ष और सूक्ष्म जीवविज्ञानी लुई पाश्वर की पुण्यतिथि मनाने के लिए, जिन्होंने पहला रेबीज टीका विकसित किया था।
29 सितम्बर	विश्व हृदय दिवस	हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाना।
30 सितम्बर	अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस	बाइबिल अनुवादक, जिन्हें अनुवादकों का संरक्षक संत माना जाता है, सेंट जेरोम की पुण्यतिथि मनाने हेतु।

पुस्तकें एवं लेखक



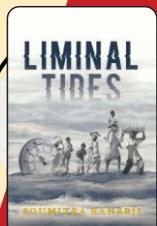
पुस्तक: एम.एस. स्वामीनाथन: द मैन हू फेड इंडिया
लेखक: प्रियंबदा जयकुमार
बारे में: यह पुस्तक पाठकों को स्वामीनाथन के जीवन के तीन प्रमुख चरणों, उनके प्रारंभिक वर्षों, उनकी वैज्ञानिक यात्रा और भारत की खाद्य सुरक्षा को आकार देने में उनकी भूमिका से परिचित कराती है।



पुस्तक: डस्क ओवर द मस्टर्ड फ़िल्ड्स
लेखक: रंजीत पोवार
बारे में: एक छठ महिला के जीवन के माध्यम से ग्रामीण पंजाब में विभाजन के लैंगिक प्रभाव की पड़ताल।



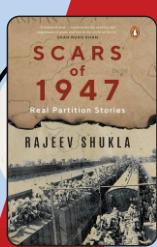
पुस्तक: द राइज़ ऑफ़ द हिटमैन
लेखक: आर. कौशिक
बारे में: अपने साथियों, कोचों और दोस्तों द्वारा साझा की गई कहानियों और यादों के माध्यम से, यह पुस्तक क्रिकेट की सफलता के पीछे के व्यक्ति की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करती है।



पुस्तक: लिमिनल टाइड्स
लेखक: सौमित्र बनर्जी
बारे में: एक काल्पनिक कथा जो पीढ़ियों से विभाजन से प्रभावित परिवारों की नियति को आपस में जोड़ती है।



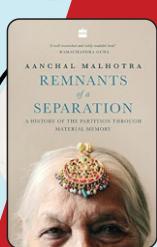
पुस्तक: द कॉशियंस नेटवर्क
लेखक: सुगाता श्रीनिवासराजू
बारे में: यह पुस्तक अमेरिका में युवा प्रवासी भारतीय कार्यकर्ताओं की प्रेरक कहानी प्रस्तुत करती है जिन्होंने इंदिरा गांधी के आपातकाल (1975-77) का विरोध किया था।



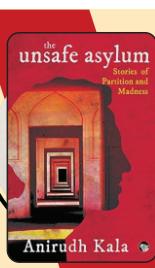
पुस्तक: स्कार्स ऑफ़ 1947
लेखक: राजीव शुक्ला
बारे में: जीवित बचे लोगों की वास्तविक जीवन की कहानियाँ साझा करती हैं जो अपने नुकसान, जीवित रहने और आघात के अनुभवों को बताती हैं।



पुस्तक: कितने पाकिस्तान
लेखक: कमलेश्वर
बारे में: एक रूपकात्मक उपन्यास जो धार्मिक, जातीय और राष्ट्रीय विभाजनों के तर्क पर गंभीर प्रश्न उठाता है।



पुस्तक: रेप्रान्ट्स ऑफ़ अ सैपरेशन
लेखिका: आंचल मल्होत्रा
बारे में: शरणार्थियों द्वारा लाई गई वस्तुओं का उपयोग प्रवास और स्मृतियों की व्यक्तिगत कहानियाँ बताने के लिए किया गया है।



पुस्तक: द अनसेफ असाइलम
लेखक: अनिरुद्ध काला
बारे में: सीमा के दोनों ओर विभाजन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर आधारित कहानियों का एक संग्रह।



पुस्तक: इन फ्रीडम्स शेड
लेखक: अनीस किदवर्ड
बारे में: एक ऐसी महिला का मार्मिक संस्मरण जिसने विभाजन पीड़ितों की सहायता की और विस्थापन के भावगात्मक प्रभाव को दर्ज किया।

अध्यास हेतु प्रश्न बैंक

स्टेटमेंट आधारित

1. भारत ने विशाखापत्तनम में द्वितीय बिमस्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव की मेजबानी की। बिमस्टेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल पहल की खाड़ी) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- (1) बिमस्टेक की स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी।
 - (2) इसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल हैं, लेकिन म्यांमार को छोड़कर।
 - (3) बिमस्टेक सदस्य देश बंगाल की खाड़ी के साथ एक सामान्य सीमा साझा करते हैं।
- उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?
- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
 (C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (A)

व्याख्या: कथन 1 सही है:

बिमस्टेक की स्थापना 1997 में बंगाल की खाड़ी की सीमा वाले देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में की गई थी।

कथन 2 गलत है:

इस कथन के विपरीत, म्यांमार वास्तव में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान के साथ बिमस्टेक का सदस्य है। इस प्रकार, संगठन में दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों के देश शामिल हैं।

कथन 3 सही है:

सभी बिमस्टेक सदस्य देश बंगाल क्षेत्र की खाड़ी में स्थित हैं, या तो बंगाल की खाड़ी के लिए एक प्रत्यक्ष समुद्र तट या निकटता साझा करते हैं, जो कि समुद्री, आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में आम भौगोलिक लिंक को बढ़ावा देने वाला सहयोग है।

2. 26 जुलाई को देखे गए मैंग्रोव इकोसिस्टम के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- (1) मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के इंटरटाइडल क्षेत्रों में बढ़ते हैं।
 - (2) सुंदरबन एकमात्र मैंग्रोव वन है जो एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है।
 - (3) मैंग्रोव तटीय तूफानों और सुनामी के खिलाफ प्राकृतिक बाधाओं के रूप में काम करते हैं।
- उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?
- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
 (C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (A)

व्याख्या: कथन 1: सही।

मैंग्रोव खारा और ज्वारीय स्थितियों के लिए अनुकूलन के साथ उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के इंटरटाइडल क्षेत्रों में पनपते हैं।

कथन 2: गलत।

जबकि सुंदरबन एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यह इस स्थिति के साथ एकमात्र मैंग्रोव वन नहीं है; उदाहरण के लिए, बांग्लादेश और भारत में सुंदरबन एक है, लेकिन वैश्विक स्तर पर अन्य मैंग्रोव जंगलों में भी संरक्षित स्थिति है।

कथन 3: सही।

मैंग्रोव प्राकृतिक बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं, तटीय तूफानों, चक्रवातों और सुनामी से नुकसान को कम करते हैं, तटीय पारिस्थितिक तंत्र और मानव बस्तियों की रक्षा करते हैं।

चीन यारलुंग ज़ंगबो नदी पर 60,000 मेगावाट जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है।

ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- (1) यह अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से तीस्ता नदी के रूप में भारत में प्रवेश करता है और बांग्लादेश में जामुना के रूप में प्रवेश करने से पहले असम से बहता है।
- (2) भारत में ब्रह्मपुत्र बेसिन में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम शामिल हैं।
- (3) दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
 (C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (C)

व्याख्या: कथन 1:

यह कथन गलत है। ब्रह्मपुत्र भारत में तीस्ता नदी में प्रवेश नहीं करता है। इसके बजाय, यह अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से सियांग के रूप में भारत में प्रवेश करता है (जिसे दीहांग भी कहा जाता है)। तीस्ता अपनी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है, बाद में बांग्लादेश में शामिल हो गया। नदी के जल विज्ञान और बेसिन प्रबंधन को समझने के लिए यह भेद महत्वपूर्ण है।

कथन 2:

भारत में ब्रह्मपुत्र बेसिन में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सहित कई राज्यों को शामिल किया गया है। यह बेसिन पारिस्थितिक रूप से समृद्ध और हाइड्रोलॉजिकल रूप से महत्वपूर्ण है, जो विविध वनस्पतियों, जीवों और मानव आबादी का समर्थन करता है। यह भारत के 30% से अधिक जल संसाधनों और लगभग 41% जलविद्युत क्षमता को भी रखता है।

कथन 3:

असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप होने का गौरव है। यह अद्वितीय भौगोलिक विशेषता ब्रह्मपुत्र की गतिशील फ्लूवियल प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करती है, जिसमें तलछट जमाव और नदी चैनल क्षेत्र के परिवृश्य और संस्कृति को आकार देते हैं।

- 4.** मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को 3-0 से हराकर 2025-26 डॉ. बी.सी. रॉय ट्रॉफी जीती।
डॉ. बी.सी. रॉय ट्रॉफी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
(1) यह टूर्नामेंट एआईएफएफ द्वारा 1962 में अंडर-19 लड़कों के लिए शुरू किया गया था।
(2) 2023-24 सीज़न से, आयु वर्ग को घटाकर अंडर-15 कर दिया गया और दो-स्तरीय प्रारूप शुरू किया गया।
(3) टियर I में सबसे सफल टीम पंजाब है, जिसने 18 बार यह खिताब जीता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (B)**व्याख्या:** कथन 1 सही है -

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने 1962 में डॉ. बी. सी. रॉय ट्रॉफी की शुरुआत की थी, जो मूल रूप से अंडर-19 लड़कों के लिए एक मंच के रूप में थी, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में जमीनी स्तर की फुटबॉल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना था।

कथन 2 सही है -

2023-24 से शुरू होने वाले एक बड़े सुधार में, टूर्नामेंट को अंडर-15 खिलाड़ियों तक सीमित कर दिया गया था, और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए दो-स्तरीय प्रारूप (टियर I और टियर II) लागू किया गया था। शीर्ष टीमें टियर I में खेलती हैं; बाकी टीमें टियर II में।

कथन 3 गलत है -

पंजाब नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल सबसे सफल टीम है, जिसने 18 बार ट्रॉफी जीतकर जूनियर फुटबॉल में अपना दबदबा स्थापित किया है।

- 5.** रूस के कामचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का भीषण भूकंप आया।

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- (1) प्राथमिक भूकंपीय तरंगें द्वितीयक तरंगों की तुलना में धीमी गति से चलती हैं, लेकिन ठोस और तरल पदार्थों से होकर गुजर सकती हैं।
(2) बेनिओफ़ ज़ोन, सबडक्षण ज़ोन के साथ भूकंप निर्माण से जुड़ा है।
(3) संशोधित मर्काली पैमाना भूकंप के स्रोत पर ऊर्जा उत्सर्जन को मापता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) (B) केवल (1) और (3)
(C) केवल (2) (D) इनमें से कोई भी नहीं
(C)

उत्तर:**व्याख्या:** कथन 1 गलत है:

प्राथमिक तरंगें (P-तरंगें) सबसे तेज़ भूकंपीय तरंगें होती हैं, द्वितीयक तरंगों से धीमी नहीं। ये संपीड़नशील होती हैं और ठोस, द्रव और गैसों से होकर गुजर सकती हैं। इसके विपरीत, द्वितीयक तरंगें (S-तरंगें) धीमी होती हैं और द्रवों से होकर नहीं गुजर सकतीं।

कथन 2 सही है:

बेनिओफ़ क्षेत्र, एक अववाही टेक्टोनिक प्लेट के साथ भूकंपीय गतिविधि के झुकाव वाले क्षेत्र को संदर्भित करता है, जो आमतौर पर एक महासागरीय खाई के नीचे होता है। यह अभिसारी प्लेट सीमाओं की एक प्रमुख विशेषता है और गहरे-केंद्रित भूकंपों की घटना की व्याख्या करता है।

कथन 3 गलत है:

संशोधित मर्काली तीव्रता (MMI) पैमाना तीव्रता, अर्थात् किसी विशिष्ट स्थान पर भूकंप के देखे गए प्रभावों और क्षति को मापता है। यह व्यक्तिपरक है और भूकंप के केंद्र से दूरी के साथ बदलता रहता है। ऊर्जा उत्सर्जन या परिमाण को रिक्टर स्केल या आर्घुर्ण परिमाण स्केल (Mw) का उपयोग करके मापा जाता है, जो वस्तुनिष्ठ और उपकरण-आधारित होते हैं।

भारत ने तटरक्षक बल के लिए पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट बनाना शुरू किया।

होवरक्राफ्ट और भारत में उनके विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- (1) होवरक्राफ्ट हवा के कुशन पर चलते हैं और विशेष डॉक की आवश्यकता के बिना ज़मीन, पानी और दलदली इलाकों में यात्रा कर सकते हैं।
(2) भारत का पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट, नंदी, डीआरडीओ द्वारा 1990 के दशक में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में विकसित किया गया था।
(3) भारतीय तटरक्षक बल मुख्य रूप से खोज और बचाव, गश्त और कठिन इलाकों में समुद्री अभियानों के लिए होवरक्राफ्ट का उपयोग करता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर:**व्याख्या:** कथन 1 सही है:

होवरक्राफ्ट या एयर कुशन व्हीकल (ACV) हवा के कुशन पर तैरते हैं और ज़मीन, पानी, दलदल और बर्फ जैसे कई इलाकों में चल सकते हैं। इन्हें गोदी या बंदरगाह की आवश्यकता नहीं होती, जिससे ये अत्यधिक अनुकूलनीय होते हैं।

कथन 2 गलत है:

पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट, नंदी, 1990 के दशक में नहीं, बल्कि 1958 में विकसित किया गया था। यह DRDO के तहत नहीं, बल्कि एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) के तहत एक परियोजना थी और इसका नेतृत्व डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। बाद में धन संबंधी समस्याओं के कारण प्रोटोटाइप का निर्माण बंद कर दिया गया।

कथन 3 सही है:

भारतीय तटरक्षक बल तटीय और दलदली क्षेत्रों में गश्त करने, खोज और बचाव अभियान चलाने और दुर्गम क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए होवरक्राफ्ट का प्रभावी ढंग से उपयोग करता है।

7. पर्वतारोहियों की उपलब्धियों के सम्मान में हर साल 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है।

पर्वतारोहण उपलब्धियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- (1) तेनजिंग नोर्गे को भारतीय पर्वतारोहण में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
- (2) बछेंद्री पाल अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट अभियान का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला थीं।
- (3) कामी रीता शेरपा के नाम माउंट एवरेस्ट पर सबसे सफल चढ़ाई का रिकॉर्ड है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (C)

व्याख्या: कथन 1: गलत

1953 में सर एडमंड हिलेरी के साथ एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले दो पुरुषों में से एक, तेनजिंग नोर्गे को 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, लेकिन उन्हें कभी भारत रत्न नहीं मिला।

उन्हें ब्रिटेन द्वारा जॉर्ज मेडल और नेपाल के ऑर्डर ऑफ द स्टार से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नहीं मिला।

कथन 2: सही

1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, बछेंद्री पाल ने बाद में कई अभियानों का नेतृत्व किया।

1993 में, उन्होंने भारत-नेपाली महिला एवरेस्ट अभियान का नेतृत्व किया, जिससे वह एवरेस्ट पर किसी अंतर्राष्ट्रीय दल का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई।

कथन 3: सही

नेपाली पर्वतारोही, कामी रीता शेरपा, 29 बार (मई 2024 तक) माउंट एवरेस्ट पर सबसे सफल चढ़ाई का विश्व रिकॉर्ड रखते हैं।

वह 1994 से लगभग हर साल एवरेस्ट पर चढ़ते आ रहे हैं।

हर साल 1 अगस्त को दुनिया वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाती है।

वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1) टिम बर्नस-ली ने 1989 में CERN में रहते हुए वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्ताव रखा था।

(2) वर्ल्ड वाइड वेब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करके संचालित होता है।

(3) इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब डिजिटल कनेक्टिविटी की एक ही प्रणाली को संदर्भित करते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)

- (C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

(A)

व्याख्या: कथन 1: सही

CERN के एक ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नस-ली ने 1989 में विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों के बीच स्वचालित सूचना-साझाकरण को सुगम बनाने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) की अवधारणा प्रस्तावित की थी।

पहली वेबसाइट (info.cern.ch) उनके द्वारा बनाई गई थी और 1991 में शुरू हुई।

कथन 2: सही

वर्ल्ड वाइड वेब HTTP (हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल) पर आधारित है, जो हाइपरलिंक किए गए टेक्स्ट दस्तावेज़ों (वेब पेजों) को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रोटोकॉल है।

HTTP, TCP/IP प्रोटोकॉल सूट पर कार्य करता है, जिससे ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच क्लाइंट-सर्वर संचार संभव होता है।

कथन 3: गलत

इंटरनेट एक वैश्विक अवसंरचना है - परस्पर जुड़े कंप्यूटरों और राउटरों का एक भौतिक और तार्किक नेटवर्क।

WWW, उन सेवाओं (जैसे ईमेल, FTP) में से एक है जो इंटरनेट का उपयोग करती हैं। ये समानार्थी नहीं हैं - कई इंटरनेट कार्यों में WWW शामिल नहीं होता है।

रूस के कुरील द्वीप समूह और जापान के उत्तरी द्वीप होककाइडो के तटीय क्षेत्रों में सुनामी आई है।

सुनामी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

(1) सुनामी तरंगों को उनकी लंबी तरंगदैर्घ्य के कारण उथले पानी की तरंगों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(2) 2004 की हिंद महासागर सुनामी सुंडा ट्रेंच के पास एक महाविक्षेप भूकंप के कारण उत्पन्न हुई थी।

(3) सुनामी से अधिकतम नुकसान वायुमंडलीय दबाव प्रणालियों को विस्थापित करने की उनकी क्षमता के कारण होता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
- (C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (B)

व्याख्या: कथन 1: सही

सुनामी उथली जल तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी गति तरंगदैर्घ्य से नहीं, बल्कि महासागर की गहराई से नियंत्रित होती है। भौतिक वर्गीकरण में "उथली" होने के बावजूद, ये तरंगें गहरे महासागरों में तेज़ी से चलती हैं - 800 किमी/घंटा तक - सतह पर बहुत कम साक्ष्य के साथ, जिससे ये भ्रामक रूप से खतरनाक हो जाती हैं।

कथन 2: सही

2004 की हिंद महासागर सुनामी सुंडा सबडक्शन ज़ोन में एक विशाल मेगाथ्रस्ट भूकंप (~9.1 तीव्रता) के परिणामस्वरूप आई थी, जहाँ इंडो-ऑस्ट्रेलियाई प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस गई थी। इसने 14 से ज्यादा देशों को प्रभावित किया और 2,30,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली।

कथन 3: गलत

उल्कापिंड सुनामी होती हैं - जो वायुमंडलीय दबाव में तेज़ बदलावों के कारण होती हैं - लेकिन ये स्थानीयकृत, छोटे पैमाने की घटनाएँ होती हैं और उत्पत्ति या प्रभाव के आधार पर टेक्टोनिक सुनामी नहीं कहलातीं। इनकी तरंगें कहीं ज्यादा छोटी और कम विनाशकारी होती हैं।

10.

केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने 1 अगस्त 2025 को एक सप्ताह तक चलने वाला "अपने बुनकरों को जानें अभियान 2025" शुरू किया।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- (1) पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में मनाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे।
- (2) 7 अगस्त की तारीख 1905 में स्वदेशी आंदोलन के शुभारंभ की याद दिलाती है, जो बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था।
- (3) 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (2025) मुंबई में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत के राष्ट्रपति संत कबीर पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगे।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
- (C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (B)

व्याख्या: कथन 1 सही है:

पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 को चेन्नई, तमिलनाडु में मनाया गया था। यह आयोजन महत्वपूर्ण था

क्योंकि इसने हथकरघा कारीगरों और स्वदेशी वस्त्र विरासत को बढ़ावा देने पर सरकार के ध्यान को दर्शाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे और उन्होंने समारोह का आधिकारिक शुभारंभ किया।

कथन 2 सही है:

7 अगस्त की तारीख 1905 में शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन के उपलक्ष्य में चुनी गई थी, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और भारत में निर्मित (स्वदेशी) उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया था। यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा बंगाल के विभाजन की सीधी प्रतिक्रिया थी, और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में एक बैठक में इसे औपचारिक रूप से समर्थन दिया गया था।

कथन 3 गलत है:

11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (2025) मुंबई में नहीं मनाया जाएगा। इसके बजाय, इसे केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया जाना है। भारत की राष्ट्रपति द्वौपदी मुर्मु मुख्य अतिथि होंगी और हथकरघा बुनाई और डिजाइन में उल्कृष्टता के लिए संत कबीर पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों के विजेताओं को सम्मानित करेंगी।

वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने 47वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला।

भारतीय नौसेना प्रमुखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- (1) नौसेना प्रमुख (सीएनएस) चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (सीओएससी) का स्थायी सदस्य होता है।
- (2) नौसेना प्रमुख की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- (3) एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना प्रमुख बनने वाले पहले हेलीकॉप्टर पायलट थे।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
- (C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं
- (A)

व्याख्या: कथन 1 सही है:

नौसेना प्रमुख (सीएनएस) भारतीय नौसेना का सर्वोच्च पदस्थ अधिकारी और चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (सीओएससी) का स्थायी सदस्य होता है, जो तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त अभियानों और सैन्य नीतियों का समन्वय करता है।

कथन 2 गलत है:

नौसेना प्रमुख की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा की जाती है, न कि सीधे अनुच्छेद 53 के तहत। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है, लेकिन सेवा प्रेमुखों की नियुक्तियाँ एसीसी के माध्यम से की जाती हैं।

कथन 3 सही है:

एडमिरल करमबीर सिंह 2019 में 24वें नौसेना प्रमुख बने और सतह और पनडुब्बी अधिकारियों के नौसेना प्रमुख बनने की परंपरा को तोड़ते हुए, शीर्ष नौसेना पद संभालने वाले पहले हेलीकॉप्टर पायलट होने के लिए उल्लेखनीय थे।

- उत्तर:** 12. आर्द्धभूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी) की 15वीं बैठक 31 जुलाई 2025 को समाप्त हुई।

आर्द्धभूमि पर रामसर कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1) रामसर कन्वेंशन आर्द्धभूमि के लिए 1971 में अपनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।

(2) मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर स्थलों का एक रजिस्टर है।

(3) 2025 तक, भारत में दुनिया में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (B)

व्याख्या: कथन 1 सही है:

आर्द्धभूमि पर रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर में अपनाया गया था और 1975 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आर्द्धभूमि का संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग करना है।

कथन 2 सही है:

मॉन्ट्रो रिकॉर्ड, रामसर ढाँचे का एक हिस्सा है और उन रामसर स्थलों को सूचीबद्ध करता है जहाँ प्रदूषण, मानवीय हस्तक्षेप या अन्य कारणों से होने वाले पारिस्थितिक परिवर्तन विशेष रूप से चिंता का विषय हैं।

कथन 3 गलत है:

2025 तक, भारत रामसर स्थलों के मामले में शीर्ष देशों में से एक है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम अभी भी विश्व स्तर पर सबसे अधिक संख्या रखता है। भारत ने अपने नामित रामसर स्थलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो 80 से अधिक स्थलों को पार कर गया है, लेकिन यह शीर्ष पर नहीं है।

- उत्तर:** 13. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद, चुनाव आयोग ने 9 सितंबर, 2025 को विशेष उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की है।

भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1) उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं।

(2) चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से होता है।

(3) भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर:

व्याख्या: कथन 1: सही

भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों (लोकसभा + राज्यसभा) के सदस्यों वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है।

राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य भी मतदान के पात्र होते हैं, जो राष्ट्रपति चुनाव से अलग है जहाँ मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते।

कथन 2: सही

यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (STV) के माध्यम से होता है और गुप्त मतदान द्वारा होता है।

इस प्रणाली में, सांसद उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में रैंक करते हैं, और वोट तब तक स्थानांतरित होते रहते हैं जब तक कोई उम्मीदवार आवश्यक कोटा प्राप्त नहीं कर लेता।

कथन 3: गलत

उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति (जिन्हें अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जाता है) की तरह महाभियोग प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया जाता है।

इसके बजाय, अनुच्छेद 67(B) में प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। इसमें कोई औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया शामिल नहीं है।

भारत पारंपरिक चिकित्सा के डिजिटलीकरण के लिए एआई का उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है।

भारत में पारंपरिक रूप से उपयोग किए जाने वाले औषधीय पौधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1) अश्वगंधा का उपयोग आयुर्वेद में पारंपरिक रूप से तनाव से राहत और प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए किया जाता है।

(2) गिलोय (टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया) को इसके कायाकल्प गुणों के कारण आयुर्वेदिक ग्रंथों में 'अमृत' कहा गया है।

(3) अर्जुन (टर्मिनलिया अर्जुन) का उपयोग मुख्य रूप से सिद्ध चिकित्सा में त्वचा रोगों के लिए किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर:

व्याख्या: कथन 1: सही

(3) डेंड्राइटिक कोशिकाएं एंटीजन-प्रेजेंटिंग कोशिकाओं के रूप में कार्य करती हैं जो भोले टी-कोशिकाओं को सक्रिय करती हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
- (C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (A)

व्याख्या: कथन 1 सही है:

मैक्रोफेज जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली के आवश्यक घटक हैं। वे फागोसाइटिक कोशिकाएं हैं जो रोगजनकों, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और मलबे को निगलना करती हैं। वे एंटीजन प्रस्तुति में भी एक भूमिका निभाते हैं और सूजन को ट्रिगर करने वाले साइटोकिन्स को जारी करते हैं।

कथन 2 गलत है:

टी-लिम्फोसाइट्स (टी-सेल) सेल-मध्यस्थता वाले प्रतिरक्षा में शामिल होते हैं, जैसे कि संक्रमित कोशिकाओं (साइटोटॉक्सिक टी-कोशिकाओं) को मारना या प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं (सहायक टी-कोशिकाओं) को विनियमित 18. करना। एंटीबॉडी उत्पादन बी-लिम्फोसाइट्स (बी-कोशिकाओं) द्वारा किया जाता है, न कि टी-कोशिकाओं द्वारा।

कथन 3 सही है:

डेंड्राइटिक कोशिकाएं विशेष रूप से एंटीजन-प्रेजेंटिंग सेल हैं जो रोगजनकों से एंटीजन को पकड़ती हैं, उन्हें संसाधित करती हैं, और लिम्फोइड अंगों की ओर पलायन करती हैं जहां वे इन एंटीजन को भोले टी-कोशिकाओं के लिए प्रस्तुत करते हैं, जो अनुकूली प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं शुरू करते हैं।

17.

यूनियन कैबिनेट ने 15 वें वित्त आयोग के दौरान PMKSY के लिए ₹ 6,520 करोड़ की कुल परिव्यय को मंजूरी दी है। भारत के वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- (1) वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
- (2) वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करना है।
- (3) वित्त आयोग की सिफारिशें भारत सरकार के लिए बाध्यकारी हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
- (C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (B)

व्याख्या: कथन 1 सही है:

भारत का वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर पांच साल में या ऐसे अंतरालों पर किया जाता है जैसे कि आवश्यक समझा जाता है।

इसकी संवैधानिक स्थिति इसे भारत की संघीय राजकोषीय संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका देती है।

कथन 2 सही है:

आयोग का मुख्य कार्य यह अनुशंसा करना है कि करों की शुद्ध आय को केंद्र और राज्यों के बीच कैसे विभाजित किया जाना है। यह उन सिद्धांतों का भी सुझाव देता है जो भारत के समेकित फंड से राज्यों को अनुदान-सहायता को नियंत्रित करना चाहिए, और पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों को पूरक करने के लिए राज्यों के समेकित निधि को बढ़ाने के लिए उपाय हैं।

कथन 3 गलत है:

वित्त आयोग की सिफारिशें प्रकृति में सलाहकार हैं और भारत सरकार के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं। हालांकि, वे उच्च प्रेरक मूल्य रखते हैं और आमतौर पर लागू होते हैं, लेकिन केंद्र सरकार विवेक को बनाए रखती है।

IEA 2025: हीटवेल्स, एसीएस, डेटा सेंटर, ईवीएस के कारण बिजली की मांग बढ़ती है; सौर, पवन, परमाणु पुनर्वासन ऊर्जा मिश्रण।

जून 2025 तक भारत के बिजली क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- (1) भारत की स्थापित बिजली क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी 50% से अधिक हो गई है।
- (2) पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा के बाद भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।
- (3) अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) RE सांख्यिकी 2025 के अनुसार, भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व स्तर पर 3 रैंक करता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
- (C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं
- (B)

व्याख्या: कथन 1 सही है:

जून 2025 तक, भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता 484.82 GW है, जिसमें से गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोत (नवीकरणीय + बड़े हाइड्रो + परमाणु) 242.78 GW का योगदान करते हैं, जो कुल का 50.08% है। यह स्वच्छ ऊर्जा की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जो पहली बार भारत के ऊर्जा मिश्रण में आधे रास्ते के निशान को पार करता है।

कथन 2 सही है:

अक्षय ऊर्जा खंड के भीतर, सौर ऊर्जा सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखती है, जो गैर-जीवाश्म क्षमता का 47.06% योगदान देता है। पवन ऊर्जा दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, 21.78% के लिए लेखांकन, इसके बाद बड़े हाइड्रो और बायोएनर्जी हैं।

कथन 3 गलत है:

IRENA अक्षय ऊर्जा सांख्यिकी 2025 के अनुसार, भारत पवन ऊर्जा क्षमता में विश्व स्तर पर 4 वें स्थान पर है। हालांकि, भारत को सौर ऊर्जा क्षमता में तीसरा स्थान दिया गया है। इसलिए, यह कथन तथ्यात्मक रूप से गलत है।

- 19.** मेरा गाँव मेरी धरोहर (एमजीएमडी) पहल के अंतर्गत, लगभग 4.7 लाख गाँवों का डेटा एमजीएमडी पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

मेरा गाँव मेरी धरोहर (एमजीएमडी) पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- (1) इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आईजीएनसीए के सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है।
- (2) एमजीएमडी का उद्देश्य भारत के गाँवों की सांस्कृतिक पहचान का दस्तावेजीकरण और डिजिटल मानचित्रण करना है।
- (3) एमजीएमडी के अंतर्गत गाँवों को कला एवं शिल्प तथा महाकाव्य (रामायण, महाभारत) जैसे विषयगत समूहों में वर्गीकृत किया गया है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (C)

व्याख्या: कथन 1 गलत है:

एमजीएमडी का कार्यान्वयन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाता है, न कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। यह एक सांस्कृतिक प्रलेखन मिशन है, न कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (एनएमसीएम) के अंतर्गत कार्यान्वयन निकाय है।

कथन 2 सही है:

एमजीएमडी का मुख्य उद्देश्य भारत भर के लगभग 6.5 लाख गाँवों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान का दस्तावेजीकरण और डिजिटल मानचित्रण करना है, सांस्कृतिक विरासत को डिजिटल रूप में संरक्षित करना है।

कथन 3 सही है:

एमजीएमडी के अंतर्गत, गाँवों को विषयगत रूप से कला और शिल्प, पारिस्थितिक रूप से उन्मुख, शैक्षिक (पाठ्य/शास्त्रीय), महाकाव्य (रामायण, महाभारत, पुराण) आदि समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। यह विषयगत वर्गीकरण सांस्कृतिक मानचित्रण और ग्रामीण सांस्कृतिक अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने में मदद करता है।

- 20.** केरल और तमिलनाडु में एक संयुक्त जनगणना में 2,668 नीलगिरि तहर दर्ज किए गए, जिनमें से 1,365 केरल में और 1,303 तमिलनाडु में थे।

नीलगिरि तहर (नीलगिरिट्रैग्स हाइलोक्रियस) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- (1) नीलगिरि तहर भारत के पूर्वी घाटों में स्थानिक है।
- (2) यह पश्चिमी घाटों में पर्वतीय धास के मैदानों के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक प्रजाति है।
- (3) नीलगिरि तहर की सबसे बड़ी आबादी केरल के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर:

व्याख्या: कथन 1 गलत है:

नीलगिरि तहर पश्चिमी घाटों में स्थानिक है, पूर्वी घाटों में नहीं। इसका वितरण तमिलनाडु और केरल की धास वाली ढलानों और चट्टानों तक सीमित है, विशेष रूप से 1,200-2,600 मीटर की ऊँचाई पर। यूपीएससी अक्सर जैव विविधता के प्रश्नों में पूर्वी और पश्चिमी घाटों की अदलाबदली करके जाल बिछाता है।

कथन 2 सही है:

नीलगिरि तहर पर्वतीय धास के मैदानों के पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के लिए एक प्रमुख संकेतक प्रजाति है। इसकी उपस्थिति एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत देती है, क्योंकि यह नीलगिरि लंगूर और शेर-पूँछ वाले मकाक जैसी अन्य स्थानिक प्रजातियों के साथ सह-अस्तित्व में रहती है। आवास क्षण सीधे इसके अस्तित्व के लिए खतरा है, जिससे यह एक पारिस्थितिक प्रहरी बन जाता है।

कथन 3 सही है:

केरल स्थित एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान (ईएनपी) में नीलगिरि तहर की सबसे बड़ी जंगली आबादी है, जो इसे संरक्षण प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बनाती है। अन्य खंडित आबादी पलानी पहाड़ियों, श्रीविल्लिपुत्तुर, मेघमलाई और अगस्तियार पर्वतमाला में मौजूद है।

कर्नाटक में शरावती पंप स्टोरेज जलविद्युत परियोजना को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।

शरावती घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- (1) शरावती घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित है, जो पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है।

- (2) राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) भारत के राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाला एक वैधानिक निकाय है।

- (3) NBWL की स्थायी समिति संरक्षित क्षेत्रों और पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में परियोजना मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (A)**व्याख्या:** कथन 1 सही है:

शरकीरी धारी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक के शिवमोगा जिले में पश्चिमी घाट के भीतर स्थित है, जो अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यह अभ्यारण्य 431.23 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसमें जोग जलप्रपात और लिंगनमक्की जलाशय जैसे उल्लेखनीय आकर्षण शामिल हैं।

कथन 2 गलत है:

एनबीडब्ल्यूएल की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति नहीं। यह यूपीएससी का एक विशिष्ट जाल है जहाँ छात्र शीर्ष निकायों के प्रमुखों को भ्रमित करते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (एमओईएफसीसी) उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

कथन 3 सही है:

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता वाली एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति को विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्रों (पीए) और पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) में परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन करने का कार्य सौंपा गया है। पूर्ण एनबीडब्ल्यूएल बड़े नीति-स्तरीय निर्णयों से संबंधित है।

22.

बढ़ते समुद्र स्तर के कारण सिएरा लियोन के कई द्वीप आसन्न जलमग्नता का सामना कर रहे हैं।

सिएरा लियोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -

(1) सिएरा लियोन की सीमाएँ गिनी और लाइबेरिया से लगती हैं।

(2) राजधानी, फ्रीटाउन, दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक होने के लिए जाना जाता है।

(3) सिएरा लियोन को वर्ष 1957 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (B)**व्याख्या:** कथन 1 सही है:

सिएरा लियोन पश्चिम अफ्रीका के दक्षिण-पश्चिमी तट पर स्थित है, जिसकी स्थलीय सीमा उत्तर और पूर्व में गिनी और दक्षिण में लाइबेरिया से लगती है। इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है।

कथन 2 सही है:

सिएरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन, दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक होने के कारण ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसने इसे औपनिवेशिक काल के दौरान एक रणनीतिक स्थान बना दिया और आज भी समुद्री व्यापार को बढ़ावा देता है।

कथन 3 गलत है:**23.**

सिएरा लियोन 1808 में एक ब्रिटिश उपनिवेश बना और बाद में 1957 में नहीं, बल्कि 1961 में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की। गलत वर्ष इस कथन को गलत बनाता है।

तकनीक-संचालित जन स्वास्थ्य पहल के तहत, आंध्र प्रदेश ने स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली शुरू की है।

मच्छर जनित सामान्य रोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -

(1) डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस, सभी एडीज़ मच्छर द्वारा फैलाए जाते हैं।

(2) मलेरिया, क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है।

(3) जापानी इंसेफेलाइटिस एक वायरल रोग है जो मुख्यतः ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में मच्छरों द्वारा फैलता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)

- (C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

(A)**व्याख्या:** कथन 1 सही है:

डेंगू, चिकनगुनिया और जीका सभी वायरल संक्रमण एडीज़ एजिटी मच्छर द्वारा फैलते हैं, जो दिन में, खासकर सुबह और देर दोपहर में काटने की आदत के लिए जाना जाता है। एडीज़ मच्छर बर्तनों, कूलरों, गमलों आदि में पाए जाने वाले साफ़, ठहरे हुए पानी में प्रजनन करते हैं।

कथन 2 गलत है:

मलेरिया क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है। यह प्लास्मोडियम परजीवी (आमतौर पर पी. फाल्सीपेरम और पी. विक्रस) के कारण होता है और मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है। मलेरिया आमतौर पर ठंड लगने के साथ तेज़ बुखार का कारण बनता है और ठहरे हुए पानी और खराब स्वच्छता वाले क्षेत्रों में आम है।

कथन 3 सही है:

जापानी इंसेफेलाइटिस (जेर्झ) एक वायरल मस्तिष्क संक्रमण है जो क्यूलेक्स मच्छरों, विशेष रूप से क्यूलेक्स ट्राइटेनियोरिन्चस द्वारा फैलता है, जो धान के खेतों और दलदली क्षेत्रों में प्रजनन करते हैं। यह मुख्यतः ग्रामीण, चावल उत्पादक और सुअर पालन वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रभावित करता है, खासकर मानसून और मानसून के बाद के मौसम में। बच्चे इसके प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, और जापानी इंसेफेलाइटिस (जेर्झ) के लिए एक टीका उपलब्ध है।

सीएसआईआर-इंस्टीचूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी (आईजीआईबी) में हाल ही में शुरू किया गया राष्ट्रीय बायोबैंक, भारत के अनुदैर्घ्य स्वास्थ्य डेटाबेस के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम है।

राष्ट्रीय बायोबैंक और फेनोम इंडिया परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें -

24.

(1) व्यक्तिगत चिकित्सा में भारत-विशिष्ट अनुसंधान का समर्थन करने के लिए फेनोम इंडिया परियोजना के तहत राष्ट्रीय बायोबैंक शुरू किया गया है।

(2) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा भारत में दुर्लभ अनुवंशिक विकारों का अध्ययन करने के लिए फेनोम इंडिया परियोजना शुरू की गई थी।

(3) बायोबैंक का उद्देश्य 10,000 विविध भारतीय प्रतिभागियों से डेटा एकत्र करके एक जीनोमिक और स्वास्थ्य भंडार बनाना है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (A)

व्याख्या: कथन 1 सही है: राष्ट्रीय बायोबैंक, फेनोम इंडिया परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत की अनुवंशिक विविधता के आधार पर व्यक्तिगत चिकित्सा को बढ़ावा देना है।

कथन 2 गलत है: यह परियोजना CSIR (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद) द्वारा शुरू की गई थी, न कि ICMR द्वारा।

कथन 3 सही है: बायोबैंक भारत भर के 10,000 प्रतिभागियों से जीनोमिक, जीवनशैली और नैदानिक डेटा एकत्र करेगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों और पृष्ठभूमियों को शामिल किया जाएगा।

25.

आईसीएआर-केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय मर्त्य अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-सीआईएफआरआई) के शोधकर्ताओं ने ब्रह्मपुत्र नदी में एक नई साइप्रिनिड मछली प्रजाति, पेथिया डिब्रूगढ़ेसिस, की खोज की है। पेथिया डिब्रूगढ़ेसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1) यह साइप्रिनिडे परिवार से संबंधित है, जिसमें कार्प और मिनो शामिल हैं।

(2) यह आमतौर पर खारे पानी और तटीय मुहाने में पाई जाती है।

(3) इसमें बारबेल नहीं होते हैं, लेकिन इसके रूपात्मक लक्षणों के कारण इसे अभी भी बार्ब के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (A)

व्याख्या: कथन 1 – सही:

Pethia dibrugarhensis का संबंध Cyprinidae परिवार से है, जो विश्व में सबसे बड़ा मीठे पानी की मछलियों का परिवार है। इस कुल में कार्प (Carps), मिनोज़

(Minnows), बाब्स (Barbs) आदि शामिल होते हैं। ये प्रायः एशिया, यूरोप और अफ्रीका में पाई जाती हैं।

कथन 2 – गलत:

यह मछली खारे पानी (Brackish Water) में नहीं पाई जाती। इसके विपरीत, Pethia dibrugarhensis का प्राकृतिक आवास मध्यम गति से बहने वाला मीठा पानी (moderately fast-flowing freshwater) है, जहाँ मिट्टी-रेती-पत्थर वाला तल (muddy-sandy-stony substrate) होता है। ये अन्य स्थानीय मीठे पानी की प्रजातियों के साथ सह-अस्तित्व में रहती हैं।

कथन 3 – सही:

मले ही इस प्रजाति में बार्बल्स (barbels) नहीं होते (जो कि बार्ब मछलियों की एक सामान्य विशेषता मानी जाती है), फिर भी इसे 'बार्ब' (Barb) वर्ग में रखा गया है क्योंकि इसमें अन्य रूपात्मक विशेषताएँ (जैसे कि अधूरी लैटरल लाइन, पूँछ के पास काले धब्बे, ह्यूमरल चिह्न की अनुपस्थिति आदि) बार्ब मछलियों के अनुरूप पाई जाती हैं।

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. क्लोरीन सबसे अधिक वैद्युतीय ऋणात्मक तत्व और अत्यंत प्रतिक्रियाशील धातु है, तथा यह आर्गन, निअॉन और हीलियम को छोड़कर अन्य सभी तत्वों के साथ प्रतिक्रिया करता है।

2. वैद्युतीय ऋणात्मकता समूहों में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है, और आवर्त में बाएं से दाएं ओर बढ़ती है।
कौन सा / कथन सही है?

- (A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) इनमें से कोई नहीं
(B)

फ्लोरीन में ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, क्लोरीन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षण होता है। जबकि फ्रैशियम सबसे कम वैद्युतीय ऋणात्मकता में से एक है।

वैद्युतीय ऋणात्मकता समूहों में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है, और आवर्त में बाएं से दाएं ओर बढ़ती है।

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. लेड क्लोराइड एक अत्यधिक विषेला यौगिक है जो एक एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

2. सीसा (टेट्राएथिल लेड) का उपयोग गैसोलीन और जेट ईंधन में एक एंटीकॉक एंजेंट के रूप में किया जाता है।
कौन सा / कथन सही है?

- (A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (B)

व्याख्या: मरकरी क्लोराइड ($HgCl_2$) एक अत्यधिक विषेला यौगिक है। यह श्लेष्म झिल्ली के लिए संक्षारक है और एक

एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है।

उत्तर: (C)
व्याख्या: 1868 में हक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा है क्योंकि जीवन के सभी गुण प्रोटोप्लाज्म में रहते हैं। सन् 1940 में पुरकिंजे ने सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था।

उत्तर: (C)
व्याख्या: लवक एक शिल्ली-युक्त अंग है जो पौधों, शैवाल और कुछ अन्य यूकेरियोटिक जीवों की कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लास्टिड्स की खोज और नाम अर्नस्ट हेकेल द्वारा दिया गया था, लेकिन ए एफ डब्ल्यू शिम्पर ने पहली बार एक स्पष्ट परिभाषा प्रदान की थी। हरितलवक प्रकाश संश्लेषण करने वाले ऑर्गेनेल हैं, जहां प्रकाश संश्लेषक वर्णक क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को संग्रहीत करता है, इसे परिवर्तित करता है, और इसे ऊर्जा-भंडारण अणुओं एटीपी और एनएडीपीएच में संग्रहीत करता है।

उत्तर: (B)
व्याख्या: ग्रहों की गति के केप्लर के तीन नियम इस प्रकार बताये जा सकते हैं: (1) सभी ग्रह सूर्य के बारे में अण्डाकार कक्षाओं में चलते हैं, जिसमें सूर्य एक foci के रूप में है। (2) सूर्य के

किसी भी ग्रह से जुड़ने वाला एक त्रिज्या सदिश समान क्षेत्रों में समान समय के बराबर दूरी पर होता है। (3) ग्रहों के नाक्षत्र काल (क्रांति काल) के वर्ग सूर्य से अपनी औसत दूरी के घन के सीधे आनुपातिक हैं। इन कानूनों का ज्ञान, विशेष रूप से दूसरा (क्षेत्रों का कानून), 1684-85 में सर आइजैक न्यूटन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ, जब उन्होंने पृथ्वी और चंद्रमा के बीच और सूर्य और ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण के अपने प्रसिद्ध कानून का सूत्रपात किया, ब्रह्माण्ड में सभी वस्तुओं के लिए वैधता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, कथन है कि ब्रह्माण्ड में किसी भी कण का द्रव्यमान किसी भी बल के साथ सीधे आकर्षित होता है, जो सीधे पदार्थ के उत्पाद के रूप में भिन्न होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के समान होता है। प्रतीकों में, आकर्षक बल F की परिमाण G के बराबर है (गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, एक संख्या जिसका आकार उपयोग की गई इकाइयों की प्रणाली पर निर्भर करता है और जो एक सार्वभौमिक स्थिरांक है) द्रव्यमान के गुणन से गुणा किया जाता है (m_1 और m_2)) और दूरी R: $F = G(m_1m_2) / R^2$ के वर्ग से विभाजित।

निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

- I. एक वाहन में मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी की गणना करता है उसे ओडोमीटर कहा जाता है।
 - II. एक इंजन को एक द्रव (भाप के रूप में) की आपूर्ति को विनियमित करने के लिए थ्रॉटल वाल्व।
सही विकल्प का चयन करें।

- (A) केवल I
(B) केवल II
(C) I और II दोनों
(D) न तो I और न ही II

उत्तरः

व्याख्या: स्पीडोमीटर, उपकरण जो वाहन की गति को इंगित करता है, आमतौर पर ओडोमीटर के रूप में जाना जाने वाला उपकरण के साथ संयुक्त होता है जो यात्रा की गई दूरी को रिकॉर्ड करता है। स्पीडोमीटर के गति-संकेत तंत्र को एक परिपत्र स्थायी चुंबक द्वारा सक्रिय किया जाता है, जो ट्रांसमिशन के पीछे गियर द्वारा संचालित एक लचीली शाफ्ट द्वारा प्रति वाहन 1,000 मील प्रति चक्कर घुमाया जाता है। थ्रोटल, एक इंजन को तरल पदार्थ (भाप के रूप में) की आपूर्ति को विनियमित करने के लिए वाल्व, विशेष रूप से एक आंतरिक-दहन इंजन के सिलेंडरों को वितरित वाष्पीकृत ईंधन की मात्रा को नियन्त्रित करने वाले वाल्व। ऑटोमोबाइल इंजन में, कार्बोरेटर के ऊपर एक कक्ष में गैसोलीन रखा जाता है।

निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

- I. एक ही आकार के एक पत्थर में अधिक जड़ता होती है।

अध्ययन करता है, जिसे जीवन की मूल इकाई के रूप में भी जाना जाता है

उत्तरः (A)
व्याख्या: मत्स्य महाजनपद आधुनिक जयपुर के आसपास का क्षेत्र था। चेदि महाजनपद आधुनिक वर्तमान के बुंदेलखण्ड प्रांत के आसपास का क्षेत्र था। इसकी राजधानी सक्तिमती थी।

उत्तर: (C) **व्याख्या:** गजनी (998-1030) के महमूद गजनवी, जिन्होंने दसवीं शताब्दी के अंत तक पूर्वी ईरान और आधुनिक अफगानिस्तान पर सत्ता हासिल करने में सफलता हासिल की थी। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की। महमूद गजनवी के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान उल्ली था।

उत्तर: (D)
व्याख्या: कोरिओलिस के अनुसार, हवा की दिशा केन्द्रापसारक बल और केन्द्रक बल से प्रभावित होती है। विक्षेपण की मात्रा अक्षांश, वस्तु की गति और पृथ्वी के घूमने के साथ बदलती रहती है। विक्षेपण ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है और भूमध्य रेखा पर शून्य तक हो जाती है। कोरिओलिस प्रभाव वातावरण के सामान्य परिसंचरण में प्रतिक्रिया देखा जा सकता है।

- 40.** निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

उत्तर: (D)
व्याख्या: $82^{\circ} 30'$ पूर्व देशांतर को भारत के मानक समय के मध्याह्न या आईएसटी के संदर्भ पत्रों के देशांतर के रूप में लिया जाता है, क्योंकि यह भारत के मध्य (इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से) से होकर गुजरता है। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ($82^{\circ}30'E$ मेरिडियन) यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है।

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- 1.** जेलेप ला सिकिम को तिब्बत से जोड़ता है।
2. बारा-लाचा हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 **(B)** केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों **(D)** न तो 1, न ही 2

उत्तर: (C)
व्याख्या: जेलेप्ला या जेलेप पास की ऊंचाई 4,267 मीटर या 13,999 फीट है, जो पूर्वी सिक्किम जिला, सिक्किम और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, चीन के बीच एक उच्च पर्वतीय मार्ग है। बारालाचला ज़ांस्कर रेंज में एक उच्च पहाड़ी दर्दा है, जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्धाख में लेह जिले से जोड़ता है।

उत्तर: (C)
व्याख्या: भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध-न्यायिक संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गयी थी। आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। जब यह पहले पहल 1950 में गठित हुआ तब से और 15 अक्टूबर, 1989 तक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित यह एक एकल-सदस्यीय निकाय था।

के आधार पर बनाता है। इसका मतलब है कि कम आय वाले व्यक्तियों की तुलना में यह उच्च आय वाले आय का बड़ा प्रतिशत लेता है। एक प्रगतिशील कर वह है जो उच्च आय अर्जित करने वाले लोगों के लिए उच्च कर दर वसूल करता है। तर्क यह है कि कम आय वाले लोग आमतौर पर अपनी आय का अधिक प्रतिशत अपने जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए खर्च करेंगे। आयकर प्रणाली को एक प्रगतिशील प्रणाली माना जाता है।

भारत का पहला आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक NHB RESIDEX, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के इशारे पर किए गए राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) की एक पहल थी। सूचकांक एक तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) के मार्गदर्शन में तैयार किया गया था जिसमें आवास बाजार से हितधारकों को शामिल किया गया था। यह जुलाई, 2007 में लॉन्च किया गया था और मार्च 2015 तक समय-समय पर अद्यतन किया गया, 2007 को आधार वर्ष के रूप में लिया गया। इस अवधि के दौरान, NHB RESIDEX का विस्तार धीरे-धीरे 26 शहरों तक हो गया।

49. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. राडार का उपयोग दफन कलाकृतियों की खोज के लिए किया जाता है और भूकंप का पता लगाने के लिए भूवैज्ञानिक द्वारा भी उपयोग किया जाता है।
 2. राडार का उपयोग पहचान, टैकिंग और निगरानी के उद्देश्य और हथियार नियंत्रण और मिसाइल मार्गदर्शन में भी किया जाता है।
- कौन सा / कथन सही है?

50.

उत्तर:

(A) केवल 1

(C) केवल 1 और 2

(B)

(B) केवल 2

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

व्याख्या: रडार एक डिटेक्शन सिस्टम है जो वस्तुओं की सीमा, कोण या वेग को निर्धारित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। इसका उपयोग विमान, जहाज, अंतरिक्ष यान, निर्देशितमिसाइल, मोटर वाहन, मौसम निर्माण और इलाके का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। एक रडार प्रणाली में रेडियो या माइक्रोवेव डोमेन में एक विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन करने वाला एक टांसमीटर होता है, जो वस्तु के गुणों को निर्धारित करने के लिए एक संचारण एंटीना, एक प्राप्त एंटीना और एक रिसीवर और प्रोसेसर होता है।

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. वर्णी लवक पीले, लाल व नारंगी रंगों के लवक हैं।
2. तारकाकाय की खोज 1888 में टी. बोबरी ने की थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(A) केवल 1

(C) 1 और 2 दोनों

(B) केवल 2

(D) न तो 1, न ही 2

उत्तर:

व्याख्या: वर्णी लवक हैं, जो कि उनके उच्च कैरोटीनॉयड सामग्री के कारण, लाल, नारंगी या पीले रंग के होते हैं। तारकाकाय की खोज 1883 में एडॉर्ड वान बेनेडेन द्वारा की गई थी और 1888 में थियोडोर बोवेरी द्वारा वर्णित और नाम दिया गया था।

"आप अपना भविष्य
नहीं बदल सकतें
लेकिन अपनी आदतें
बदल सकते हैं !
और निश्चित रूप से
आपकी आदतें आपका
भविष्य बदल देंगी !!

"एक सपने के
टूटकर चकनाचूर हो
जाने के बाद !
दूसरा सपना देखने
के हौसले को
ज़िन्दगी कहते हैं !!"

सही मिलान प्रश्नावली

1. निम्नलिखित का मिलान करें –

नदी	विशेषता
(a) वर्धा	1. 'दक्षिण गंगा' के नाम से प्रसिद्ध है
(b) भीमा	2. प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक
(c) तापी	3. कृष्णा की सहायक नदी, सिंचाई में अत्यंत उपयोगी
(d) कृष्णा	4. सतपुड़ा और तापी बेसिन से होकर बहती है
(e) गोदावरी	5. गोदावरी की सहायक नदी, उपजाऊ मैदानों के लिए जानी जाती है

विकल्प:

- (A) a-5, b-3, c-4, d-2, e-1
 (B) a-1, b-2, c-3, d-4, e-5
 (C) a-3, b-4, c-2, d-1, e-5
 (D) a-4, b-1, c-2, d-5, e-3

उत्तर: (A)

व्याख्या: (a) वर्धा – गोदावरी की सहायक नदी, उपजाऊ मैदानों के लिए जानी जाती है (5)
 (b) भीमा – कृष्णा की सहायक नदी, सिंचाई में अत्यंत उपयोगी (3)
 (c) तापी – सतपुड़ा और तापी बेसिन से होकर बहती है (4)
 (d) कृष्णा – प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक (2)
 (e) गोदावरी – 'दक्षिण गंगा' के नाम से प्रसिद्ध है (1)

2. निम्नलिखित का मिलान कीजिए:

द्वीप	मुख्य विशेषता
(a) स्वालबार्ड	1 - हिंद महासागर में स्थित फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र, जिसमें एक सक्रिय शील्ड ज्वालामुखी है
(b) बौगनविल	2 - दक्षिण कोरिया का ज्वालामुखीय द्वीप, यूनेस्को जैवमंडल रिजर्व घोषित
(c) रीयूनियन	3 - यमन का हिस्सा, जहाँ ड्रैगन ब्लड ट्री और विशिष्ट जैव विविधता पाई जाती है
(d) सोकोत्रा	4 - पापुआ न्यू गिनी का स्वायत्त द्वीप, तांबे के भंडारों के लिए प्रसिद्ध
(e) जेजू	5 - आर्कटिक महासागर में स्थित नॉर्वे का द्वीपसमूह, जहाँ ग्लोबल सीड वॉल्ट स्थित है

विकल्प:

- (A) a-5, b-2, c-4, d-3, e-1
 (B) a-1, b-3, c-2, d-5, e-4

(C) a-5, b-4, c-1, d-3, e-2

(D) a-2, b-1, c-5, d-3, e-4

उत्तर: (C)

व्याख्या: (a) स्वालबार्ड – 5:

यह नॉर्वे का एक द्वीपसमूह है जो आर्कटिक महासागर में स्थित है। यह ग्लोबल सीड वॉल्ट के लिए प्रसिद्ध है और एक निरस्तीकृत क्षेत्र है।

(b) बौगनविल – 4:

यह पापुआ न्यू गिनी का एक स्वायत्त द्वीप है, जहाँ तांबे की खदानें हैं और स्वतंत्रता की माँगें रही हैं।

(c) रीयूनियन – 1:

यह फ्रांस का एक विदेशी क्षेत्र है, जो हिंद महासागर में स्थित है और यहाँ पिटॉन डे ला फोर्नेज नामक सक्रिय शील्ड ज्वालामुखी पाया जाता है।

(d) सोकोत्रा – 3:

यह यमन का हिस्सा है, जो अपनी अद्वितीय जैव विविधता और विशेष रूप से ड्रैगन ब्लड ट्री के लिए प्रसिद्ध है।

(e) जेजू – 2:

यह दक्षिण कोरिया का एक ज्वालामुखीय द्वीप है, जिसे यूनेस्को ने जैवमंडल रिजर्व घोषित किया है और यहाँ हल्लासान ज्वालामुखी स्थित है।

निम्नलिखित बीमारियों का उनके संबंधित विवरणों से मिलान करें:

बीमारी	विवरण
1. मलेरिया	A. मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है
2. टीबी	B. बूदों से फैलता है
3. इन्फ्लूएंजा	C. बुखार और ठंड लगना
4. मधुमेह टाइप 1	D. उच्च रक्त शर्करा की ओर ले जाता है
5. हैजा	E. गंभीर निर्जलीकरण और दस्त की ओर ले जाता है

विकल्प:

- (A) 1-C, 2-A, 3-B, 4-D, 5-E
 (B) 1-B, 2-D, 3-A, 4-C, 5-E
 (C) 1-E, 2-C, 3-B, 4-A, 5-D
 (D) 1-C, 2-E, 3-D, 4-B, 5-A

उत्तर: (A)

व्याख्या: मलेरिया: प्लास्मोडियम परजीवी के कारण, एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। लक्षणों में बार-बार बुखार, ठंड लगना और पसीना आना शामिल है।

तपेदिक: माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण, यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, जिससे खांसी, सीने में दर्द और थकान होती है।

इन्फ्लूएंजा: एक वायरल संक्रमण जो सांस की बूंदों के माध्यम से फैलता है, जिससे तेज बुखार, शरीर में दर्द, गले में खराश और थकान होती है।

मधुमेह टाइप 1: एक ऑटोइम्यून बीमारी जिसमें शरीर इसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला करता है, जिससे इंसुलिन की कमी के कारण रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है।

हैजा: विभिन्नों कोलेरा बैक्टीरिया के कारण, यह तेजी से तरल पदार्थ की कमी, गंभीर निर्जलीकरण और पानी जैसा दस्त का कारण बनता है, जो अक्सर दृष्टिपानी के कारण होता है।

4. निम्नलिखित टीकों का मिलान उन बीमारियों से करें जिनसे वे बचाव करते हैं:

टीके	रोके जाने वाले रोग
1. बीसीजी वैक्सीन	A. खसरा, कण्ठमाला और रूबेला
2. एमएमआर वैक्सीन	B. क्षय रोग
3. डीपीटी वैक्सीन	C. टेटनस, डिघीरिया और पर्टुसिस
4. हेपेटाइटिस बी वैक्सीन	D. हेपेटाइटिस बी
5. वैरिसेला वैक्सीन	E. चिकनपॉक्स

विकल्पः

- (A) 1-C, 2-D, 3-A, 4-E, 5-B
(B) 1-E, 2-C, 3-B, 4-A, 5-D
(C) 1-A, 2-E, 3-D, 4-B, 5-C
(D) 1-B, 2-A, 3-C, 4-D, 5-E

उत्तरः (D)

व्याख्या: बीसीजी वैक्सीन: तपेदिक की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से बच्चों में प्रभावी।

एमएमआर वैक्सीन: खसरा, कण्ठमाला और रूबेला से बचाता है।

डीपीटी वैक्सीन: तीन जीवाणु संक्रमणों से लड़ता है: डिघीरिया, पर्टुसिस (काली खांसी), और टेटनस।

हेपेटाइटिस बी वैक्सीन: हेपेटाइटिस बी के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जो यकृत को प्रभावित करने वाला एक वायरल संक्रमण है।

वैरिसेला वैक्सीन: चिकनपॉक्स, एक संक्रामक वायरल संक्रमण को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है।

5. निम्नलिखित प्रमुख सुनामी घटनाओं का उनके संबंधित वर्षों से मिलान करें:

सुनामी	घटना वर्ष
(a) लिस्बन सुनामी	1 – 2004
(b) क्राकाटोआ सुनामी	2 – 2011
(c) हिंद महासागर सुनामी	3 – 1755
(d) जापान (तोहोकू) सुनामी	4 – 1883

विकल्पः

- (A) a-1, b-2, c-3, d-4
(B) a-4, b-1, c-2, d-3
(C) a-2, b-3, c-4, d-1
(D) a-3, b-4, c-1, d-2
(D)

उत्तरः **व्याख्या:** लिस्बन सुनामी (1755): एक शक्तिशाली भूकंप के कारण आई इस सुनामी ने पुर्तगाल को तबाह कर दिया और यूरोपीय बौद्धिक वित्तन को गहराई से प्रभावित किया।
क्राकाटोआ सुनामी (1883): इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आई इस सुनामी में विशाल लहरों ने 36,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली।

हिंद महासागर सुनामी (2004): सबसे घातक सुनामी में से एक, सुमात्रा के तट पर 9.1 तीव्रता के भूकंप के कारण आई; 14 देशों में 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए।

जापान (तोहोकू) सुनामी (2011): 9.0 तीव्रता के भूकंप के कारण आई; फुकुशिमा परमाणु आपदा हुई और 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई।

निम्नलिखित का मिलान करें: भारत-संबंधित युद्ध और उनके वर्ष

युद्ध	वर्ष
(a) प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध	1- 1999
(b) कारगिल युद्ध	2- 1845
(c) प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध	3- 1775
(d) भारत-चीन युद्ध	4- 1962

विकल्पः

- (A) a-3, b-1, c-2, d-4
(B) a-2, b-3, c-1, d-4
(C) a-1, b-2, c-4, d-3
(D) a-3, b-4, c-2, d-1
(A)

उत्तरः **व्याख्या:** प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध (1775): मराठा उत्तराधिकार विवादों में ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण शुरू हुआ; 1782 में सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ।

कारगिल युद्ध (1999): कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठ के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष; भारत ने सफलतापूर्वक नियंत्रण पुनः प्राप्त कर लिया।

प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध (1845): सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया; आंशिक ब्रिटिश नियंत्रण के साथ समाप्त हुआ।

भारत-चीन युद्ध (1962): अक्साई चिन और नेफा पर विवाद से उत्पन्न सीमा संघर्ष; जिसके परिणामस्वरूप एक संक्षिप्त लैकिन तीव्र युद्ध हुआ।

निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों को सुमेलित कीजिए -

(a) कामसूत्र	1- वात्स्यायन
(b) प्रश्नोत्तरमालिका	2- भासा
(c) स्वप्रवसदत्तम	3- अमोघवर्षा

ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर लगाया गया है, जो कि अक्षय ऊर्जा (RE) जैसे सौर, पवन, बायोमास, आदि से अपनी बिजली का न्यूनतम प्रतिशत खरीदने के लिए हैं, यह भारत में फिर से अपनाने के लिए एक प्रमुख नीति उपकरण है।

(c) एनर्जी टिलेमा इंडेक्स - 1:

वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल द्वारा विकसित, एनर्जी टिलेमा इंडेक्स तीन मुख्य पहलुओं - ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा इंकिटी (पहुंच और सामर्थ्य), और पर्यावरणीय स्थिरता को संतुलित करने की उनकी क्षमता पर देशों का मूल्यांकन करता है। यह एक देश की ऊर्जा नीति प्रभावशीलता को दर्शाता है।

(d) पंप स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स - 2:

ये परियोजनाएं बड़े पैमाने पर ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के रूप में कार्य करती हैं। वे अतिरिक्त ऊर्जा (अक्सर सौर/हवा से) पानी को एक ऊंचे जलाशय में पंप करके संग्रहीत करते हैं। चरम की मांग के दौरान, बिजली उत्पन्न करने के लिए पानी जारी किया जाता है, पुनः परिवर्तनशीलता के कारण होने वाले ग्रिड में उतार-चढ़ाव को स्थिर किया जाता है।

12.

मिलान कीजिए:

अनुच्छेद (अनुदेशात्मक सिद्धांत - DPSP)	उद्देश्य / प्रावधान
(a) अनुच्छेद 44	1- ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना
(b) अनुच्छेद 47	2- राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना
(c) अनुच्छेद 50	3- सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को बढ़ावा देना
(d) अनुच्छेद 43	4- पोषण स्तर को बढ़ाने और जनस्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का दायित्व

विकल्प:

- (A) a-4, b-1, c-2, d-4
- (B) a-1, b-2, c-3, d-4
- (C) a-3, b-2, c-4, d-1
- (D) a-3, b-4, c-2, d-1

उत्तर:

व्याख्या:

(a)

अनुच्छेद 44 — 3: भारत में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) को लागू करने का निर्देश देता है।

(b) अनुच्छेद 47 — 4: राज्य को पोषण स्तर, जीवन स्तर, और जनस्वास्थ्य में सुधार करने का निर्देश देता है।

13.

- (c) अनुच्छेद 50 — 2: राज्य के मामलों में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने का उद्देश्य रखता है।
- (d) अनुच्छेद 43 — 1: ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है।

निम्नलिखित संसदीय समितियों का उनकी संबंधित विशेषताओं से मिलान करें:

संसदीय समिति	विशेषताएँ
(a) विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ	1- सरकारी व्यय पर CAG रिपोर्टों की जाँच करती हैं
(b) सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति	2- सार्वजनिक व्यय में मितव्यिता और दक्षता के लिए वैकल्पिक नीतियाँ सुझाती हैं
(c) लोक लेखा समिति	3- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSE) के कामकाज की समीक्षा करती हैं
(d) प्राक्कलन समिति	4- विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जाँच करती हैं

विकल्प:

- (A) a-4, b-3, c-1, d-2
- (B) a-1, b-2, c-3, d-4
- (C) a-2, b-1, c-4, d-3
- (D) a-3, b-2, c-1, d-4

उत्तर:

व्याख्या: a-4 (डीआरएससी → अनुदानों की माँगों की जाँच):

विभागीय संबद्ध स्थायी समितियाँ (डीआरएससी) बजट पारित होने से पहले विभिन्न मंत्रालयों की अनुदानों की माँगों की विस्तृत जाँच के लिए गठित की जाती हैं।

b-3 (सीओपीयू → सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा):

सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) के कामकाज, प्रदर्शन और स्वायत्ता की जाँच करती है।

c-1 (पीएसी → सीएजी रिपोर्टों की जाँच):

लोक लेखा समिति (पीएसी) संसद द्वारा अधिकृत सार्वजनिक धन के सरकार द्वारा व्यय के तरीके पर सीएजी रिपोर्टों का लेखा-परीक्षण करने के लिए ज़िम्मेदार है।

d-2 (अनुमान समिति → नीतिगत विकल्प सुझाती है):

अनुमान समिति बजट अनुमानों का विश्लेषण करती है और सरकारी खर्च में बेहतर मितव्यिता और दक्षता के लिए वैकल्पिक नीतियों की सिफारिश करती है।

निम्नलिखित संवैधानिक निकायों का उनके स्थापना वर्ष से मिलान कीजिए:

संवैधानिक निकाय	स्थापना वर्ष
-----------------	--------------

(a) संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)	1- 1950
(b) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)	2- 1951
(c) भारत का चुनाव आयोग (ECI)	3- 1926
(d) वित्त आयोग	4- 1950

विकल्पः

- (A) a-2, b-3, c-1, d-4
 (B) a-3, b-1, c-2, d-4
 (C) a-3, b-4, c-1, d-2
 (D) a-3, b-4, c-2, d-1

उत्तरः (C)

व्याख्या: UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को ब्रिटिश शासन के तहत लोक सेवा आयोग के रूप में हुई थी। 1950 के बाद यह एक संवैधानिक निकाय बन गया।

b-4 (CAG → 1950):

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का कार्यालय 26 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किया गया था।

c-1 (ECI → 1950):

भारत के गणतंत्र बनने से एक दिन पहले, 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग का गठन किया गया था।

d-2 (वित्त आयोग → 1951):

भारत का पहला वित्त आयोग 1951 में अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया गया था।

15.

भारत में निम्नलिखित समुद्री सीमावर्ती देशों को सुमेलित कीजिए -

(a) एड्रियाटिक सागर	1- अल्बानिया
(b) काला सागर	2- मोरक्को
(c) कैस्पियन सागर	3- कजाकिस्तान
(d) भूमध्य सागर	4- यूक्रेन

विकल्पः

- (A) a-1, b-4, c-3, d-2
 (B) a-2, b-3, c-1, d-4
 (C) a-1, b-2, c-4, d-3
 (D) a-1, b-3, c-2, d-4

उत्तरः (A)

व्याख्या: एड्रियाटिक सागर - अल्बानिया
 काला सागर - यूक्रेन
 कैस्पियन सागर - कजाकिस्तान
 भूमध्य सागर - मोरक्को

16.

भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों का मिलान करें -

(a) कांडला	1- गुजरात
(b) पारादीप	2- उड़ीसा
(c) मैंगलोर	3- कर्नाटक

विकल्पः

- (A) a-1, b-2, c-3

(B) a-2, b-3, c-1

(C) a-3, b-2, c-1

(D) a-1, b-3, c-2

उत्तरः (A)

व्याख्या: कांडला - गुजरात
 पारादीप - उड़ीसा
 मैंगलोर - कर्नाटक

17.

भारत में निम्नलिखित थर्मल पावर स्टेशनों का मिलान करें -

(a) दुर्गापुर टीपीपी	1- पश्चिम बंगाल
(b) सिक्का टीपीएस	2- गुजरात
(c) सतपुड़ा टीपीएस	3- उत्तर प्रदेश
(d) सिंगरौली सुपर टीपीएस	4- मध्य प्रदेश

विकल्प

- (A) a-1, b-4, c-3, d-2
 (B) a-2, b-3, c-1, d-4
 (C) a-1, b-2, c-4, d-3
 (D) a-1, b-3, c-2, d-4

उत्तरः (C)

व्याख्या: दुर्गापुर टीपीपी - पश्चिम बंगाल
 सिक्का टीपीएस - गुजरात
 सतपुड़ा टीपीएस - मध्य प्रदेश
 सिंगरौली सुपर टीपीएस - उत्तर प्रदेश

18.

भारत में निम्नलिखित प्रसिद्ध गुफाओं का मिलान करें -

(a) महाराष्ट्र	1- भाजा गुफाएँ
(b) उड़ीसा	2- उदयगिरि और खंडगिरि गुफाएँ
(c) तमिलनाडु	3- महाबलीपुरम

विकल्प

- (A) a-1, b-2, c-3
 (B) a-2, b-3, c-1
 (C) a-3, b-2, c-1
 (D) a-1, b-3, c-2

उत्तरः (A)

व्याख्या: महाराष्ट्र - भाजा गुफाएँ
 उड़ीसा - उदयगिरि और खंडगिरि गुफाएँ
 तमिलनाडु - महाबलीपुरम

19.

भारतीय द्वीपों का उनकी प्रमुख विशेषताओं से मिलान करें:

ड्रोन का नाम	प्रमुख विशेषता
(a) लक्ष्य	1. ISTAR भूमिकाओं के लिए विकसित MALE UAV
(b) निशांत	2. कम तीव्रता वाले संघर्ष में प्रयुक्त कम दूरी का UAV

(c) रुस्तम-1	3. SR-RPAS (800 किमी वर्ग); ISR और छवि शोषण के लिए प्रयुक्त
(d) TAPAS (रुस्तम-2)	4. रॉकेट-लॉन्च टर्बोजेट-संचालित लक्ष्य ड्रोन
(e) आर्चर	5. निगरानी और तोपखाने की आग सुधार के लिए बहु-मिशन यूएवी

विकल्प:

- (A) a-4, b-5, c-3, d-1, e-2
 (B) a-1, b-4, c-2, d-3, e-5
 (C) a-4, b-3, c-5, d-2, e-1
 (D) a-5, b-2, c-1, d-4, e-3

उत्तर: (A)

व्याख्या: लक्ष्य → (4) प्रशिक्षण और टोही के लिए टर्बोजेट द्वारा संचालित एक रॉकेट-लॉन्च किया गया लक्ष्य ड्रोन।

निशांत → (5) एक बहु-मिशन यूएवी, जिसका उपयोग निगरानी, लक्ष्य ट्रैकिंग और तोपखाने की गोलाबारी सुधार के लिए किया जाता है।

रुस्तम-1 → (3) एक छोटी दूरी का आरपीएस, जो आईएसआर और छवि शोषण के लिए आदर्श है।

तापस/रुस्तम-2 → (1) आईएसटीएआर भूमिकाओं के लिए एक मध्यम ऊँचाई लंबी क्षमता (एमएएलई) यूएवी।

आर्चर → (2) छोटी दूरी, कम तीव्रता वाले संघर्ष अभियानों के लिए एक हथियारबंद यूएवी।

20. राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को उनकी उल्लेखनीय सफलता की कहानियों से सुमेलित कीजिए:

राज्य	सफलता की कहानी
(a) केरल	1. IFC के माध्यम से जमीनी स्तर पर नवाचार को समर्पन और NIF, NIT मिज़ोरम के साथ सहयोग
(b) तमिलनाडु	2. अनुसंधान में वापस लौटने वाली महिला वैज्ञानिकों के लिए फेलोशिप कार्यक्रमों का कार्यान्वयन
(c) पंजाब	3. बौद्धिक संपदा दाखिल करने में राष्ट्रीय अग्रणी और बौद्धिक संपदा पुरस्कार (विशेष प्रशस्ति पत्र) प्राप्तकर्ता
(d) मिज़ोरम	4. प्रदूषण नियंत्रण और सतत अर्थव्यवस्था के लिए धान की पराली प्रबंधन
(e) मणिपुर	5. ग्रामीण उद्यम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के तहत सुगंधित पौधों की खेती

विकल्प:

- (A) a-3, b-2, c-4, d-1, e-5
 (B) a-1, b-2, c-3, d-5, e-4
 (C) a-2, b-4, c-3, d-5, e-1

(D) a-2, b-3, c-4, d-1, e-5

उत्तर: (D)

व्याख्या: केरल → (2): महिला वैज्ञानिकों को अवकाश के बाद शोध करियर फिर से शुरू करने में मदद करने वाले अपने फेलोशिप कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु → (3): पेटेंट और जीआई दाखिलों में शीर्ष रैंकिंग के साथ, भारत के आईपी नेता के रूप में उभरा, और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया।

पंजाब → (4): धान की पराली प्रबंधन, प्रदूषण से निपटने और टिकाऊ कृषि-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है।

मिज़ोरम → (1): आईएफसी के माध्यम से, यह एनआईएफ और एनआईटी मिज़ोरम के साथ साझेदारी में 175 से अधिक उत्पादों के विकास के साथ, जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देता है।

मणिपुर → (5): राष्ट्रीय मिशन के तहत इसकी सुगंधित पौधों की पहल, ग्रामीण उद्यमिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है।

निम्नलिखित कृषि मिशनों का उनके संबंधित उद्देश्यों से मिलान कीजिए:

(a) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)	1- बागवानी उत्पादन में सतत वृद्धि
(b) बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (MIDH)	2- चावल, गेहूँ, दालों और मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाना
(c) राष्ट्रीय तिलहन और पाम ऑयल मिशन (NMOOP)	3- तिलहन और पाम ऑयल की उत्पादकता बढ़ाना
(d) कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (SMAM)	4- छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना

विकल्प:

- (A) a-2, b-1, c-3, d-4
 (B) a-3, b-2, c-1, d-4
 (C) a-4, b-1, c-2, d-3
 (D) a-2, b-4, c-3, d-1
 (A)

व्याख्या: एनएफएसएम → (2): खाद्यान्नों (विशेषकर चावल, गेहूँ, दालें, मोटे अनाज) का उत्पादन स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए 2007 में शुरू किया गया।

एमआईडीएच → (1): फलों, सब्जियों, मसालों और फूलों सहित बागवानी उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक कैंद्र प्रायोजित योजना।

एनएमओओपी → (3): इसका उद्देश्य तिलहन और पाम अँयल की उत्पादकता बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना है।

एसएमएएम → (4): उत्पादकता में सुधार और श्रम निर्भरता को कम करने के लिए, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि मशीनीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है।

22. निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों का उनके प्रमुख प्रावधानों से मिलान कीजिए:

(a) 42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976	1- पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया
(b) 44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978	2- मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर अंकुश लगाया गया
(c) 73वाँ संशोधन अधिनियम, 1992	3- प्रस्तावना में "समाजवादी", "धर्मनिरपेक्ष" और "अखंडता" शब्द जोड़े गए
(d) 24वाँ संशोधन अधिनियम, 1971	4- आपातकाल से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करके नागरिक स्वतंत्रताएँ बहाल की गई

विकल्प:

- (A) a-4, b-1, c-2, d-3
 (B) a-2, b-3, c-4, d-1
 (C) a-3, b-4, c-1, d-2
 (D) a-1, b-2, c-3, d-4

उत्तर: (C)

व्याख्या: 42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976 → (3): इसे "लघु संविधान" के रूप में जाना जाता है, इसने प्रस्तावना में "समाजवाद", "धर्मनिरपेक्ष" और "अखंडता" शब्द जोड़े और नीति निर्देशक सिद्धांतों का विस्तार किया।

44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978 → (4): आपातकाल के दौरान सीमित की गई नागरिक स्वतंत्रताओं, विशेषकर अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त सुरक्षाओं को बहाल किया। 73वाँ संशोधन अधिनियम, 1992 → (1): पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, भाग IX और अनुसूची XI को शामिल किया गया।

24वाँ संशोधन अधिनियम, 1971 → (2): यह प्रतिपादित किया गया कि संसद को संविधान के किसी भी भाग, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, में संशोधन करने की शक्ति है (गोलकनाथ मामले के प्रत्युत्तर में)।

23. नदी तट पर स्थित निम्नलिखित शहरों का मिलान करें -

(a) कुरनूल	1- तुंगभद्रा
(b) कटक	2- महानदी

(c) डिब्रुगढ़	3- सतलुज
(d) फिरोजपुर	4- ब्रह्मपुत्र

विकल्प

- (A) a-1, b-4, c-3, d-2
 (B) a-2, b-3, c-1, d-4
 (C) a-1, b-2, c-4, d-3
 (D) a-1, b-3, c-2, d-4

उत्तर:

व्याख्या: कुरनूल - तुंगभद्रा

कटक - महानदी

डिब्रुगढ़ - ब्रह्मपुत्र

फिरोजपुर - सतलुज

भारत में निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व का मिलान करें -

(a) सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व	1- ओडिशा
(b) अचानकमार - अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व	2- छत्तीसगढ़
(c) अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व	3- केरल और तमिलनाडु

विकल्प

- (A) a-1, b-2, c-3
 (B) a-2, b-3, c-1
 (C) a-3, b-2, c-1
 (D) a-1, b-3, c-2

उत्तर:

व्याख्या: सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व - ओडिशा

अचानकमार - अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व - छत्तीसगढ़

अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व - केरल और तमिलनाडु

निम्नलिखित का मिलान करें:

राज्य	जनजातियाँ
(a) नागालैंड	1. चेंचू, येरुकुला, कोया
(b) राजस्थान	2. एओ, अंगामी, कोन्याक
(c) आंध्र प्रदेश	3. गरासिया, सहरिया, भील
(d) ओडिशा	4. बोंडा, साओरा, कोंथ
(e) मध्य प्रदेश	5. गोंड, बैगा, भील

विकल्प:

- (A) a-2, b-3, c-1, d-4, e-5
 (B) a-1, b-2, c-5, d-3, e-4
 (C) a-2, b-5, c-1, d-3, e-4
 (D) a-3, b-1, c-2, d-5, e-4

उत्तर:

व्याख्या:

(a) नागालैंड

- एओ, अंगामी, कोन्याक

(b) राजस्थान - गरासिया, सहरिया, भील

(c) आंध्र प्रदेश - चेंचू, येरुकुला, कोया

- (d) ओडिशा - बोंडा, साओरा, कोंध
 (e) मध्य प्रदेश - गोंड, बैगा, भील

26. निम्नलिखित का मिलान करें:

बांड के प्रकार	विशेषताएँ
(a) शून्य कूपन बांड	1. अंकित मूल्य पर जारी किया जाता है, लेकिन समय-समय पर ब्याज देता है
(b) शाश्वत बांड	2. छूट पर जारी किया जाता है, कोई आवधिक ब्याज नहीं
(c) मुद्रास्फीति-सूचकांकित बांड	3. मूलधन और ब्याज मुद्रास्फीति सूचकांक से जुड़ा होता है
(d) प्रतिदेय बांड	4. जारीकर्ता द्वारा परिपक्ता से पहले भुनाया जा सकता है
(e) निश्चित दर बांड	5. पूरी अवधि के दौरान स्थिर ब्याज देता है

विकल्प:

- (A) a-2, b-4, c-3, d-4, e-5
 (B) a-3, b-2, c-5, d-1, e-4
 (C) a-2, b-4, c-3, d-1, e-5
 (D) a-2, b-1, c-3, d-4, e-5

उत्तर: (D)

व्याख्या: शून्य कूपन बॉन्ड (a-2): छूट पर बेचा जाता है, अपनी अवधि के दौरान कोई ब्याज नहीं देता; परिपक्ता पर पूरा अंकित मूल्य देता है।

शाश्वत बांड (b-1): कोई परिपक्ता तिथि नहीं; हमेशा के लिए नियमित ब्याज देता है।

मुद्रास्फीति-सूचकांकित बॉन्ड (c-3): मूलधन और ब्याज दोनों को मुद्रास्फीति (जैसे, WPI या CPI) के अनुसार समायोजित किया जाता है।

प्रतिदेय बॉन्ड (d-4): जारीकर्ता को परिपक्ता से पहले ही भुनाने का अधिकार देता है।

निश्चित दर बॉन्ड (e-5): अपनी अवधि के दौरान एक पूर्व-निर्धारित स्थिर ब्याज (कूपन) देता है।

27. भारत में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों का मिलान करें -

(a) मध्य प्रदेश	1- संजय राष्ट्रीय उद्यान
(b) कर्णाटक	2- नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान
(c) पश्चिम बंगाल	3- बन्द्रेरघटा राष्ट्रीय उद्यान
(d) महाराष्ट्र	4- नेगांव राष्ट्रीय उद्यान

विकल्प

- (A) a-1, b-4, c-3, d-2
 (B) a-2, b-3, c-1, d-4
 (C) a-1, b-2, c-4, d-3
 (D) a-1, b-3, c-2, d-4

उत्तर: (D)

व्याख्या: मध्य प्रदेश - संजय राष्ट्रीय उद्यान

कर्णाटक - बन्द्रेरघटा राष्ट्रीय उद्यान
 पश्चिम बंगाल - नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान
 महाराष्ट्र - नेगांव राष्ट्रीय उद्यान

28.

भारत में निम्नलिखित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का मिलान करें

(a) तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन	1- महाराष्ट्र
(b) काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन	2- गुजरात
(c) कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र	3- तमिलनाडु

विकल्प

- (A) a-1, b-2, c-3
 (B) a-2, b-3, c-1
 (C) a-3, b-2, c-1
 (D) a-1, b-3, c-2

उत्तर:

व्याख्या: तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन - महाराष्ट्र
 काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन - गुजरात
 कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र - तमिलनाडु

29.

2011 की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें -

(a) सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य	1- बिहार
(b) सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य	2- केरल
(c) सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य	3- अरुणाचल प्रदेश
(d) सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य	4- हरियाणा

विकल्प

- (A) a-1, b-4, c-3, d-2
 (B) a-2, b-3, c-1, d-4
 (C) a-1, b-2, c-4, d-3
 (D) a-1, b-3, c-2, d-4

उत्तर:

व्याख्या: सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य - बिहार
 सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य - अरुणाचल प्रदेश
 सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य - केरल
 सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य - हरियाणा

30.

निम्नलिखित बुकर पुरस्कार विजेताओं 2022 और उनके कार्यों का मिलान करें (शॉर्टलिस्ट के लिए नामांकित व्यक्ति)

(a) एलन गार्नर	1- ट्रेकल वॉकर
(b) क्लेयर कीगन	2- स्मॉल थिंग्स इन लाइफ
(c) एलिजाबेथ स्ट्रॉथ	3- ओह विलियम!

विकल्प

- (A) a-1, b-2, c-3
 (B) a-2, b-3, c-1
 (C) a-3, b-2, c-1

(D) a-1, b-3, c-2

उत्तर: (A)

व्याख्या: एलन गार्नर - ट्रैकल वॉकर
क्लेयर कीगन - स्मॉल थिंग्स इन लाइफ
एलिज़ाबेथ स्ट्रॉथ - ओह विलियम!

31. निम्नलिखित को मिलाएं -

सूची I	सूची II
(a) वर्ड रैप	1- किसी शब्द को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जाता है यदि वह वर्तमान पंक्ति में फिट नहीं होता है
(b) क्लाइंट	2- एक ही कंप्यूटर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का इंटरलीड निष्पादन
(c) मल्टीटास्किंग	3- डेटा प्राप्त करने वाला एप्लिकेशन
(d) लैंडस्केप	4- वर्कशीट का ओरिएंटेशन

विकल्प

- (A) a-1, b-4, c-3, d-2
 (B) a-2, b-3, c-1, d-4
 (C) a-1, b-2, c-4, d-3
 (D) a-1, b-3, c-2, d-4

उत्तर: (D)

व्याख्या: वर्ड रैप - किसी शब्द को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जाता है यदि वह वर्तमान पंक्ति में फिट नहीं होता है
 क्लाइंट - डेटा प्राप्त करने वाला एप्लिकेशन
 मल्टीटास्किंग - एक ही कंप्यूटर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का इंटरलीड निष्पादन
 लैंडस्केप - वर्कशीट का ओरिएंटेशन

32. निम्नलिखित राज्यों और उनके नृत्य रूपों का मिलान करें -

(a) घूमर	1- राजस्थान
(b) छऊ	2- मयूरभंजी
(c) बिहू	3- असम

विकल्प

- (A) a-1, b-2, c-3
 (B) a-2, b-3, c-1
 (C) a-3, b-2, c-1
 (D) a-1, b-3, c-2

उत्तर: (A)

व्याख्या:

घूमर - राजस्थान
 छऊ - मयूरभंजी
 बिहू - असम

33. राष्ट्रीय महत्व के निम्नलिखित स्मारकों का उनकी विशेषताओं या ऐतिहासिक महत्व से मिलान कीजिए:

स्मारक	विशेषता/महत्व
--------	---------------

(a) रबडेंटसे खंडहर, सिक्किम	1- भारतीय संसद भवन के गोलाकार डिज़ाइन की प्रेरणा
(b) मार्टड सूर्य मंदिर, अनंतनाग	2- सिक्किम साम्राज्य की पूर्व राजधानी, अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्थल
(c) चौसठ योगिनी मंदिर, मुरैना	3- कश्मीर में ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा निर्मित 8वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर
(d) शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम	4- 16वीं शताब्दी में निर्मित भारत-अफगान शैली की अष्टकोणीय संरचना

विकल्प:

- (A) a-1, b-2, c-3, d-4
 (B) a-2, b-3, c-1, d-4
 (C) a-4, b-1, c-2, d-3
 (D) a-3, b-4, c-2, d-1

उत्तर: (B)

व्याख्या: (a) रबडेंटसे खंडहर - सिक्किम साम्राज्य की राजधानी; भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत पुरातात्त्विक महत्व।
 (b) मार्टड सूर्य मंदिर - कश्मीर में प्राचीन सूर्य मंदिर, जिसका निर्माण ललितादित्य ने आठवीं शताब्दी में करवाया था।

(c) चौसठ योगिनी मंदिर - खुला गोलाकार मंदिर, जिसने भारतीय संसद के डिज़ाइन को प्रभावित किया।
 (d) शेरशाह सूरी का मकबरा - अफगान स्थापत्य शैली का प्रतिनिधित्व करने वाली अष्टकोणीय मकबरा संरचना।

34. निम्नलिखित ऐंगोलिक विशेषताओं का उनकी विशेषताओं या स्थानों से मिलान करें:

ऐंगोलिक विशेषता	संबंधित विवरण/स्थान
(a) बैदैन जारन रेगिस्टान	1- नामीबियाई तट पर तेज़ तटीय हवाओं द्वारा निर्मित तटीय रेत के टीले
(b) एर्ग चेब्बी	2- मोरक्को में रेत का समुद्र जौ बड़े अर्धचंद्राकार टीलों के लिए जाना जाता है
(c) कंकाल तट	3- आंतरिक मंगोलिया में दुनिया के कुछ सबसे ऊँचे स्थिर टीले हैं
(d) लोएस पठार	4- उत्तरी चीन में रेगिस्टान से हवा द्वारा उड़ाई गई गाद द्वारा निर्मित निक्षेपण विशेषता

विकल्प:

- (A) a-1, b-3, c-4, d-2
 (B) a-2, b-4, c-3, d-1
 (C) a-3, b-2, c-1, d-4
 (D) a-4, b-1, c-2, d-3

उत्तर: (C)

- व्याख्या:** (a) बदायूँ जारन रेगिस्टान - चीन के भीतरी मंगोलिया में स्थित; 500 मीटर ऊँचे स्थिर रेत के टीलों के लिए जाना जाता है।
 (b) एर्ग चेब्बी - मोरक्को में एक प्रसिद्ध सहारा रेगिस्टानी रेत का मैदान; विशाल रेत के टीले (अर्धचंद्राकार) बनाता है।
 (c) कंकाल तट - नामीबिया में एक धूधली, बंजर तटरेखा, जहाँ हवाओं द्वारा आकार दिए गए विशाल तटीय टीले हैं।
 (d) लोएस पठार - उत्तरी चीन में हवा से जमा गाद वाला पठार; अत्यधिक उपजाऊ लेकिन कटाव-प्रवण।

35. निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों का उनके योगदान से मिलान कीजिए:

स्वतंत्रता सेनानी	योगदान
(a) राम प्रसाद बिस्मिल	1- स्टटगार्ट में भारतीय ध्वज का पहला संस्करण फहराया
(b) भीकाजी कामा	2- काकोरी षडयंत्र कांड (1925) से जुड़े
(c) मातंगिनी हाजरा	3- तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद
(d) सूर्य सेन	4- चटगाँव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया (1930)

विकल्प:

- (A) a-2, b-1, c-3, d-4
 (B) a-3, b-4, c-1, d-2
 (C) a-1, b-3, c-4, d-2
 (D) a-2, b-4, c-1, d-3

उत्तर:**व्याख्या:**

- राम प्रसाद बिस्मिल (a-2): काकोरी षडयंत्र में प्रमुख व्यक्ति।
 भीकाजी कामा (b-1): जर्मनी के स्टटगार्ट में पहला भारतीय ध्वज फहराया।
 मातंगिनी हाजरा (c-3): भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई।
 सूर्य सेन (d-4): बंगाल में चटगाँव शस्त्रागार पर हमले का नेतृत्व किया।

36. निम्नलिखित सर्वोच्च न्यायालय के मामलों का उनके प्रमुख निर्णयों से मिलान करें:

केस	फैसला
(a) न्यायमूर्ति के.एस. पुद्दस्वामी बनाम भारत संघ	1 - आजीविका का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है
(b) इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ	2 - निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया

(c) मेनका गांधी बनाम भारत संघ	3 - 27% ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा; पदोन्नति में आरक्षण को रद्द किया गया
(d) ओला टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन	4 - अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाया गया

विकल्प:

- (A) a-2, b-1, c-3, d-4
 (B) a-3, b-1, c-2, d-4
 (C) a-4, b-2, c-1, d-3
 (D) a-2, b-3, c-4, d-1

उत्तर:**व्याख्या:** न्यायमूर्ति के.एस. पुद्दस्वामी (2017): निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना।

इंद्रा साहनी (1992): 27% ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा, पदोन्नति में आरक्षण को अस्वीकार किया।

मेनका गांधी (1978): अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यापक व्याख्या की।

ओला टेलिस (1985): घोषित किया कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है।

37. निम्नलिखित भारतीय उपग्रहों का उनके प्राथमिक उद्देश्यों से मिलान कीजिए:

उपग्रह	उद्देश्य
(a) कार्टॉसैट-3	1- संचार और डिजिटल कनेक्टिविटी
(b) जीसैट-30	2- उच्च-रिज़ॉल्यूशन पृथ्वी अवलोकन
(c) रीसैट-2बी	3- सभी मौसमों में निगरानी के लिए रडार इमेजिंग
(d) एस्ट्रोसैट	4- अंतरिक्ष-आधारित खगोलीय अवलोकन

विकल्प:

- (A) a-2, b-1, c-3, d-4
 (B) a-3, b-2, c-1, d-4
 (C) a-1, b-3, c-2, d-4
 (D) a-2, b-4, c-1, d-3

(A)**व्याख्या:** कार्टॉसैट-3: उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग क्षमताओं वाला एक तीसरी पीढ़ी का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह (उद्देश्य 2)।

जीसैट-30: डिजिटल प्रसारण और इंटरनेट सेवाओं के लिए इनसैट-4ए का स्थान लेने वाला एक संचार उपग्रह (उद्देश्य 1)।

रीसैट-2बी: सभी मौसमों में निगरानी के लिए सिथेटिक अपर्चर रडार से सुसज्जित (उद्देश्य 3)।

एस्ट्रोसैट: भारत की पहली समर्पित बहु-तरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला (उद्देश्य 4)।

38. निम्नलिखित अधिनियमों का उनके प्राथमिक उद्देश्य से मिलान कीजिए:

अधिनियम	उद्देश्य
(a) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986	1- जैविक विविधता का विनियमन और आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच
(b) जैविक विविधता अधिनियम, 2002	2- भोपाल गैस त्रासदी के बाद व्यापक कानून
(c) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972	3- अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों के माध्यम से वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण
(d) वन संरक्षण अधिनियम, 1980	4- गैर-वनीय उपयोग के लिए वन भूमि के अनारक्षण और उपयोग पर प्रतिबंध

विकल्पः

- (B) a-1, b-2, c-4, d-3
 (A) a-2, b-1, c-3, d-4
 (C) a-3, b-4, c-2, d-1
 (D) a-4, b-3, c-1, d-2

उत्तरः

- (A)

39. उनकी प्रमुख विशेषताओं या उद्देश्य के साथ निम्नलिखित राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का मिलान करें।

पुरस्कार	प्रमुख विशेषताएँ
(a) राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार	1. खेल में उत्कृष्टता के लिए वादा करने वाले युवा एथलीटों को दिया गया
(b) अर्जुन अवार्ड	2. अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में असाधारण प्रदर्शन के लिए भारत में उच्चतम खेल सम्मान
(c) द्रोणाचार्य अवार्ड	3. पदक विजेता एथलीटों के निर्माण के लिए कोचों को सम्मानित किया गया
(d) ध्यान चंद अवार्ड	4. खेल विकास में योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड

विकल्पः

- (A) a-2, b-3, c-1, d-4
 (B) a-2, b-1, c-4, d-3
 (C) a-2, b-1, c-3, d-4
 (D) a-1, b-2, c-3, d-4

उत्तरः

- (C)

व्याख्या: (a) राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में सबसे अधिक खेल सम्मान है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में असाधारण प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है।

(b) अर्जुन पुरस्कार खेल में उत्कृष्टता के लिए युवा एथलीटों को होनहार करने के लिए दिया जाता है।

(c) द्रोणाचार्य पुरस्कार पदक विजेता एथलीटों के निर्माण के लिए कोचों को प्रदान किया जाता है।

(d) ध्यान चंद अवार्ड खेल विकास में योगदान के लिए एक लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड है।

40.

निम्नलिखित रासायनिक यौगिकों को उनके साथ मिलान करें।

यौगिक	रासायनिक सूत्र
(a) अमोनियम नाइट्रेट	1-Ca(OH) ₂
(b) कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड	2-NH ₄ NO ₃
(c) एसिटिक एसिड	3-C ₂ H ₄ O ₂
(d) पोटेशियम परमैग्नेट	4-KMnO ₄

विकल्पः

- (A) a-3, b-4, c-2, d-1
 (B) a-2, b-1, c-3, d-4
 (C) a-4, b-3, c-2, d-1
 (D) a-1, b-2, c-4, d-3

उत्तरः

- (B)

व्याख्या: अमोनियम नाइट्रेट (NH₄NO₃): एक उर्वरक के रूप में और विस्फोटकों में उपयोग किया जाता है।

कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड (Ca(OH)₂): स्लेक्ड लाइम के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग निर्माण और जल उपचार में किया जाता है।

एसिटिक एसिड (C₂H₄O₂): सिरका का मुख्य घटक, भोजन और रासायनिक प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है।

पोटेशियम परमैग्नेट (KMnO₄): एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट जो कीटाणुशोधन और जल उपचार में उपयोग किया जाता है।

41.

भारत में निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों का मिलान करें -

(a) असम	1- बोर्डीइबाम बीलमुख पक्षी अभ्यारण्य
(b) बिहार	2- सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य
(c) गोवा	3- नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य
(d) गुजरात	4- गागा वन्यजीव अभ्यारण्य

विकल्पः

- (A) a-1, b-4, c-3, d-2
 (B) a-2, b-3, c-1, d-4
 (C) a-1, b-2, c-4, d-3
 (D) a-1, b-3, c-2, d-4

उत्तरः

- (D)

व्याख्या: असम - बोर्डीइबाम बीलमुख पक्षी अभ्यारण्य

बिहार - नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य

गोवा - सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य

गुजरात - गागा वन्यजीव अभ्यारण्य



42. भारत में राज्यों के गठन की निम्नलिखित तिथियों का मिलान करें -

(a) हिमाचल प्रदेश	1- 1971
(b) झारखण्ड	2- 2000
(c) कर्नाटक	3- 1956

विकल्प

- (A) a-1, b-2, c-3
 (B) a-2, b-3, c-1
 (C) a-3, b-2, c-1
 (D) a-1, b-3, c-2

उत्तर: (A)

व्याख्या: हिमाचल प्रदेश - 1971
 झारखण्ड - 2000
 कर्नाटक - 1956

43. निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों का उनकी विशिष्ट विशेषताओं या स्थानों से मिलान करें:

राष्ट्रीय उद्यान	विशेषता / स्थान
(a) बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान	1- भारत का एकमात्र उद्यान जहाँ चारों बड़ी बिल्लियाँ पाई जाती हैं: बाघ, तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ, हिम तेंदुआ
(b) नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान	2- मेघालय में स्थित; 'आत्माओं की भूमि' के रूप में जाना जाता है
(c) पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान	3- छत्तीसगढ़ में स्थित; भारत के 54वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में प्रस्तावित
(d) गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान	4- हिमाचल प्रदेश का एकमात्र शीत मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान

विकल्प:

- (A) a-1, b-2, c-4, d-3
 (B) a-3, b-4, c-2, d-1
 (C) a-2, b-1, c-4, d-3
 (D) a-4, b-1, c-3, d-2

उत्तर: (C)

व्याख्या: (a) बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान - 2: मेघालय में स्थित, यह गारो जनजाति द्वारा 'आत्माओं की भूमि' के रूप में पूजनीय है।
 (b) नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान - 1: अरुणाचल प्रदेश में, चारों बड़ी बिल्लियों वाला एकमात्र भारतीय उद्यान: बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ।
 (c) पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान - 4: हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में स्थित, यह राज्य का एकमात्र ठंडा रेगिस्तानी राष्ट्रीय उद्यान है।
 (d) गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान - 3: छत्तीसगढ़ में स्थित, और भारत के 54वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में प्रस्तावित।

निम्नलिखित ओलंपिक खेलों को उनके विशिष्ट तथ्यों या विशेषताओं से मिलाएँ:

ओलंपिक खेल	विशिष्ट तथ्य/विशेषता
(a) मॉर्डन पेंटाथलॉन	1- इसमें वॉल्ट, पॉमेल हॉर्स और फ्लोर एक्सरसाइज़ जैसी स्पर्धाएँ शामिल हैं
(b) आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक	2- इसमें तलवारबाज़ी, तैराकी, घुड़सवारी शो जंपिंग, पिस्टल शूटिंग और दौड़ शामिल हैं
(c) कैनो स्लैलम	3- एथलीट क्याक या कैनो का उपयोग करके सफेद पानी की तेज़ धाराओं पर दौड़ लगाते हैं
(d) रिदमिक जिम्नास्टिक	4- केवल महिलाएँ भाग लेती हैं, रिबन और हूप जैसे उपकरणों के साथ प्रदर्शन करती हैं

विकल्प:

- (A) a-2, b-1, c-3, d-4
 (B) a-3, b-2, c-4, d-1
 (C) a-1, b-4, c-2, d-3
 (D) a-4, b-3, c-1, d-2

उत्तर: (A)

व्याख्या: (a) मॉर्डन पेंटाथलॉन - 2: इसमें पाँच विधाएँ शामिल हैं - तलवारबाज़ी, तैराकी, घुड़सवारी, निशानेबाज़ी और दौड़। इसे एक सैनिक के कौशल का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है।

(b) आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक - 1: इसमें वॉल्ट, पॉमेल हॉर्स, रिंग्स, फ्लोर और पैरेलल बार जैसे उपकरणों का उपयोग होता है; पुरुष और महिला दोनों प्रतिस्पर्धा करते हैं।

(c) कैनो स्लैलम - 3: इसमें एथलीट डोंगी या क्याक में सफेद पानी की तेज़ धाराओं को पार करते हैं, और कम से कम पेनल्टी के साथ सबसे तेज़ समय में दौड़ पूरी करने का लक्ष्य रखते हैं।

(d) रिदमिक जिम्नास्टिक - 4: इसमें केवल महिलाएँ ही प्रतिस्पर्धा करती हैं, और संगीत के साथ रिबन, हुप्स, गेंद और क्लब जैसे उपकरणों का उपयोग करती हैं।

निम्नलिखित प्रमुख पर्वत शृंखलाओं का उनके संबंधित देशों या स्थानों से मिलान करें:

पर्वत शृंखला	स्थान
(a) एंडीज़	1. उत्तरी अमेरिका (अमेरिका और कनाडा)
(b) आल्स	2. यूरोप (फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया)
(c) रॉकीज़	3. दक्षिण अमेरिका (चिली, पेरू, अर्जेंटीना)
(d) ग्रेट डिवाइंडिंग रेंज	4. ऑस्ट्रेलिया

विकल्पः

- (A) a-3, b-2, c-1, d-4
 (B) a-1, b-2, c-3, d-4
 (C) a-3, b-1, c-2, d-4
 (D) a-2, b-3, c-1, d-4

उत्तरः (A)

व्याख्या: Great Dividing Range → Eastern Australia (largest mountain range in Australia)

एंडीज़ → दक्षिण अमेरिका (सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला)

आल्प्स → यूरोप (फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया जैसे देशों में फैला हुआ)

रॉकी पर्वत → उत्तरी अमेरिका (अमेरिका और कनाडा)

ग्रेट डिवाइंडिंग रेंज → पूर्वी ऑस्ट्रेलिया (ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला)

46. निम्नलिखित प्रमुख खनिज भंडारों का उनके संबंधित देशों या स्थानों से मिलान करें:

खनिज भंडार	स्थान
(a) काराजस लौह अयस्क खदान	1. स्वीडन
(b) चुक्किकामाटा ताम्र खदान	2. ब्राज़ील
(c) किरुना लौह अयस्क खदान	3. चिली
(d) झारिया कोयला क्षेत्र	4. भारत

विकल्पः

- (A) a-1, b-2, c-3, d-4
 (B) a-2, b-3, c-1, d-4
 (C) a-3, b-1, c-4, d-2
 (D) a-4, b-2, c-3, d-1

उत्तरः (B)

व्याख्या: काराजस लौह अयस्क खदान → ब्राज़ील में स्थित चुक्किकामाटा ताम्र खदान → चिली में स्थित किरुना लौह अयस्क खदान → स्वीडन में स्थित झारिया कोयला क्षेत्र → भारत में स्थित

47. निम्नलिखित समितियों का उनके कार्यक्षेत्रों से मिलान कीजिए:

समिति	कार्यक्षेत्र
(a) बिबेक देबरॉय समिति	1- राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा
(b) बिमल जालान समिति	2- भारतीय रेलवे के पुनर्गठन से संबंधित
(c) कस्तूरीरंगन समिति	3- RBI के आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा
(d) टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समिति	4- पर्यावरण संबंधी कानूनों की समीक्षा

विकल्पः

- (A) a-2, b-3, c-1, d-4
 (B) a-1, b-2, c-3, d-4
 (C) a-3, b-4, c-2, d-1

(D) a-4, b-1, c-3, d-2

उत्तरः (A)

व्याख्या: बिबेक देबरॉय समिति → भारतीय रेलवे के पुनर्गठन के लिए गठित (2015)।

बिमल जालान समिति → RBI के आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा हेतु गठित (2019)।

कस्तूरीरंगन समिति → राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया।

टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समिति → पर्यावरण कानूनों की समीक्षा के लिए गठित (2014)।

48.

निम्नलिखित दिवसों का उनके मनाए जाने की तिथि से मिलान कीजिए:

दिवस / पहल	मनाए जाने की तिथि
(a) विश्व शौचालय दिवस	1- 16 नवंबर
(b) विश्व रेडक्रॉस दिवस	2- 8 मई
(c) अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस	3- जुलाई का पहला शनिवार
(d) राष्ट्रीय प्रेस दिवस	4- 19 नवंबर

विकल्पः

- (A) a-3, b-2, c-1, d-4
 (B) a-1, b-4, c-2, d-3
 (C) a-4, b-2, c-3, d-1
 (D) a-2, b-3, c-4, d-1

उत्तरः (C)

व्याख्या: विश्व शौचालय दिवस – 19 नवंबर को स्वच्छता की वैश्विक आवश्यकता पर जागरूकता के लिए मनाया जाता है।

विश्व रेडक्रॉस दिवस – 8 मई, रेडक्रॉस आंदोलन के संस्थापक हेनरी ड्यूनैट के जन्मदिन पर मनाया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस – हर साल जुलाई के पहले शनिवार को सहकारिता के मूल्यों के लिए मनाया जाता है।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस – 16 नवंबर को, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है।

49. निम्नलिखित का मिलान करें - प्रमुख पर्यावरण समझौते और उनकी प्रमुख विशेषताएँ -

संधि/समझौते	प्रमुख विशेषताएँ
(a) मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल	1 - आर्द्रभूमि संरक्षण
(b) कार्टिजिना प्रोटोकॉल	2 - विकसित देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य
(c) रामसर कन्वेन्शन	3 - तरलीकृत प्राकृतिक गैसों (LMO) की सीमा पार आवाजाही में जैव सुरक्षा
(d) क्योटो प्रोटोकॉल	4 - ओजोन-क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना

विकल्पः

- (A) a-4, b-3, c-1, d-2
 (B) a-3, b-1, c-2, d-4
 (C) a-1, b-2, c-4, d-3
 (D) a-2, b-4, c-1, d-3

उत्तर: (A)

व्याख्या: मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल → ओज़ोन-क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना।
 कार्टरेजना प्रोटोकॉल → जीएमओ/एलएमओ के सीमा पार आवागमन के दौरान जैव सुरक्षा।
 रामसर कन्वेशन → आर्द्धभूमि का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग।
 क्योटो प्रोटोकॉल → विकसित देशों के लिए उत्सर्जन में कमी के बाधकारी लक्ष्य।

50. निम्नलिखित का मिलान करें - भारतीय इतिहास: आंदोलन और उनके नेता -

आंदोलन	नेता
(a) स्वाभिमान आंदोलन	1 - सरदार वल्लभभाई पटेल

"व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है !
 वह जो सोचता है, वही बन जाता है !!

(b) चंपारण सत्याग्रह	2 - महात्मा गांधी
(c) तेभागा आंदोलन	3 - ई. वी. रामासामी (पेरियार)
(d) बारदोली सत्याग्रह	4 - किसान सभा/बंगाल कम्युनिस्ट नेता

विकल्पः

- (A) a-3, b-2, c-4, d-1
 (B) a-1, b-3, c-2, d-4
 (C) a-2, b-1, c-4, d-3
 (D) a-4, b-3, c-1, d-2

उत्तर:

व्याख्या: आत्म-सम्मान आंदोलन → जाति-विरोधी सामाजिक सुधार के लिए ई.वी. रामासामी (पेरियार)।
 चंपारण सत्याग्रह → बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए गांधीजी का पहला सत्याग्रह (1917)।
 तेभागा आंदोलन → काश्तकारों के अधिकारों के लिए बंगाल के कम्युनिस्टों/किसान सभा द्वारा नेतृत्व किया गया।

"सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है !
 आप जो कर रहे हैं, उससे अगर आप प्यार करते हैं, तो आप ज़रूर सफल होंगे !!"

WORLD ORGAN DONATION DAY



13 August

Motto

- This day strives to motivate people to donate their healthy and precious organs after death to save lives.
- Donating an organ is like gifting life to someone because one organ donor can save up to eight lives.

Facts Behind

- A donor can initiate to donate organs like heart, liver, intestine, kidneys, lungs and pancreas after his or her death.
- In the case of natural death tissues of cornea, heart valves, bone and skin can be donated whereas other vital organs like heart, liver, intestines, kidneys, lungs, and pancreas can only be donated in the case of brain death.
- After organ failure, vital organs like heart, liver, intestines, kidneys, lungs and pancreas can be transplanted into the patient to help the recipient lead a normal life.
- Anyone can be an organ donor irrespective of age, caste, religion, community etc.

INDEPENDENCE DAY IN INDIA



15 August

Importance

To mark the end of British rule in 1947 and the establishment of a free and independent Indian nation.

Interesting Facts behind

- India is known as Bharat Ganarajya in Sanskrit.
- Our country got its name 'India' from the River Indus.
- India had no national anthem when it became an independent country.
- Hindi was declared as the official language of India on 14th September, 1949.
- The Governor General was the only and the most authoritative person in India at the time of independence.
- India became independent on July 18, 1947, Lord Mountbatten declared 15th August as the date of Independence because this date observed the second anniversary of the surrendering of Japan to the Allied Forces during World War II.
- India shares its Independence Day with five more countries on August 15, but with different years.
- The countries are Bahrain, North Korea, South Korea, Congo, and Liechtenstein.

क्रिकेट बाइट्स

- लेफ्टिनेंट जनरल पुष्टेंद्र सिंह अगले उप-सेना प्रमुख का पदभार संभालेंगे
- कमोडोर वर्गास मैथू ने केरल के नौसेना प्रभारी अधिकारी का पदभार संभाला
- एजीएमयूटी कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी एसबीके सिंह ने दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है।
- अनुभवी वैज्ञानिक और कंपोजिट विशेषज्ञ डॉ. ए. राजराजन को 1 अगस्त, 2025 से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी), तिरुवनंतपुरम का नया निदेशक नियुक्त किया गया है।
- वरिष्ठ अभिनेता केपीएसी राजेंद्रन का 74 वर्ष की आयु में निधन
- प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लेखक मेघनाद देसाई का 85 वर्ष की आयु में निधन
- दो बार की ओलंपिक चैम्पियन लॉरा डाहलमीयर की पाकिस्तान में पर्वतारोहण दुर्घटना में मर्यादा
- बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रमुख प्रावधान 1 अगस्त से लागू
- 71वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 2023 ने भारतीय सिनेमा की विविधता और समृद्धि को प्रदर्शित किया। शाहरुख खान ने अपना पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और 12वें फेल को सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का खिताब मिला।
- डॉ. मयंक शर्मा ने वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएँ) का पदभार ग्रहण किया।
- वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन, एवीएसएम, एनएम, ने 1 अगस्त, 2025 को नौसेना स्टाफ के 47वें उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला।
- वाइस एडमिरल मनीष चड्हा ने भारतीय नौसेना अकादमी की कमान संभाली।
- शशि प्रकाश गोयल ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव का पदभार संभाला।
- भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस के साथ स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस हिमगिरी को शामिल किया।
- 1 अगस्त, 2025 को, एआईएफएफ ने खालिद जमील को भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया।
- स्पेसएक्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा के क्रू-11 मिशन का प्रक्षेपण किया।
- मलयालम अभिनेता और मिमिक्री कलाकार कलाभवन नवस का 51 वर्ष की आयु में निधन।
- भारत और मोरक्को ने एक पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- आरबीआई ने एनआईसीबीएल के सारस्वत सहकारी बैंक में विलय को मंजूरी दी
- मछली उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर, चीन शीर्ष पर
- सरकार ने ट्रॉक ड्राइवरों के लिए 'अपना घर' विश्राम सुविधा शुरू की
- भारत को स्पेन से अंतिम एयरबस सी-295 विमान प्राप्त हुआ
- लैंडो नॉरिस ने पियास्ती के साथ रोमांचक मुकाबले के बाद हंगेरियन ग्रां प्री जीता
- मैग्नस कार्लसन ने पहला शतरंज ईस्पोर्ट्स विश्व कप जीता
- इसरो अमेरिकी नौसेना के साथ ब्लूबर्ड उपग्रह प्रक्षेपण की तैयारी कर रहा है। सहयोग
- आईडीबीआई के अध्यक्ष और सत्यम के पुनरुद्धारकर्ता टी एन मनोहरन का निधन
- भारतीय सेना ने नेक्स्टजेन टैंक ट्रांसपोर्टर ट्रैलरों के लिए एक्सिसके इस एयरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ 223 करोड़ रुपये का सौदा किया
- वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने नौसेना उप प्रमुख का पदभार संभाला
- लेफ्टिनेंट जनरल पुष्टेंद्र सिंह ने उप सेना प्रमुख का पदभार संभाला
- वेदिका भंसाली ने पाइनहर्स्ट में यूएस किड्स गोल्फ विश्व खिताब जीता
- अब्दुल्ला अबूबकर ने कोसानोव मेमोरियल 2025 में ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीता
- फिच ने वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.3% किया
- सावलकोट जलविद्युत परियोजना: भारत ने जम्मू-कश्मीर के सबसे बड़े जलविद्युत संयंत्र का पुनरुद्धार किया
- टाटा मोटर्स के पीबी बालाजी जगुआर लैंड रोवर के नए सीईओ नियुक्त
- भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं ने SIMBEX 2025 का सफलतापूर्वक समापन किया
- फीफा और एआईएफएफ ने इस शहर में लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा प्रतिभा अकादमी शुरू की
- झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिशू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में निधन
- अर्जेंटीना ने 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप के दोनों खिताब जीते
- सेना और आईआईटी मद्रास ने रक्षा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 'अग्निशोध' कार्यक्रम शुरू किया
- प्रत्यय अमृत बिहार के अगले मुख्य सचिव नियुक्त
- विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा ने मर्चेंट शिपिंग विधेयक पारित किया
- खीर गंगा नदी में बादल फटने से उत्तरकाशी में अचानक बाढ़ आ गई
- अभिनेता केली मैक का 33 वर्ष की आयु में ग्लियोमा से निधन
- भारत और रूस ने औद्योगिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

- संसद ने समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तटीय नौवहन विधेयक पारित किया
- दिल्ली विधानसभा भारत की पहली पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा बनी
- पंजाब समावेशी न्याय के लिए सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को नियुक्त करेगा
- मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 107वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ
- लोकसभा ने 2025 के लिए मणिपुर जीएसटी और विनियोग विधेयक पारित किया
- म्यामार के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू म्यिंट स्वे का 74 वर्ष की आयु में निधन
- भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी 'रुद्रस्त' का ट्रायल रन किया
- अज़रबैजान और आर्मेनिया ने व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए
- भारत की अन्न रानी ने अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मनियाक स्मारक में स्वर्ण पदक जीता
- अरुणाचल के पर्वतारोही कबक यानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की
- 'भारत' टैक्सी: सहकारी समितियों ने ओला और उबर को टक्कर देने के लिए ₹300 करोड़ का राइड-हेलिंग प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया
- प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक M.S. भोजन और शांति के लिए स्वामीनाथन पुरस्कार, नाइजीरियाई वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया
- प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन का उद्घाटन किया
- अपोलो 13 के कमांडर जिम लवेल, जिन्होंने सुरक्षित वापसी का मार्गदर्शन किया, का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- सिक्किम के मुख्यमंत्री ने स्थानीय महिलाओं के नेतृत्व वाले न्याय के लिए 'नारी अदालत' का शुभारंभ किया।
- पंजाब ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए 'बाज अख' एंटी-ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया।
- भारत एआई और एनसीजी ने कैंसर देखभाल में एआई के लिए कैच अनुदान शुरू किया
- लोकसभा ने खेल प्रशासन और डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक पारित किया
- महाराष्ट्र ने विशेष शिक्षा के लिए 'दिशा अभियान' लागू किया
- भारत की अंडर-20 महिला टीम ने 20 साल बाद एफसी एशियन कप 2026 के लिए कालीफाई किया
- जयपुर में भारत का पहला ड्रोन-एआई-संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग।
- डेविड वार्नर ने टी20 क्रिकेट में विराट कोहली को पीछे छोड़ा
- भारत ने एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 27 पदक जीते
- एक्सिस बैंक ने डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए 'लॉक एफडी' सुविधा शुरू की
- ज़ोमैटो ने शाहरुख खान को ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया
- केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दवा सुरक्षा के लिए SHRESTH पहल की शुरुआत की
- UIDAI और ISI ने आधार सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए 5 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए
- शुभमन गिल ने जुलाई 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ़ द मॉन्ट का पुरस्कार जीता
- झारखंड ने जूनियर महिला हॉकी का खिताब बरकरार रखा, 2025 की सभी श्रेणियों में जीत हासिल की
- SC ने पूर्व न्यायाधीश नागेश्वर राव को BCA का लोकपाल नियुक्त किया
- कैबिनेट ने ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में ₹4,600 करोड़ की सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी
- भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025: भारत के समुद्री भविष्य का आधुनिकीकरण, लोकसभा द्वारा पारित
- भारत ने मानवीय सहायता के रूप में फिजी को 5 टन लोबिया के बीज भेजे
- कैबिनेट ने ₹8,146 को मंजूरी दी अरुणाचल प्रदेश में करोड़ टाटा-II जलविद्युत परियोजना
- ऑस्ट्रेलिया सिंतंबर में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा
- नेपाल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 97 हिमालयी चोटियों पर मुफ़्त चढ़ाई की पेशकश कर रहा है
- भारत ने सहकारी नियर्यात को बढ़ावा देने के लिए जाम्बिया के साथ व्यापार सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12 स्वतंत्रता दिवस भाषणों के साथ इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा
- कारगिल के खुबानी का सऊदी अरब में पदार्पण: भारत के कृषि नियर्यात और ओडीओपी पहल के लिए एक मील का पथर
- प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी तकनीक से प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए 'मिशन सुदर्शन चक्र' का शुभारंभ किया
- प्रधानमंत्री मोदी ने 3.5 करोड़ नौकरियों के सृजन के लिए ₹1 लाख करोड़ की प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना का शुभारंभ किया
- श्रीनगर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 के शुर्भंकर के रूप में हिमालयन किंगफिशर का अनावरण किया गया
- नेल्को और यूटेलसैट ने वनवेब लियो सैटेलाइट सेवाओं को लॉन्च करने के लिए साझेदारी की
- नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना को गति दी
- भारत ने 100 गीगावाट सौर पीवी निर्माण का मील का पथर हासिल किया ALMM
- बढ़ते सरकारी खर्च के बीच अमेरिकी राष्ट्रीय ऋण रिकॉर्ड 37 ट्रिलियन डॉलर पर पहुँच गया
- सार्वजनिक आक्रोश के बाद ICICI बैंक ने न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता कम कर दी

- राजीव प्रताप रूडी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के CCI महासचिव का पद बरकरार रखा
- रणनीतिक नेतृत्व में बदलाव के बीच रवि नारायणन को SMFG इंडिया क्रेडिट का CEO नियुक्त किया गया
- भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए आधिकारिक तौर पर बोली लगाई: IOA की मंजूरी की पुष्टि
- ओलंपिक हॉकी पदक विजेता और खेल प्रशासक वेस पेस का 80 वर्ष की आयु में निधन
- पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बॉब सिम्पसन का 89 वर्ष की आयु में निधन।
- रूस 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा-टी मिशन भेजने की योजना बना रहा है।
- अजय कुमार भल्ला को नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला।
- तान्या हेमंत ने साइपन इंटरनेशनल 2025 महिला एकल खिताब जीता।
- देविका सिहांग ने मलेशिया 2025 में पहला अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज खिताब जीता।
- श्रीलंका-भारत नौसैनिक अभ्यास SLINEX-25 का समुद्री चरण कोलंबो में शुरू हुआ।
- वीनस विलियम्स को 45 वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला।
- विसेंट कीमर ने कांटबॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज खिताब जीता।
- नागालैंड के राज्यपाल और पूर्व तमिलनाडु भाजपा प्रमुख ला गणेशन का निधन। 80
- पुतिन-ट्रम्प अलास्का शिखर सम्मेलन यूक्रेन शांति समझौते के बिना संपन्न हुआ
- Microsoft टॉपब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची में शीर्ष पर; NVIDIA और Apple दूसरे स्थान पर
- रियल मैड्रिड को 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब चुना गया
- एसबीआई ने अग्रिमीरों के लिए बिना ज़मानत के ₹4 लाख का ऋण शुरू किया; ₹25,000 से अधिक के ऑनलाइन हस्तांतरण के लिए IMPS शुल्क संशोधित
- मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता, थाईलैंड में 74वें मिस यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी
- असम राइफल्स ने रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए IIIT मणिपुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
- कार्लोस अल्काराज़ ने सिनसिनाटी ओपन का पहला खिताब जीता, सिनर के फाइनल में रिटायर होने के बाद
- इगा स्विएटेक ने सिनसिनाटी ओपन जीता, यूएस ओपन से पहले चेतावनी दी
- पूर्व ट्रिटर सीईओ पराग अग्रवाल ने मशीनों के लिए वेब बनाने हेतु AI स्टार्टअप 'पैरेलल' लॉन्च किया
- अनुभवी अभिनेता अच्युत पोतदार का 91 वर्ष की आयु में निधन: भारतीय सिनेमा में उनकी उल्लेखनीय विरासत को श्रद्धांजलि
- संसद ने खान एवं खनिज संशोधन विधेयक, 2025 पारित किया
- लोकसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक, 2025 पारित किया
- बजट फिल्मों के लिए मशहूर मलयालम निर्देशक निसार का 2025 में निधन
- कपिल बैंसला ने एशियाई निशानेबाजी चैपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता
- ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने AUKUS के तहत 50 वर्षीय जिलौना संधि पर हस्ताक्षर किए
- बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्य स्वच्छता कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की
- ऑस्कर पियास्ट्री ने फॉर्मूला-1 बेल्जियम ग्रां प्री 2025 जीता
- ईरान ने रूसी सोयुज रॉकेट से नाहिद-2 दूरसंचार उपग्रह प्रक्षेपित किया
- ऑपरेशन महादेव: भारतीय सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले के आतंकवादियों को मार गिराया
- भारत-मालदीव मत्स्य पालन और जलीय कृषि सहयोग 2025 पर समझौता ज्ञापन
- उत्तल कुमार सिंह को संसद टीवी का सीईओ नियुक्त किया गया
- नात्सा ने रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कानूनी सहायता को मजबूत करने हेतु योजना शुरू की
- इंग्लैंड की महिलाओं ने यूरो 2025 जीता: एक ऐतिहासिक जीत इसरो 2026 तक 3 और नैविगेशन नाविक उपग्रह लॉन्च करेगा
- ब्रिटेन की सबसे बड़ी जैज़ गायिका क्लियो लेन का 97 वर्ष की आयु में निधन
- भारत के पहले हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण
- भारत ने मालदीव को ₹4,850 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की - द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना
- इसरो प्रमुख डॉ. वी. नारायणन को जीपी बिड़ला स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया
- गीतांजलि श्री ने 'कभी यहाँ हाथी रहते थे' के लिए पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जीता
- प्रोफेसर उमा कांजीलाल इम्मू की पहली महिला कुलपति नियुक्त
- भारत-सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास 'बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025'
- रिले पॉवेल ने आईबीएसएफ विश्व 6-रेड स्कूकर चैम्पियनशिप 2025 में पंकज आडवाणी को हराया
- मैंगलोर की 20 वर्षीय छात्रा रेमोना एवेट परेरा ने 170 घंटे के भरतनाट्यम प्रदर्शन के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया
- भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज मध्य प्रदेश के जबलपुर में खुलेगा
- यूरोपीय संघ और अमेरिका ने 15% टैरिफ के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए

- नपने झारने पर महाराष्ट्र का पहला कांच का पुल खुला
- दिव्या देशमुख तीसरी महिला विश्व कप चैंपियन बनों
- क्योटो प्रोटोकॉल के वास्तुकार विजय शर्मा का निधन
- रक्षा मंत्रालय और टीआईडीसीओ ने ₹400 करोड़ की परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
- RBI ने AIF योजना में किसी बैंक के निवेश की सीमा 10 प्रतिशत तय की
- भारत, UAE ने समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए
- भारत-अमेरिका का पहला अंतरिक्ष सहयोग NISAR स्टीक कक्ष में स्थापित
- अप्रिवीरों को कॉर्बट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में शामिल किया जाएगा
- असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चरागाह पक्षी गणना
- भारत व्यापार समझौते के बीच अमेरिका पाकिस्तान के तेल भंडार का अन्वेषण करेगा
- अनंत अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक नियुक्त
- वाराणसी रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर
- आईआईटी मद्रास ने भारत के पहले सिलिकॉन फोटोनिक्स कांटम रैंडम नंबर जेनरेटर (QRNG) का लाइसेंस प्राप्त किया
- ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए असम राइफल्स ने आईआईटी मणिपुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार संचालन की मजबूती, सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) के साथ एक पाँच वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की जब एकानॉट कमांडर जतिंदर पाल सिंह (सेवानिवृत्त) और राजू रमेश ने अटलांटिक महासागर में क्रमशः 4,025 मीटर और 5,002 मीटर की गहराई तक गोता लगाया।
- इसरो एक नया भारी-भरकम रॉकेट विकसित कर रहा है जो 40 मंजिला इमारत जितना ऊँचा होगा।
- केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएबी) में भारत के पहले 'पशु स्टेम सेल बायोबैंक' का उद्घाटन किया।
- डीआरडीओ द्वारा प्रलय मिसाइल के लगातार दो सफल उड़ान परीक्षण
- फिल्म '3 इडियट्स' में सख्त प्रोफेसर की भूमिका के लिए मशहूर दिग्गज अभिनेता अच्युत पोतदार का 91 वर्ष की आयु में निधन।
- मराठी अभिनेत्री ज्योति चंदेकर का 68 वर्ष की आयु में निधन
- प्रमुख लेबनानी संगीतकार जियाद रहबानी का 69 वर्ष की आयु में निधन
- ब्रिटेन के सबसे सफल जैज गायक क्लियो लेन का 97 वर्ष की आयु में निधन
- व्यंय को संगीतमय बनाने वाले प्रतिभाशाली टॉम लेहरर का 97 वर्ष की आयु में निधन
- विश्व एथलेटिक्स ने महिला वर्ग के लिए नए पात्रता नियम लागू किए हैं
- भारत सरकार ने सीआरपीएफ और आईटीबीपी के पूर्व महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) नियुक्त किया है।

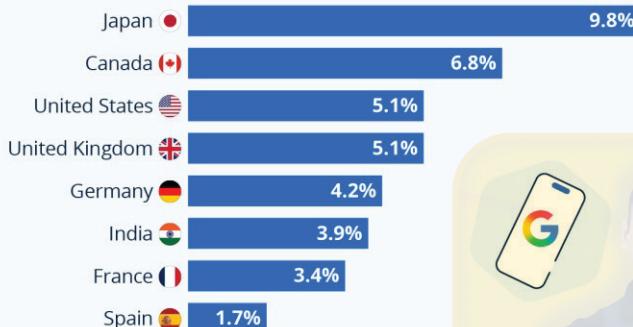
"किसी भी काम के प्रति सकरात्मक सोच रखनी चाहिए !
क्योंकि नकरात्मक सोच ही हमारी असफलता का कारण
बनती है !!

"कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है !
लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं !!

इन्फोग्राफिक्स

Google Remains a Fringe Player in the Smartphone Market

Share of respondents who used a Google phone as their primary smartphone in 2024/25



1,700-8,600 smartphone users (18-64 y/o) per country surveyed Jul. 2024-Jun. 2025
Source: Statista Consumer Insights



KUMAR EDUTAINMENT

The World's Top Gaming Markets

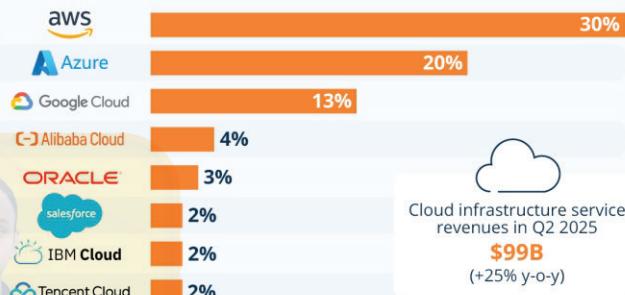
Estimated revenue of the video games market*, by country (in billion U.S. dollars)



* Covers the creation, publishing, distribution and monetization of console, PC, mobile and online games, plus related hardware and accessories. Estimates as of May, 2025.
Source: Statista Market Insights

The Big Three Stay Ahead in Ever-Growing Cloud Market

Worldwide market share of leading cloud infrastructure service providers in Q2 2025*



Cloud infrastructure service revenues in Q2 2025
\$99B
(+25% y-o-y)

* Includes platform as a service (PaaS) and infrastructure as a service (IaaS) as well as hosted private cloud services

Source: Synergy Research Group

The Chinese-Indian Trade Relationship

Trade in selected goods between China and India in 2023*



% change since 2019

Chinese exports to India

Electronics and machinery	\$70.3B	+104%
Chemical products	\$20.3B	+56%
Metals	\$8.4B	+42%
Plastics and rubber	\$6.4B	+83%
Textiles	\$5.0B	+35%

Indian exports to China

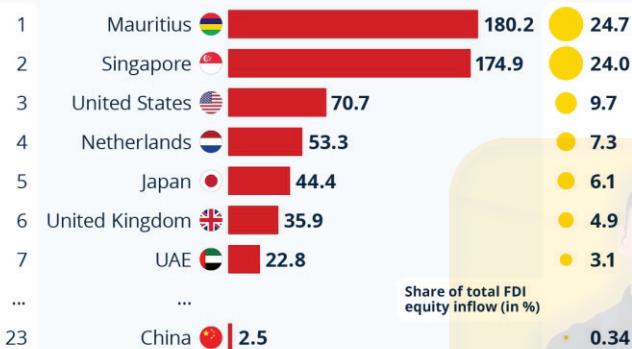
Minerals and oil	\$5.8B	+9%
Chemical products	\$2.1B	-43%
Electronics and machinery	\$1.9B	+6%
Metals	\$1.3B	+8%
Fish, Crustaceans, Molluscs	\$1.2B	-8%



Source: UN Comtrade/BACI International via OEC/MIT

China Has Not Been a Major Source of FDI into India

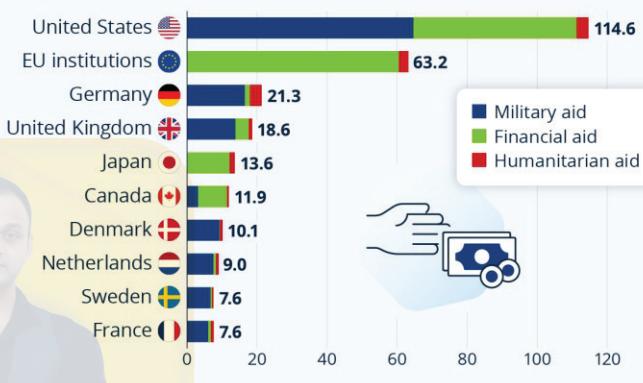
FDI* equity inflows to India from Apr. 2000 to Mar. 2025, by major investors (in billion U.S. dollars)



* Foreign direct investment
Source: High Commission of India

U.S. Has Given Ukraine the Most Aid to Date

Countries allocating the most aid to Ukraine from Jan. 24, 2022 to Jun. 30, 2025 (in billion euros)



Source: IfW Kiel, Ukraine Support Tracker

KUMAR
EDUTAINMENT

India's Growing Trade Deficit With China

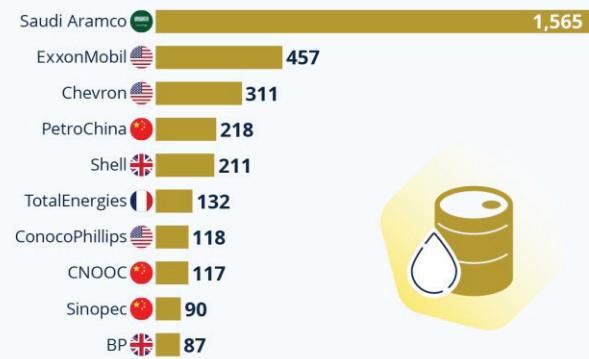
India's annual trade deficit* with China (in billion U.S. dollars)



* exports minus imports
Source: India's Department of Commerce

The Biggest Oil and Gas Companies in the World

Market capitalization of major oil companies in 2025 (in billion U.S. dollars)



As of Aug. 6, 2025
Source: companiesmarketcap.com

The World's Most (And Least) Powerful Passports

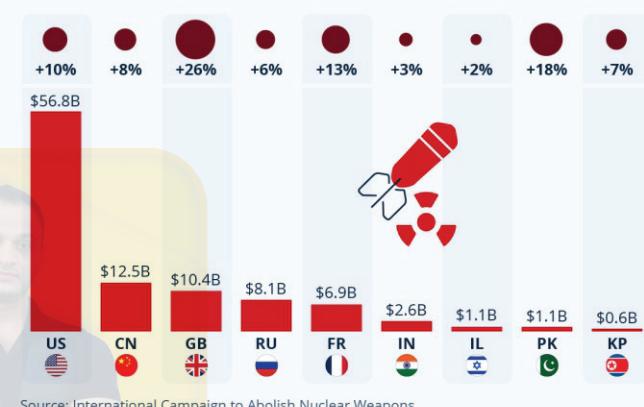
Passports ranked by the number of destinations their holders can access without a prior visa (as of July 2025)



Based on 199 different passports and 227 travel destinations
Source: Henley Passport Index

Nuclear Weapons Spending on the Rise

Annual total spending on nuclear weapons in 2024 and change from previous year



Source: International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

KUMAR EDUTAINMENT

The Countries That Will Sell You a Passport

Countries with citizenship-by-investment schemes (as of August 2025)

\$130,000 - \$250,000

- Antigua & Barbuda
- Dominica
- Egypt
- North Macedonia
- St. Kitts & Nevis
- St. Lucia
- Grenada
- Nauru

\$400,000 - \$750,000

- Jordan
- Malta
- Turkey

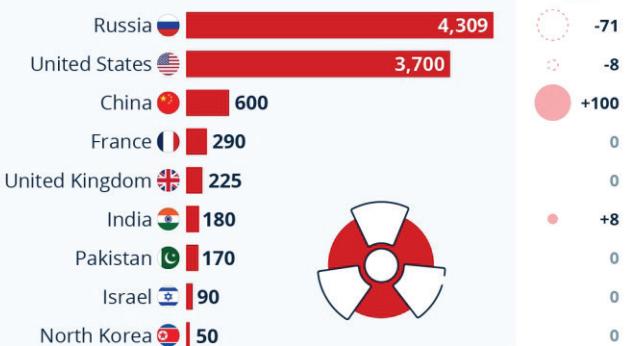
Substantial contribution

- Austria

Malta: Mandatory residence period with rental/purchased property minimum value requirement.
Turkey alternative: Create 50 jobs
Source: Henley & Partners

The Countries Armed With Nuclear Weapons

Estimated nuclear warhead inventories (as of Jan. 2025)*

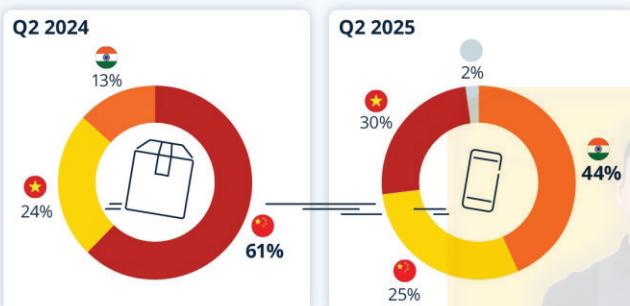


* Deployed warheads as well as warheads in central storage. Excludes retired warheads
Source: SIPRI

India Is Now the Top Supplier of Smartphones to the U.S.

Share of smartphone shipments to the United States in Q2 2024 and Q2 2025, by manufacturing country

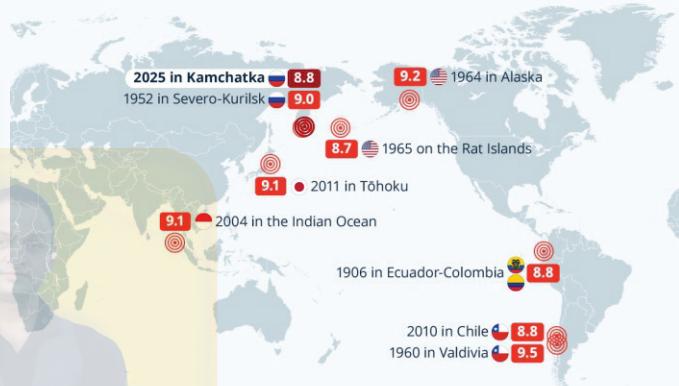
● China ● Vietnam ● India ● Others



Source: Canalys

The Most Powerful Quakes Are in the Ring of Fire

Most powerful earthquakes measured worldwide since 1900, according to the Moment Magnitude scale (Mw)

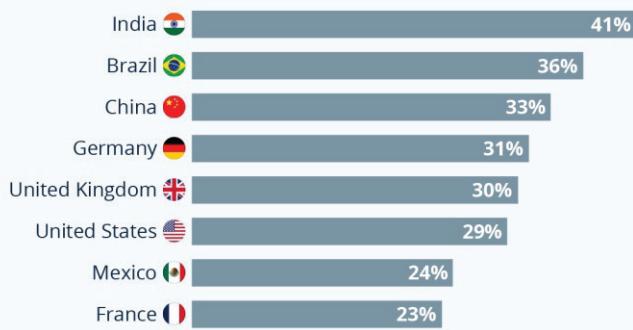


Source: United States Geological Survey (USGS)

**KUMAR
EDUTAINMENT**

Functional Phone = Electronic Waste?

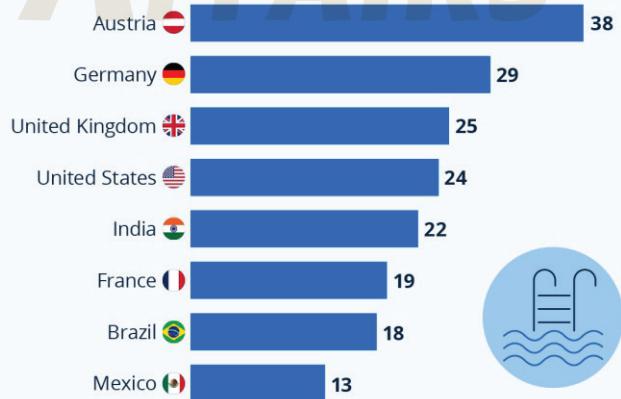
Share of respondents who buy new electronics even when their old model still works



1,800-9,300 respondents (18-64 y/o) surveyed per country Jul. 2024-Jun. 2025
Source: Statista Consumer Insights

Which Countries Like to Swim?

Share of respondents in a selection of countries who say they swim/diver at least occasionally (in percent)



5,000-23,000 respondents (18-64 y/o) per country surveyed Jul. 2024-Jun. 2025
Source: Statista Consumer Insights





Kumar Edutainment Presents

CURRENT AFFAIRS MAGAZINE

- 7 Jawahar Nagar, Khandari, Agra, Uttar Pradesh
- 8882388888
- Kumariasacademy@gmail.com
- kumarsias.com
- Kumar Edutainment
- your_kumar_sir



Kumar Edutainment